# बरी हुए केजरीवाल

दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। इससे देश की ख्यात जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ ही, ईडी को भी झटका लगा है, तो दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी में स्वाभाविक ही नए उत्साह का संचार हो गया है। यह तथ्य है, आबकारी नीति से जुड़े इस कथित घोटाले से सर्वाधिक नुकसान आम आदमी पार्टी का हुआ था, जो तब दिल्ली की सत्ता में थी। वैसे, निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई उच्च न्यायालय में अपील करेगी, पर प्रथम दृष्टया, इस सवाल को बल मिला है कि क्या सीबीआई दिल्ली के कुछ आला नेताओं को बगैर मजबूत अभियोजन के कठघरे में खड़ा कर रही थी? अब सीबीआई भले यह शिकायत करे कि निचली अदालत ने तथ्यों को ठीक से नहीं देखा, पर तथ्यों को अदालत में ठीक से पेश करने की जिम्मेदारी क्या सीबीआई की नहीं थी? केवल किसी मामले को उठा देना, सनसनी बनाकर बड़े से बड़े नेता या मुख्यमंत्री, मंत्री को गिरफ्तार कर लेना कहां तक उचित है? क्या किसी नागरिक या नेता पर शिकंजा कसने से पहले ही किसी जांच एजेंसी को अपराध संबंधी तमाम सुबूत नहीं जुटाने चाहिए?

खैर, यह देखने वाली बात होगी कि अब सीबीआई उच्च न्यायालय में अपील करते हुए कैसे नए सुबूत पेश करती है? सीबीआई ही नहीं, देश की सभी जांच एजेंसियों को गौर करना चाहिए कि हर एजेंसी की एक छवि है, जो बिगड़नी नहीं चाहिए। एजेंसियों को अपनी छवि के साथ ही, आम लोगों की गरिमा, जन-प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध लोगों की छवि के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। वैसे भी जन-प्रतिनिधियों पर आरोप कम नहीं लगते हैं, पर ऐसे आरोप राजनीतिक प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं। यहां यह ध्यान रखने की बात होगी कि राजनीतिक प्रवृत्ति के आरोपों से प्रेरित होकर हमारी एजेंसियों को कदम नहीं उठाने चाहिए। इससे भी बड़ी बात है, एक बार पुख्ता ढंग से सुबूत जुटा लिए, आरोप लगा दिए, गिरफ्तार कर लिया, तो अपराध साबित करके दम लेना चाहिए। इस बहु-चर्चित मामले में अभाव केवल सुबूतों का ही नहीं है, अभियोजन में कई आंतरिक विरोधाभास भी हैं, तभी यह मामला न्यायिक जांच में खरा नहीं उतरा है।

**कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल सहित 23 लोगों को बरी कर दिया गया है, इससे आम आदमी पार्टी को बल मिला है, पर जांच एजेंसियों के लिए चिंता बढ़ गई है।**

निस्संदेह, अदालत के इस फैसले से पूरी आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल की बातों पर लोग गौर कर रहे हैं। उन्होंने भावुक होते हुए कहा है कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं, साबित हो गया है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं। संकेत स्पष्ट है, यहां से आम आदमी पार्टी की राजनीति को नया जीवन मिलेगा। जिन राज्यों में चुनाव आसन्न हैं, वहां पार्टी की सक्रियता बढ़ेगी। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सबसे ज्यादा फायदा उसे वहीं होगा। साल 2027 में वहां विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी अब वहां आक्रामक ढंग से प्रचार कर सकेगी। राजनीति का अपना ढंग होता है, वहां राजनेता लाभ-हानि का गणित बिठाते हैं और इस बार भी जरूर बिठाएंगे। हमारे लिए ज्यादा चिंतन की बात तो यह है कि कानून-व्यवस्था पर आम लोगों के विश्वास को कैसे बनाए रखा जाए? अब समय आ गया है कि देश की तमाम जांच एजेंसियों या उसके अधिकारियों की योग्यता को परखा जाए। अगर कोई भी जांच एजेंसी अभियोजन, जांच और ईमानदार दस्तावेजीकरण में कोताही बरत रही है, तो उसमें यथोचित सुधार की पहल शुरू होनी चाहिए।

# पाकिस्तान-अफगान जंग के मायने

सुशांत सरीन | सीनियर फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन

**दोनों देशों के बीच हालात इतने बिगड़े हैं कि पाकिस्तान ने खुली जंग का एलान कर दिया है। अब आगे जंग में स्थिति जो बने, पाकिस्तान के सामने ही चुनौतियां ज्यादा रहेंगी।**

पाकिस्तान ने डुरंड सीमा पर 'खुली जंग' का एलान करके बेवजह मुसीबत मोल ले ली है। इस्लामाबाद का दावा है कि बीते 48 घंटों में उसके हवाई हमलों से अफगान-तालिबान के 133 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि 200 से अधिक घायल हुए हैं, उधर काबुल ने भी बयान जारी करके कहा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। इस बदलते घटनाक्रम पर तमाम देशों की नजर है। रूस सहित कई मुल्कों ने तुरंत संघर्ष-विराम की अपील भी की है।

आखिरकार अफगानिस्तान-पाकिस्तान के संबंध इतने खराब कैसे हो गए? यह सही है कि बीते दो दिनों में सीमा पर काफी कुछ अप्रत्याशित घटा है, लेकिन दोनों देशों में तनातनी तो तभी शुरू हो गई थी, जब 2021 में तालिबान ने काबुल की सत्ता संभाली थी। दरअसल, दुनिया भर में तालिबान की 'तारीफ' कर पाकिस्तान ने तकरीबन दो दशकों तक उस पर 'निवेश' किया था, लेकिन जब तालिबान को बागडोर मिली, इस्लामाबाद का भ्रम टूटने लगा। इसकी शुरुआत हुई तहरीक-ए-तालिबान के करीब 5,000 लड़ाकों की रिहाई से, जो अफगान जेलों में बंद थे। इसके बाद पाकिस्तान में छोटे-बड़े हमले बढ़ गए, जिनको इस्लामाबाद अफगान-तालिबान की कारस्तानी बताता है, जबकि उनके पीछे तहरीक-ए-तालिबान का हाथ था।

अब चूंकि तहरीक-ए-तालिबान (पाकिस्तान के तालिबान) और अफगान-तालिबान में करीबी रिश्ता रहा है, इसलिए इस्लामाबाद ने इन हमलों के जवाब में अफगानिस्तान के भीतर बमबारी शुरू की। इन कार्रवाइयों की एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत को अपने अधीन रखना चाहता था, जबकि अफगानों के बारे में यही कहा जाता है कि 'उनको किराये पर तो लिया जा सकता है, मगर खरीदा नहीं जा सकता'। इससे अफगानिस्तान को अपना पांचवां सूबा बनाने की पाकिस्तान की मंशा भी टूट गई।

यहां मुल्ला अब्दुल सलाम जईफ की किताब *माई लाइफ विद द तालिबान* का जिक्र भी जरूरी है। जईफ 2000-01 के दौरान पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत थे। उन्होंने लिखा है, इस्लाम का गलत इस्तेमाल करने के कारण अफगानों को पाकिस्तान पसंद नहीं। उनके मुताबिक, अरब मुल्कों से इमदाद लेने के लिए पाकिस्तान इस्लाम के राग अलापता है और धर्म का कथित ठेकेदार बना हुआ है। अफगानों को लगता है कि पाकिस्तान ने उनको धोखा दिया है, क्योंकि अपने हित के लिए उसने तालिबान के विरुद्ध अमेरिका से हाथ मिला लिया था। उनको पाकिस्तान की वे यातनाएं भी याद हैं, जब संरक्षण का भरोसा देने के बावजूद उनके लोगों को बंधक बनाया गया व बर्बर कार्रवाई की गई।

बहरहाल, डुरंड रेखा पर फिलहाल 'पारंपरिक जंग' शायद ही होगी, क्योंकि जिस तरह से अक्तूबर 2025 से यहां तनाव बना हुआ है, उसका असर खूब पड़ रहा है। उस समय करीब एक हफ्ते तक संघर्ष चला था, जिस पर तुर्किये और कतर की मध्यस्थता के बाद विराम लग सका था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने सीमा बंद कर दी। इससे पाकिस्तान का व्यापार तो प्रभावित हुआ ही, क्योंकि अफगानिस्तान उसके लिए एक बड़ा बाजार रहा है, लेकिन काबुल को कहीं ज्यादा समस्याएं हुईं। इससे वहां दवाई जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति भी बाधित हो गई थी, जिसकी पूर्ति बाद में भारत ने 'मानवीय मदद' के रूप में की।

दबाव बनाने का पाकिस्तान का यह दांव यहीं तक नहीं रुका। उसने अपने यहां दो-ढाई दशकों से रह रहे अफगान शरणार्थियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया और उनकी संपत्ति लूट ली। मूलतः पंजाबी मुसलमानों ने ऐसा किया और उनको अफगानिस्तान वापस भेजना शुरू किया। इन सबसे अफगानिस्तान में पाकिस्तान को लेकर जबर्दस्त नाराजगी फैली। रही-सही कसर 'आतंकवाद विरोधी अभियान' के नाम पर शुरू की गई हालिया कार्रवाइयों ने पूरी कर दी। हालांकि, ये हमले पाकिस्तानी हुकूमत ने 'मजबूरीवश' किए हैं, क्योंकि बीते दो हफ्तों में जब कुछ बड़े हमले पाकिस्तान के भीतर हुए, तो वहां की हुकूमत पर 'कुछ करने' का दबाव बढ़ गया था। मौजूदा हुकूमत अवाम में लोकप्रिय नहीं है। लिहाजा, फौज की शह पर अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में बमबारी की गई, जिनमें तालिबानी लड़ाकों से कहीं ज्यादा आम अफगान की मौत हुई। इससे अफगानिस्तान की हुकूमत को भी कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ा है।

यह संघर्ष आखिर कहां रुकेगा? तीन स्थिति बनती दिख रही है। पहली, पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले होते रहेंगे और ये तब रुकेंगे, जब अफगानिस्तान के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक 'नो मेन्स लैंड' बनाने की अपनी योजना इस्लामाबाद पूरी कर लेगा। दूसरी, दोनों तरफ से ठहर-ठहरकर संघर्ष होते रहेंगे और बीच-बचाव से मामला शांत किया जाता रहेगा। तीसरी स्थिति कहीं अधिक गंभीर है। संभव है कि अफगान हुकूमत अपने यहां के तालिबान को खुली कार्रवाई करने की छूट दे दे। चूंकि काबुल की सरकार पाकिस्तान से खार खाए हुए है, इसलिए स्थिति कोई भी बनेगी, चुनौती इस्लामाबाद के सामने ही अधिक रहेगी।

इससे पाकिस्तान की दुविधा कहीं अधिक बढ़ जाती है। वह तालिबान को सह भी नहीं सकता और उसे रोक भी नहीं सकता। अमेरिका इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसने ढाई-तीन लाख अफगानों को मारा, फिर भी उसे अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ी। लिहाजा, यह पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान द्वारा उड़ता तीर लेने जैसा है। अफगानिस्तान के पक्ष में उसका यह आश्वासन भी है, जिसमें उसने कहा था कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देगा। उसने कई देशों से यह वायदा किया है और अब तक वह इस पर खरा उतरा है। ऐसे में, पाकिस्तान अपनी करनी का फल ही भोग रहा है। आतंकवाद की जिस आग को उसने भड़काया, आज वही उसको लील रही है।

रही बात भारत की, तो हमें शायद ही कोई खतरा है। भारत का रुख स्पष्ट है। हम पाकिस्तान की कार्रवाई को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन मानते हैं। सीमा पार कार्रवाइयों से तनाव ही बढ़ेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

**नई दिल्ली के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध-प्रदर्शन का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। एक पक्ष यह मानता है कि ऐसे प्रदर्शन करना ठीक नहीं है, तो दूसरा पक्ष ऐसे प्रदर्शन के बचाव में लगा हुआ है।**

# शर्मनाक ढंग से सियासी प्रदर्शन करना ठीक नहीं

शहजाद पूनावाला | राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

पिछले कुछ सालों में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने भाजपा-विरोध को इस हद तक बढ़ा दिया है कि वह देश-विरोध में बदल गया है। हर बार जब भारत जीतता है, कांग्रेस प्रधानमंत्री व भाजपा पर निशाना साधने के चक्कर में भारत पर ही हमले कर बैठती है।

जब 'ऑपरेशन सिंदूर' में हमने आतंकवाद के खिलाफ अभूतपूर्व जवाबी रुख अपनाया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी शिविरों व एयर बेस को नेस्तनाबूद किया, तब राहुल गांधी और उनके साथियों ने इसे 'समर्पण' बताया। हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई। कोविड महामारी के समय जब हमने दो 'आत्मनिर्भर वैक्सीन' बनाईं और भारतीयों को मुफ्त में टीके लगाए, तब उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों पर हमला बोला। जब दुनिया भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बता रही थी और हमारी जीडीपी 8.2 फीसदी पर पहुंच गई, तब राहुल गांधी की राय आई कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है।

एआई सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी का 'शर्टलेस' विरोध भी इससे अलग नहीं था। भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन था। इसमें 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष शामिल हुए। साथ ही, 118 देशों के 59 मंत्री स्तर के प्रतिनिधि आए। टेक जगत के 100 से ज्यादा सीईओ व दिग्गज हस्तियां आईं। वैश्विक नेताओं और सीईओ ने सम्मेलन की खूब तारीफ की और हमारी एआई महत्वाकांक्षाओं पर 200 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। यह कार्यक्रम कोई भाजपा या प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि पूरे देश का 'शोकेस' था। अगर कांग्रेस में राजनीतिक परिपक्वता होती, तो उसके नेता अपने युवाओं की एआई क्षमता के पीछे एकजुट होते, लेकिन उन्होंने एक शर्मनाक काम कर दिया।

भारत के इस सफल वैश्विक आयोजन से परेशान होकर और भारत-विरोधी ताकतों के इशारे पर युवा कांग्रेस के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने 'ब्रांड भारत' की छवि खराब करने की कोशिश की। आधे नंगे होकर और अपने सीने पर प्रधानमंत्री-विरोधी नारे लिखकर उन्होंने प्रदर्शन किया। यह शर्मनाक कृत्य था। इससे भी शर्मनाक था कि राहुल गांधी ने इस कृत्य के दोषियों का बचाव करते हुए उन्हें 'बब्बर शेर' कहा और कांग्रेस ने गांधी व भगत सिंह से उनकी तुलना की। 'असहमति का लोकतांत्रिक अधिकार' बताकर उन्होंने इसका बचाव किया, लेकिन न तो अदालत और न ही उनके सहयोगी इससे सहमत हुए।

कांग्रेस का दोहरापन असीम है। यूपीए के शासनकाल के समय उसके नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले युवाओं पर खूब लाठीचार्ज किए, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध कर रहे करीब 9,000 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए थे। आज वे लोग हमें लोकतंत्र का ज्ञान दे रहे, जिन्होंने आपातकाल को भी सही बताया था। एआई सम्मेलन के समय ही कर्नाटक के धारवाड़ में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जब बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया, तो उन पर लाठियां चलीं, मगर कांग्रेस उन लोगों की गिरफ्तारी पर शोर मचा रही, जिनके कृत्य को कोर्ट ने 'राष्ट्रीय शर्म' कहा है।

**आमने-सामने**

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साल 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के विरोध-प्रदर्शन से इसकी गलत तुलना करने की कोशिश की है। वे विरोध-प्रदर्शन खेल के एक हफ्ते बाद हुए थे, न कि विदेशी खिलाड़ियों के सामने या खेल स्थल पर। एआई सम्मेलन में शर्टलेस विरोध से उसकी तुलना बेईमानी है। सच यह है कि कांग्रेस के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि 'एनार्की इन इंडिया' है। सम्मेलन में युवा कांग्रेसियों के कृत्य नीतिगत आलोचना से नहीं, बदले की भावना से प्रेरित थे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

# विरोध करने के अधिकार को देशद्रोह न माना जाए

आलोक शर्मा | राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस

जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है और कोई भी उसकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसे खामोश करने की कोशिश की जाती है। कोई किसी विधेयक के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है; कोई मुस्लिम आवाज उठाता है, तो उसे पाकिस्तान जाने की नसीहत दी जाने लगती है; कोई पढ़ा-लिखा किसी मुद्दे पर विरोध जताता है, तो वह 'अर्बन नक्सल' हो जाता है; युवा रोजगार मांगते हैं, तो पुलिस की लाठियों से पीटे जाते हैं। आज जो हालात बने हैं, वे बहुत सारे मुद्दों के इकट्ठे होने से बने हैं।

देश के युवा मोदीजी में अपना भविष्य देख रहे थे। अब इन नौजवानों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। बेरोजगारी का आलम यह है कि आईआईटी जैसे श्रेष्ठतम संस्थानों से 'प्लेसमेंट' के बारे में बहुत सकारात्मक संकेत नहीं आ रहे हैं। मुक्त व्यापार (फ्री ट्रेड) का झुनझुना बजाया जा रहा है। पहले न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड किया गया। न्यूजीलैंड की पूरी आबादी बमुश्किल 55 लाख है। इससे हमें तो फायदा नहीं होगा, न्यूजीलैंड को होगा। उसके डेयरी उत्पाद यहां आएंगे और हम डेयरी प्रोडक्ट के मामले में मारे जाएंगे। इसके बाद यूरोपीय संघ से समझौता किया गया। उनके लिए सारे रास्ते खोल दिए गए। जिस दिन एफटीए हुआ, जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा गया, उसी दिन यूरो मजबूत और रुपया कमजोर हो गया।

अमेरिका से ऐसा व्यापार समझौता हुआ कि न वाणिज्य मंत्री को कुछ पता, न विदेश मंत्री को मालूम। विदेश मंत्री से पूछिए, तो वह वाणिज्य मंत्री की बात करते हैं, वाणिज्य मंत्री एनएसए की बात करते हैं, फिर भी आप कहीं धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकते।

हमने प्रतीकात्मक रूप से एक विरोध-प्रदर्शन किया कि आप यह सब नहीं कर सकते। यह यूथ कांग्रेस ने किया। सरकार इतना डर गई कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने, धर-पकड़ करने में जुट गई। उनके खिलाफ ऐसी-ऐसी धाराएं लगाई गई हैं, जैसे आतंकियों को पकड़ लिया गया हो। आज तक पुलवामा किसने किया, इसका पता नहीं लगा है; पहलगाम वालों का क्या हुआ, पता नहीं; दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हो गया, आज तक उसके मृतकों की सूची जारी नहीं की गई, लेकिन कांग्रेस के युवाओं को मार रहे हैं।

यह सरकार व्यापार समझौते में अमेरिका के सामने घुटने टेक रही है, किसानों के हितों को गिरवी रख रही है और यह चाहती है कि कोई उसका विरोध भी नहीं करे। युवा कांग्रेस के साथियों ने प्रतीक के तौर पर 'पीएम इज कंप्रोमाइज्ड' का नारा लगाया और अपना विरोध-प्रदर्शन किया। इसके लिए प्रधानमंत्री ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया, वह बहुत दुखद है। हालत यह है कि सरकार छापेमारी करती घूम रही है कि टीशर्ट कहां छपी? इसके पैसे किसने दिए?

अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल गए थे, वहां उनकी मौजूदगी में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खूब नारे लगे। तो क्या हम यह कहेंगे कि ये नारे हमारे देश के खिलाफ लगे? अगर एआई समिट में हमने अपनी सरकार की नीतियों का विरोध किया, तो यह क्यों माना जाना चाहिए कि ये नारे सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों के खिलाफ लगे?

भारत मंडपम में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। किसी ने कोई लड़ाई-झगड़ा, हिंसक प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि वहां मौजूद भाजपा के कुछ लोगों ने ही हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया। झगड़ा बढ़ सकता था, लेकिन हम गांधीजी में विश्वास रखते हैं, इसलिए वहां कोई जवाबी हमला नहीं हुआ। हमारी सरकार बनने पर या आज भी जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं, अगर भाजपा के लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, तो हम सम्मान करेंगे। कांग्रेस जैसे को तैसा में विश्वास नहीं करती।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

## हिन्दुस्तान | 75 साल पहले 28 फरवरी, 1951

# पाकिस्तान से समझौता

जबकि देश में रूई, पाट और अन्न की कमी के कारण हमारी अर्थ-नीति संकटापन्न है, स्वदेश में आवश्यक मात्रा में ये उपलब्ध नहीं हैं और विदेशों से आ नहीं पा रही हैं, इन चीजों में बचत वाले अपने निकट-पड़ोसी पाकिस्तान से इन्हें प्राप्त करने का मार्ग जो समझौता खोलता हो, उसका हमें स्वागत ही करना चाहिए। सितम्बर 1949 में ब्रिटेन के साथ हमने भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया और पाकिस्तान ने नहीं किया, तभी से दोनों देशों के बीच व्यापार ठप्प हो रहा था। एक ही सिक्का रुपया दोनों देशों में चलता है, अवमूल्यन तक दोनों का मूल्य समान था, राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते समय भारत को शायद खयाल भी नहीं था कि पाकिस्तान भी ऐसा ही नहीं करेगा। अतः जब भारत ने रुपये का अवमूल्यन कर लिया और पाकिस्तान ने नहीं किया तो हमारे सामने एक अजीब स्थिति हो गई। इस आशा से कि पाकिस्तान भी आगे-पीछे ऐसा ही करेगा, नहीं करेगा तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव से उसे ऐसा करना पड़ेगा, भारत इस बात पर आग्रही रहा कि पाकिस्तानी रुपये को भारतीय रुपये से महत्व न मिले; किन्तु कुछ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के बढ़ते स्वतंत्र रुख तथा कुछ पाकिस्तान की कच्चे माल में बहुलता के कारण पाकिस्तान पर अवमूल्यन के लिए दबाव नहीं डाला गया।

इधर कोरियाई युद्ध तथा भावी सामरिक तैयारियों ने जब विश्व में कच्चे माल के संग्रह और सुदूरवर्ती देशों से माल के यातायात की कठिनाई को प्रोत्साहन दिया तो पलड़ा पाकिस्तान के पक्ष में और झुकने लगा तथा भारत को पैतरा बदलने में हिचकिचाने में प्रतिष्ठा के पीछे आत्मघात के सिवा कोई लाभ नजर न आया। यही कारण है कि यथार्थवादी की तरह उसने साहस के साथ पाकिस्तानी रुपये की उस दर को स्वीकार कर लिया जिसे वह कृत्रिम मानता था पर पाकिस्तान, जिस पर अड़ा हुआ था। इसमें ऊपर से पाकिस्तान की जीत और भारत की हार लगते हुए भी इसे भारत की यथार्थवादी राजनीतिज्ञता एवं दूरन्देशी ही मानना चाहिए। 26 फरवरी को घोषित और 27 फरवरी से लागू होने वाला डेढ वर्षीय समझौता दोनों पड़ोसी देशों के बीच खुले व्यापार का प्रथम पग है। इसके फलस्वरूप हम रूई व पाट (पटसन) की अपनी कमी की शीघ्र-पूर्ति की आशा कर सकते हैं।

# इससे महिलाओं की भूमिका सशक्त होगी

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस महान भारतीय वैज्ञानिक सी वी रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को 'रामन प्रभाव' की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एक विशेष थीम पर आधारित होता है। इस वर्ष 2026 की थीम है- 'विज्ञान में महिलाएं: विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति।' यह थीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, योगदान और नेतृत्व को उजागर करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वास्तव में, वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सतत विकास में विज्ञान की भूमिका को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। कहना गलत नहीं होगा कि यह दिन देश में वैज्ञानिक संस्कृति को बढ़ावा देने का एक सशक्त मंच है। विज्ञान मानव जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाता है। यह अंधविश्वास और रूढ़ियों को दूर कर तर्क, सत्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त करता है। आज स्वास्थ्य, संचार, परिवहन और कृषि जैसे क्षेत्रों में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। नई-नई तकनीकों के विकास से समय और श्रम की बचत हुई है तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है। प्राकृतिक घटनाओं के रहस्यों को समझने में भी विज्ञान हमारी सहायता करता है।

बिजली, इंटरनेट, मोबाइल फोन और आधुनिक परिवहन के तमाम साधन, ये सभी विज्ञान की ही देन हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान के कारण अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अनेक गंभीर रोगों का उपचार संभव हो पाया है। इसी तरह, कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति, उन्नत बीज, उर्वरक, आधुनिक सिंचाई तकनीक और कृषि मशीनरी ने उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इंटरनेट, उपग्रह, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुलभ बना दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय ज्ञान के प्रसार को सरल बना रहे हैं। स्पष्ट है, संचार और सूचना क्रांति विज्ञान के कारण ही संभव हो सकी है।

यह दिन केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि का स्मरण नहीं, बल्कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशीलता और नवाचार की भावना को सुदृढ़ करने का अवसर है। आज जब भारत तकनीक, अंतरिक्ष, चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है, तब विज्ञान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

**सुनील कुमार महला,** टिप्पणीकार

**अनुलोम-विलोम**

**राष्ट्रीय विज्ञान दिवस**

# अभिशाप नहीं, शांति का वाहक बने विज्ञान

हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में विद्यार्थियों की विज्ञान और लोगों को इसके प्रति रुचि बढ़ाना भी है। ऐसा लगता है कि विज्ञान के क्षेत्र में नए-नए आविष्कारों से दुनिया में शांति गायब हो रही है और कई बार आशंका होती है कि विज्ञान के तेजी से विकास करने के कारण यह मानव जाति के लिए अभिशाप और संहारक बनता जा रहा है।

हमारा देश भी विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूरज-चांद के बारे में नए-नए अध्ययन करने की ओर अग्रसर हो गया है। हमारे देश के वैज्ञानिक भी अमेरिका, चीन आदि उन दूसरे देशों से कम नहीं हैं, जो तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में अपने आपको सुपर पावर मानते हैं। आज बेशक विज्ञान ने बहुत सी उपलब्धियों के झंडे गाड़े हैं, लेकिन दुनिया से शांति गायब हो रही है। विश्व में शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती, जब तक कि दुनिया के सभी देश अपना स्वार्थ और अपनी युद्ध करने वाले हथियारों से परिपूर्ण होने की 'ईगो' को नहीं छोड़ते। विश्व शांति भंग होने का एक कारण, जो सबसे बड़ा है, वह तो यह है कि वैज्ञानिकों ने बेवजह ही दुनिया को तबाह करने वाले हथियार, परमाणु बम, मिसाइलों का निर्माण कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इनकी जरूरत ही क्या थी?

इंसान ने विज्ञान के क्षेत्र में बेशक बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं ताडंव मचा करके इंसान को यह एहसास दिलाती हैं कि कुदरत के आगे इंसान अब भी बौना है। अतः हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जो कुदरत की लक्ष्मण रेखा से बाहर हो। विज्ञान को अब जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और अन्य उन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही काम करना होगा, जो जीवमात्र के लिए हानिकारक न हो।

निस्संदेह, विज्ञान देश की प्रगति और आर्थिक विकास का आधार है। शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से यह नवाचार को निरंतर गति प्रदान करता है। वास्तव में, विज्ञान मानव सभ्यता के उज्ज्वल भविष्य की सुदृढ़ नींव है। हालांकि, विज्ञान का दुरुपयोग होने की भी आशंका को निराधार नहीं कहा जा सकता और ऐसा होने पर यह विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम वैज्ञानिक सोच अपनाएं और विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देने का अवसर भी है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि विज्ञान मानव जीवन को बेहतर बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है।

**राजेश कुमार चौहान,** टिप्पणीकार

# कर्ज के मामले में सोने ने पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड को पीछे छोड़ा

**नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।** अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वर्ण आभूषण गिरवी रखकर ऋण लेने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि गोल्ड लोन में सालाना आधार पर 127 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि अकेले दिसंबर 2025 में देशभर में स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रखकर 24061 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया है।

आरबीआई की मासिक रिपोर्ट में ऋणों से जुड़ा ब्योरा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि स्वर्ण आभूषण के बदले लिए गए ऋण में तेजी के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, ऐसा कर्ज हासिल करना आसान है। इसके लिए बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान सोने की शुद्धता की जांच करने के बाद आसानी से ऋण जारी कर देते हैं। इसमें कोई बड़ी कागजी कार्रवाई या ग्राहक के सिबिल स्कोर की जांच करने कीआवश्यकता नहीं होती है।

दूसरा, रिजर्व बैंक ने ऋण से जुड़े नियमों को सरल किया है। 2.5 लाख रुपये तक के छोटे ऋणों में सोने की कीमत का 85 प्रतिशत तक कर्ज दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे ग्राहकों को ज्यादा धनराशि आसानी से ऋण के तौर पर मिल जा रही है। इसके साथ ही, सोने की ज्वेलरी को गिरवी रखकर लिए गए ऋण की ब्याज दर पर्सनल और क्रेडिट कार्ड पर लिए गए ऋण की तुलना में कम होती है।

**127.6 प्रतिशत बढ़ा ऋण :** भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर में सालाना आधार पर स्वर्ण आभूषण के बदले ऋण लेना 127.6 प्रतिशत बढ़ गया है। जबकि वित्तीय वर्ष के आधार पर तुलना की जाए तो 85.5 प्रतिशत का उछाल आया है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि बीते वर्ष 31 मार्च तक 206282 करोड़ रुपये का ऋण सोने की ज्वेलरी के सापेक्ष जारी किया गया था, जो नवंबर 2025 में बढ़कर 358645 करोड़ रुपये का हुआ और 31 दिसंबर 2025 को बढ़कर 382706 करोड़ रुपये का हो गया।

### गोल्ड लोन का अनुपात दोगुना हुआ

सोने की ज्वेलरी को गिरवी रखकर ऋण लेने प्रक्रिया में भारी तेजी आ रही है। वहीं पर्सनल, हाउस, व्हीकल और शिक्षा के लिए लिए जाने वाले ऋण में औसत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिसंबर 2025 तक सोने पर ऋण का पोर्टफोलियो 16.2 लाख करोड़ रुपये था, जबकि पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो 15.9 लाख करोड़ रुपये रहा। दूसरी ओर, इस अवधि में आवास ऋण का पोर्टफोलियो लगभग 43 लाख करोड़ रुपये के साथ सबसे बड़ा खंड बना रहा। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही से उपभोग ऋणों में गोल्ड लोन का अनुपात दोगुना हो गया।



### अन्य ऋणों में सालाना आधार पर बढ़ोतरी

| ऋण | प्रतिशत |
|---|---|
| पर्सनल | 14.4 |
| हाउस | 11.1 |
| एफडी पर ऋण | 15.3 |
| वाहन | 10.1 |
| शिक्षा | 14.8 |

## बाजार 30s

### शेयर बाजार

| सेंसेक्स | निफ्टी |
|---|---|
| 81,287 -916.42 | 25,178 -317.90 |

### राजकोषीय घाटा 63 प्रतिशत पर रहा

**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार का रोजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 10 महीने में जनवरी 2026 तक संशोधित अनुमान के 62.97 प्रतिशत पर रहा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक केंद्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 27,08,654 करोड़ रुपये रही, जो संशोधित अनुमान का 79.5 प्रतिशत है। कुल व्यय 36,90,061 करोड़ रुपये रहा।

### विदेशी मुद्रा भंडार दो अरब डॉलर घटा

**मुंबई।** देश का विदेशी मुद्रा भंडार 20 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 2.11 अरब डॉलर घटकर 723.60 अरब डॉलर रहा। आरबीआई ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। छह फरवरी को समाप्त सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 8.66 अरब डॉलर बढ़कर 725.72 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। स्वर्ण भंडार का मूल्य 97.7 करोड़ डॉलर घटकर 127.48 अरब डॉलर रहा।

### एफडीआई 18% बढ़कर 47.87 अरब डॉलर पर

**नई दिल्ली।** चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में देश के भीतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 18 प्रतिशत बढ़कर 47.87 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। वित्त वर्ष 2024-25 की समान अवधि में देश के भीतर 40.67 अरब डॉलर का एफडीआई आया था।आंकड़ों के मुताबिक, पुनर्निवेशित आय सहित कुल एफडीआई प्रवाह अप्रैल-दिसंबर 2025-26 के दौरान 73.31 अरब डॉलर रहा।

### अनिल अंबानी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए

**नई दिल्ली।** उद्योगपति अनिल अंबानी शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। एजेंसी ने उन्हें धनशोधन मामले में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था। इससे पहले गुरुवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े कथित 40,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में अनिल अंबानी ने अधिकारियों के समक्ष बयान दर्ज कराया था।

### बैंक ऑफ बड़ौदा 10,000 करोड़ जुटाएगा

**मुंबई।** सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ बड़ौदा हरित अवसंरचना बॉन्ड जारी कर 10,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रहा है। बाजार सूत्रों ने बताया कि आधार निर्गम आकार 5,000 करोड़ रुपये है। इसमें अधिक बोली आने पर 5,000 करोड़ रुपये तक की बोली रखने (ग्रीन शू) का विकल्प शामिल होगा जिससे कुल निर्गम आकार 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

### फिनटेक कंपनी चार हजार छंटनी करेगी

**बैंकॉक।** वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ब्लॉक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जैक डोर्सी ने कहा कि कंपनी अपने 10,000 से अधिक कर्मचारियों में से 4,000 से अधिक की छंटनी कर रही है। यह कृत्रिम मेधा (एआई) के उपयोग का लाभ उठाने के लिए पुनर्गठन का हिस्सा है। गौरतलब है कि कंपनी की स्थापना 2009 में की गई थी।

नए आधार वर्ष पर इस बार हुई गणना, विनिर्माण-सेवा जैसे क्षेत्रों और निजी खपत में बढ़ोतरी दर्ज की गई

# भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी बरकरार

**रिपोर्ट**

**नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।** वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुआ अर्थव्यवस्था वाला देश बना हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया गया कि मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7.6 फीसदी की रफ्तार से बढ़ सकती है, जो पूर्व अनुमान से 0.2 प्रतिशत अधिक होगी।

पहले जीडीपी 7.4 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था। इस बार जीडीपी की गणना आधार वर्ष 2011-12 के बजाय 2022-23 के आधार पर की गई है। इस नई गणना के हिसाब से तिमाही में वास्तविक जीडीपी 84.54 लाख करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल इसी तिमाही में 78.41 लाख करोड़ रुपये थी।

चालू वित्त वर्ष की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में विनिर्माण, निर्माण, सेवा, निजी खपत जैसे क्षेत्रों में सालाना आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि कृषि और खनन जैसे कुछ क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई है। यह आंकड़े इसलिए भी अहम हैं क्योंकि यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बाद की पहली पूरी तिमाही है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की वृद्धि दर यह बताती है कि घरेलू मांग और विनिर्माण क्षेत्र सेक्टर में मजबूती बनी हुई है।

**नए आंकड़े आएंगे:** सरकार सिर्फ नए आंकड़े ही नहीं जारी करेगी, बल्कि पुराने आंकड़ों की भी नए आधार वर्ष हिसाब से दोबारा गणना करेगी।1950-51 तक के आंकड़े दिसंबर 2026 तक आने की उम्मीद है। कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी आंकड़ों को जीडीपी की गणना में सही तरीके से शामिल करने के लिए आधार वर्ष को संशोधित किया गया है।

### बीती छह तिमाहियों में जीडीपी की रफ्तार




### क्षेत्रवार तीसरी तिमाही में तेजी (%)

| क्षेत्र | वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2025-26 |
|---|---|---|
| विनिर्माण | 10.8 | 13.3 |
| कंस्ट्रक्शन | 6.4 | 6.6 |
| कृषि | 5.8 | 1.4 |
| खनन | 13.1 | 4.7 |
| ट्रेड, होटल व अन्य | 6.7 | 11.0 |
| वित्त, रियल एस्टेट व अन्य | 11.1 | 11.2 |



### जानें नए आधार वर्ष से जुड़े जरूरी सवाल-जवाब

**■ आधार वर्ष क्या है?**
आधार वर्ष वह साल होता है, जिसे मानकर देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि मापी जाती है। इससे महंगाई का असर अलग कर दिया जाता है, ताकि यह समझा जा सके कि वास्तव में उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों में कितनी बढ़ोतरी हुई है।

**■ इसे बदलने जरूरत क्यों पड़ती है?**
यदि आधार वर्ष बहुत पुराना हो जाए तो वह मौजूदा अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर नहीं दिखा पाता। नई तकनीक, डिजिटल सेवाएं, लोगों के खर्च करने के तरीके और नए सेक्टर जुड़ जाते हैं। इसलिए कुछ वर्षों के अंतराल पर आधार वर्ष को अपडेट करना आवश्यक होता है।

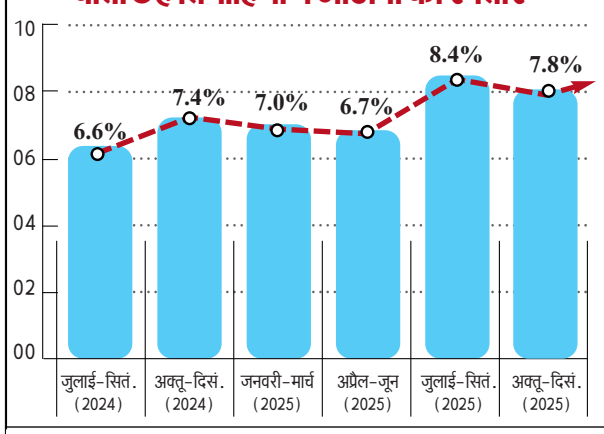

**■ राष्ट्रीय लेखा का नया आधार वर्ष क्या होगा?**
राष्ट्रीय लेखा का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया गया है। हालांकि आमतौर पर हर पांच साल में यह संशोधन होता है, लेकिन कोविड महामारी और जीएसटी लागू होने के कारण इसमें देरी हुई।

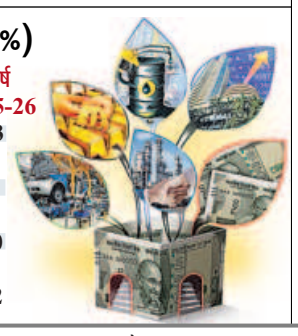

**■ किन नए आंकड़ों को शामिल किया जाएगा?**
आर्थिक आंकड़ों को ज्यादा सटीक बनाने के लिए जीएसटी डेटा, ई-वाहनों से जुड़े आंकड़े और घरेलू सेवाओं (जैसे रसोइया, चालक, घरेलू सहायक) से जुड़े आंकड़े शामिल किए जाएंगे। इससे अर्थव्यवस्था की अधिक व्यापक तस्वीर सामने आएगी।

### आम लोगों को ऐसे फायदा होगा

1. अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
2. सरकार बेहतर नीतियां बना सकेगी, जिससे रोजगार, निवेश और विकास योजनाएं ज्यादा प्रभावी होंगी।
3. महंगाई और आय से जुड़े आंकड़े ज्यादा सटीक होंगे, जिससे सब्सिडी, वेतन और सामाजिक योजनाओं का निर्धारण बेहतर तरीके से हो सकेगा।
4. अलग-अलग सेक्टर की सही तस्वीर सामने आने से निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ सकते हैं।

## सोना 1800 रुपये उछला, चांदी लुढ़की

**नई दिल्ली, एजेंसी।** राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत 1,800 रुपये बढ़कर 1,64,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।

दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत गुरुवार को 1,62,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी। हालांकि, चांदी में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही और 2,500 रुपये यानी टूटकर 2,68,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही। इसका पिछला भाव 2,70,500 रुपये प्रति किलोग्राम था।

## डॉलर के मुकाबले 91 के पार रुपया

**मुंबई, एजेंसी।** कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी पूंजी निकासी के कारण शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे टूटकर 91.08 पर बंद हुआ।

गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 90.91 पर अपरिवर्तित रुख के साथ बंद हुआ था। विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने की वजह से रुपया नकारात्मक रुख के साथ कारोबार करेगा।

## विदेशी निवेशकों ने की भारी निकासी

**मुंबई, एजेंसी।** भारतीय शेयर बाजारों में शुक्रवार को आई बड़ी गिरावट के पीछे एक साथ कई कारण काम करते दिखे। सबसे अधिक विदेशी निवेशक बिकवाल बने हुए हैं। उन्होंने पिछले दो दिनों में 10 हजार करोड़ से अधिक रुपया निकाल लिया है।

आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 7,314 करोड़ मूल्य के शेयर बेचे।इससे पहले गुरुवार को उन्होंने 3,465.99 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी।

## मेमोरी चिप संकट से सिकुड़ सकता है स्मार्टफोन बाजार

**नई दिल्ली, एजेंसी।** बाजार अनुसंधान संस्था आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार मेमोरी चिप की कमी और उनकी बढ़ती कीमतों के कारण इस वर्ष स्मार्टफोन की आपूर्ति में करीब 13 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है।

अनुमान है कि 2026 में दुनिया भर में लगभग 1.12 अरब स्मार्टफोन की बिक्री होगी, जो पिछले वर्ष के लगभग 1.26 अरब के मुकाबले काफी कम है। इसे पिछले एक दशक की सबसे बड़ी गिरावट माना जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े डाटा सेंटर की बढ़ती मांग के कारण मेमोरी चिप की उपलब्धता कम हो गई है। इससे चिप की कीमतों में तेज उछाल आया है और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों की लागत बढ़ गई है। कई कंपनियां कम मुनाफे वाले सस्ते मॉडलों का उत्पादन घटा रही हैं।


**Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Limited**
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
GSTIN: 09AACCU2250P1ZZ CIN: U85310UP2018SGC102425

Date: 26-02-2026

**Tender Notice Invitation**

Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Limited, Lucknow invites tenders on GeM Portal from eligible and qualified Manufacturer/Importer/Authorized Agent for supply of **following Medical Equipment's.** The schedules of Tendering activities are as here under:

| Sr. No. | Tender Ref. No. & Date | Items Name | Date & Time of Pre-Bid Meeting | Last Date & Submission of Online Bids | Date & Time of Opening of Technical Bids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEM/2026/B/ 7280138 Dated: 26-02-2026 | Power Generator-DG Set (up to 900 KVA) | 05/03/2026 at 3:00 PM in Conference Hall of UPMSCL, Lucknow. | 19/03/2026 up to 15:00 PM | 19/03/2026 at 15:30 PM |
| 2 | GEM/2026/B/ 7277613 Dated: 26-02-2026 | Stacker | 05/03/2026 at 4:00 PM in Conference Hall of UPMSCL, Lucknow. | 19/03/2026 up to 18:00 PM | 19/03/2026 at 18:30 PM |
| 3 | GEM/2026/B/ 7293406 Dated: 26-02-2026 | Walk in Cooler | 06/03/2026 at 4:00 PM in Conference Hall of UPMSCL, Lucknow. | 19/03/2026 up to 15:00 PM | 19/03/2026 at 15:30 PM |

The details of tender notice are given on GeM Portal & UPMSCL website www.upmsc.in. Kindly check GeM Portal & UPMSCL website for any detail & updates.

**Managing Director, UPMSCL**

**Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh**



**उत्तर रेलवे**

**ई-अधिप्राप्ति हेतु सूचना**

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/मालभाड़ा सेवाएं, दिल्ली मंडल, उत्तर रेलवे, रेलवे बोर्ड के पत्र सं. **2020/TC(FM)/02/05** दिनांक **17.04.2025**, के अनुसार, 01 (एक) एन एम जी रेक के 25 वैगनों पर लगाये जाने हेतु 50 पैडलॉक्स (ई-लॉक्स) की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव हेतु 01 वर्ष की अवधि के अनुबंध के लिए ऑनलाइन IREPS पोर्टल (www.ireps.gov.in) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करता है:

| निविदा संख्या | निविदा बंद होने की तिथि तथा समय | पैडलॉक्स (ई-लॉक्स) (प्रति वैगन) | पैडलॉक्स (ई-लॉक्स) की कुल संख्या | अनुबंध की अवधि | अनुमानित राशि (प्रति ई-लॉक) (रु.) | कुल अनुमानित राशि (50 ई-लॉक्स हेतु) (रु.) | बयाना राशि (ई.एम.डी.) (रु.) | निविदा राशि @18% GST सहित (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-MG-NMG-Padlocks-eLocks | दिनांक 23.03.2026 को 15:00 बजे | 02 | 50 | 01 वर्ष | 14,632/- | 7,31,600/- | 14,600/- | 0/- |

**महत्वपूर्ण सूचनाः**

1. ई-अधिप्राप्ति के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को https://www.ireps.gov.in/html/helpdesk/learning_centre.html {e-Tender(works)} पर जाने की सलाह दी जाती है।
2. रेलवे प्रशासन के पास किसी भी समय इस निविदा/अनुबंध को समाप्त करने और/या अनुबंध को बीच में ही समाप्त करने / जारी रखने के संबंध में कोई भी निर्णय लेने का पूर्ण और निरपेक्ष अधिकार सुरक्षित है, जिसमें इसके सफल निष्पादन के आधार पर कोई भी संशोधित/अतिरिक्त नियम और शर्तें लागू हो सकती है, या इस संबंध में रेलवे द्वारा जारी किए गए किसी अन्य संशोधित नियम के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है।

680/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ



**नगर निगम वाराणसी**
**VARANASI MUNICIPAL CORPORATION**
**Sigra, Varanasi - 221010**

**NOTICE INVITING TENDER (NIT)**

**NIT No.:** 233/T/VSCL/TENDER /2025-26 **Date:** 27/02/2026

The Municipal Commissioner, Varanasi Municipal Commissioner, Varanasi invites an online tender for following work:

| S. No. | Name of Works | Tender Fees (Non-Refundable) | Earnest Money Deposit |
|---|---|---|---|
| 1. | Request for Proposal for Selection of Agency to Design, Construct, Operate and Maintain Waterless Urinal Models Public Toilets/ Urinals on D.B.F.O.T. basis at various Locations in Varanasi for a license period of 05 years extendable up to 05 years | ₹10,000/- + 18% GST = ₹11,800/- | ₹5,00,000/ |

The prospective bidders may download the detailed Tender/RFP document in this regard from https://etender.up.nic.in from 28/02/2026 at 0930 Hrs. (IST) to 21/03/2026 till 1600 Hrs. (IST).For queries, if any, email: mail@varanasismartcity.gov.in latest by 07/03/2026 till 1400 Hrs. (IST). The Last Date & Time of Online Bid Submission: 21/03/2026 till 1600 Hrs. (IST)

s/d-
**Municipal Commissioner**
Varanasi Municipal Corporation

**Ref. No.:** 127/VSCL/2025-26 **Date:** 27.02.2026



**PSPCL**
**पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालयः पीएसईबी हेड ऑफिस, दी मॉल, पटियाला-147001
कॉर्पोरेट पहचान सं.: U40109PB2010SGC033813
वेबसाइटः www.pspcl.in, सम्पर्क नं.: 0175-2207649

**निविदा पूछताछ सं. 356/DIT-1148** दिनांकः 27.02.2026

डिप्टी चीफ इंजीनियर/आईटी (ओएंडएस) संगठन (चीफ इंजीनियर/आईटी का कार्यालय के अधीन), पीएसपीसीएल, कक्ष सं. 402, चतुर्थ तल, सात मंजिला भवन, दी मॉल, पटियाला द्वारा पीएसपीसीएल के लिए यूटीलिटी नेटवर्क जीआईएस डेटाबेस का सृजन एवं कंज्यूमर इंडेक्सिंग, जीआईएस आधारित फील्ड सर्वे एवं असेट मैपिंग हेतु एजेंसी (जीआईएस क्रियान्वयन एजेंसी-जीआईए) की सूचीबद्धता के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना और निविदा विनिर्देशन के लिए कृपया दि. 03.03.2026, पूर्वा. 09.00 बजे से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोटः शुद्धिपत्र और संशोधन, यदि कोई हो तो उसे https://eproc.punjab.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा।

RO No. 1079/12/2025/26/8941 सी 314/26



**उत्तर रेलवे**

**निविदा आमंत्रण सूचना**

| | | | |
|---|---|---|---|
| कार्य का नाम और इसकी स्थिति | **48-R1-SRDEE-G-DLI-2025-26** दिल्ली डिवीजन में स्थापित ओमेगा ब्रांड की लिफ्टों के लिए तीन साल की व्यापक वार्षिक प्रबंधन योजना (एएमसी)। | | |
| निविदा की अनुमानित लागत | ₹ 86,79,060.00/- | बयाना राशि | ₹ 173600.00/- |
| निविदा निवेदन की दिनांक व समय | 23.03.2026 16.00 बजे | निविदा खोलने की दिनांक व समय | 23.03.2026 16.00 बजे |
| कार्यालय का पता | वरिष्ठ मंडल विधुत अभियन्ता/ जी, स्टेट एंट्री रोड नई दिल्ली | | |
| वेब साइट व नोटिस बोर्ड | www.ireps.gov.in वरिष्ठ मंडल विधुत अभियन्ता/ जी, नई दिल्ली | | |

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 692/2026



**उत्तर रेलवे**

**निविदा सूचना**

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण, उत्तर रेलवे, तिलक ब्रिज नई दिल्ली निम्नलिखित कार्य के लिए दो पैकेट प्रणाली के अंतर्गत ई-निविदा आमंत्रित करते हैं:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कार्य का नाम एवं स्थान | दिल्ली सफदरजंग स्टेशन (DSJ) पर टर्मिनल परीक्षण सुविधा के लिए, नए प्लेटफॉर्म नम्बर 4 और 5 आईलैण्ड प्लेटफार्म के निर्माण के साथ यार्ड रिमोडलिंग का कार्य, (BLT) बालास्टलैस ट्रैक के साथ वॉशेबल एपरन (Washable apron) का प्रावधान, और प्लेटफॉर्म नम्बर 1 से 5 पर पीएफ ड्रेन (PF Drain का प्रावधान इत्यादि सम्बन्धित कार्य करने हेतु। |
| 2. | अनुमानित लागत | रुपये 223790214.86 |
| 3. | कार्य पूरा करने की अवधि | 18 माह |
| 4. | जमा की जाने वाली जमानती राशि | रुपये 12,69,000.00 |
| 5. | ई-निविदा प्रस्तुत करने और निविदा खुलने की तिथि और समय | निविदा दिनांक 05.03.2026 से दिनांक 20.03.2026 15.00 बजे तक आई आर ई पी एस की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड की जा सकती हैं तथा उसके बाद केवल तकनीकी सह वाणिज्यिक बिडों को 15.00 बजे दिनांक 20.03.2026 को खोला जाएगा। |
| 6. | विस्तृत ई-निविदा सूचना तथा निविदा दस्तावेज | उपर्युक्त निविदा दस्तावेज आई आर ई पी एस की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर 27.02.2026 से 20.03.2026 तक उपलब्ध होगी। उपरोक्त निविदा से संबंधित अन्य सभी शर्तें और निबंधन निविदा दस्तावेज में दी गई हैं। |

सं0 496-एकाउन्टस-सी-यार्ड रिमोडलिंग-तिलक ब्रिज दिनांकः 27.02.2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 664/26



**जल संसाधन विभाग**
**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**
**सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, खगौल।**

बिहार सरकार

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या -NIT- 06/2025-26

**राष्ट्रीय स्पर्द्धा निविदा आमंत्रण**

(केवल ई-टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

1.कार्य का विवरण-

| क्रम सं0 | कार्य का नाम | प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में) | अग्रधन की राशि (लाख रू0 में) (ऑन लाईन अथवा फिजिकल /मैनुअल मोड में भुगतेय) | परिमाण-विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतेय) रू0 | बेलट्रॉन को देय "बीड प्रोसेसिंगफी" (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतेय) रू0 | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | गंगा नदी के दायें तट पर ग्राम हल्दी छपरा (बदल टोला) के U/S से श्मशान घाट (नैयका टोला) तक कटाव निरोधक कार्य। (एजेण्डा सं0-243/09/2026) | 139.56 | 2.80 | 10,000.00 | 3,540.00 | 15.05.2026 |
| 02 | गंगा नदी के दायें तट पर ग्राम हल्दी छपरा के निकट अतिभारित (Overburden) को हटाने का कार्य। (एजेण्डा सं0-243/10/2026) | 48.69 | 0.98 | 5000.00 | 590.00 | 15.05.2026 |
| 03 | गंगा नदी के निम्न धार में ग्राम-दरवेशपुर में वर्ष 2025 में कराये गए कटाव निरोधक कार्य के निकट कटाव निरोधक कार्य। (एजेण्डा सं0-243/12/2026) | 66.92 | 1.34 | 10,000.00 | 590.00 | 15.05.2026 |

2 विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, खगौल। मो0-7463889543
3 निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक-25.02.2026
4 निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की अवधि : दिनांक 06.03.2026 के 10.00 बजेपूर्वाह्न से 11.03.2026 के 03.00 बजे अपराह्न तक (केवल वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
5 प्री-बीड मीटिंग का समय स्थान एवं तिथि : दिनांक 07.03.2026 को 02.30 बजे अपराहन में मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना का कार्यालय।
6 तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 13.03.2026 के अपराह्न 03.30 बजे (केवल वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)।
7 वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर घोषित की जायेगी।
8 निविदा खोलने का स्थान : केवल वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर।
9 निविदा की वैद्यता अवधि : 120 दिन।
10 विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु : वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in /www.wrd.bih.nic.in / www.state.bihar.nic.in पर देखा जा सकता है।

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखी जा सकती है।

PR- 025174 ( W R D ) 2025-26

कार्यपालक अभियंता
सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, खगौल
मो0: 7463889543

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।



**कार्यालय, महाप्रबन्धक, पी0आई0यू0-03, यू०पी०डी०सी०सी०एल० देहरादून**

**ई-निविदा सूचना**

**ई-निविदा सूचना 05/ पी0आई0यू0-3/2025-26, दिनांक 27.02.2026**

महाप्रबन्धक, पी0आई0यू0-3, यू०पी०डी०सी०लि०, देहरादून द्वारा निम्न कार्यो के निर्माण हेतु टू-बिड प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा हेतु वही ठेकेदार मान्य होंगे जो केन्द्र सरकार / राज्य सरकार या केन्द्रशासित प्रदेशों में कार्य की लागत की समकक्ष श्रेणी में पंजीकृत होंगे।

| क्र. सं. | कार्य का नाम | धरोहर धनराशि लाख रु० में | निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0) | निविदा की वैधता अवधि | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Har-Ki-Pauri Revitalisation (Haridwar) | रू0 73.13 लाख | 5000.00+ 900.00 (18%GST) | 90 दिवस | 24 माह |
| 2 | North of Har-Ki-Pauri Development (Haridwar ) | रू 77.54 लाख | 5000.00+ 900.00 (18%GST) | 90 दिवस | 24 माह |
| 3 | Rodibelwala Area Revitalisation and Development (Haridwar ) | रू 70.11 लाख | 5000.00+ 900.00 (18%GST) | 90 दिवस | 24 माह |

निविदाओं से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी हेतु उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाईट www.uktenders.gov.in पर लॉगऑन करें।

(मनोज कुमार सिंह)
महाप्रबन्धक, पी0आई0यू0-3
यू०पीडी०सी०सी०लि०, देहरादून

संपादकीय जागरण

शनिवार, 28 फरवरी, 2026 : फाल्गुन शुक्ल - 12 वि. 2082

आसक्ति से मुक्ति ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है

# आगे आए उद्योग जगत

बजट के बाद 'विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त' विषय एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय कंपनियों को नए निवेश एवं नवाचार के साथ आगे आना चाहिए, उस पर उन्हें सकारात्मकता के साथ सक्रियता का परिचय देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से बजट घोषणाओं का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। कायदे से तो ऐसे किसी आग्रह की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। उद्योग जगत को स्वतः सक्रिय हो जाना चाहिए। यह पहली बार नहीं, जब प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को नवाचार के जरिये अपनी क्षमता प्रदर्शित करने को कहा हो। वे इसके साथ ही यह भी कहते रहे हैं कि उद्योग जगत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनना चाहिए और शोध एवं विकास में निवेश करना चाहिए। विडंबना यह है कि हमारे ऐसे बड़े कारोबारी भी यह काम नहीं कर रहे हैं, जिनके पास पूंजी की कोई कमी नहीं। वे नवाचार के नाम पर ऐसे नए काम अधिक हाथ में लेते हैं, जिनसे कम समय में आसानी से धन अर्जित किया जा सके। यही कारण है कि वे ऐसे कोई उत्पाद तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी देश के साथ दुनिया में भी मांग हो।

यह सामान्य बात नहीं कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने के बाद भी चंद भारतीय उत्पाद ही ऐसे हैं, जिनकी विश्व में थोड़ी-बहुत पहचान और प्रतिष्ठा है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि भारतीय उद्योग जगत शोध एवं विकास में पैसा खर्च न कर पाने के कारण न तो चीनी उत्पादों का मुकाबला कर पा रहे हैं और न ही अपने उत्पाद विश्व बाजार में आसानी से खपा पा रहे हैं। जहां चीन में उद्योग जगत आर्थिक विकास का नेतृत्व करते दिखता है, वहीं भारत में कारोबारी सरकार के प्रोत्साहन पर भी तत्परता नहीं दिखाते। एक-दो कारोबारी समूहों को छोड़ दिया जाए तो आम तौर पर हमारे कारोबारी वैश्विक स्तर की उत्पादकता हासिल करने के लिए सक्रिय नहीं। वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता भी विश्वस्तरीय बनाने के लिए उत्साही नहीं हैं। एक ऐसे समय जब सरकार एक के बाद एक देशों से मुक्त व्यापार समझौते कर रही हैं और इसके चलते शीघ्र ही कई विकसित देशों के बाजार भी भारतीय उद्योग जगत की पहुंच में होंगे, तब तो उन्हें इन समझौतों का पूरा लाभ उठाने के लिए कमर कसनी ही चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि सरकार प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही है। उचित यह होगा कि प्रधानमंत्री ने सरकार, उद्योग जगत, वित्तीय संस्थानों और शिक्षाविदों के बीच सहयोग स्थापित करने वाले जिस 'रिफार्म पार्टनरशिप चार्टर' की बात की, उस पर गंभीरता से काम हो, ताकि वह विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बन सके।

# जांच एजेंसी पर सवाल

दिल्ली में आबकारी घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री समेत सभी 23 आरोपितों को बरी कर दिया गया है। अदालत ने आरोपितों को बरी करते हुए सीबीआइ पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने कहा है कि जांच एजेंसी ने ऐसे कोई सुबूत नहीं दिए जिनसे प्रथमदृष्टया स्थापित होता हो कि आरोपितों ने कोई साजिश रची थी। यही नहीं, अदालत ने आरोपित नंबर एक को बिना सुबूत आरोपित बनाए जाने पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं और इस मामले में जांच अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निश्चित तौर पर यह मामला गंभीर है कि जांच एजेंसी जिन्हें आरोपित बताती रही वह आरोप पत्र में उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं पेश कर सकी।

जांच में खामियों को लेकर संबंधित अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई की जाए, ताकि निष्पक्षता बरकरार रह सके

ऐसा नहीं है कि सीबीआइ पर पहली बार कोई सवाल खड़े हुए हैं। पूर्व में भी कई मामलों में सीबीआइ की किरकिरी हो चुकी है। आबकारी घोटाले के इस मामले में भी जांच एजेंसी को कठघरे में खड़ा किया जाना सर्वथा उचित है। यह सही है कि सीबीआइ ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट गई है, लेकिन निचली अदालत से सभी आरोपित बरी हैं, ये सीबीआइ की जांच पर बड़ा सवाल है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि जांच में खामियों को लेकर संबंधित अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाए, ताकि जांच एजेंसी की निष्पक्षता बरकरार रखी जा सके।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा पर कांग्रेस की आपत्ति उचित है?

आज का सवाल
क्या अदालती राहत के बाद अरविंद केजरीवाल राजनीतिक रूप से और मजबूत होकर उभरेंगे?

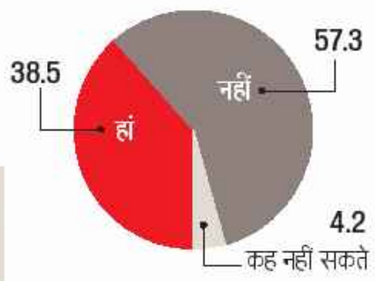


परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

# विवादों के केंद्र में शंकराचार्य

हृदयनारायण दीक्षित

यह दुखद है कि आज के शंकराचार्य स्वयं के सम्मान के लिए झगड़ा करते हैं और कोर्ट-कचहरी में पदों की लड़ाई लड़ते हैं

शंकराचार्य भारत की अनोखी त्याग परंपरा का विस्तार हैं। आदि शंकराचार्य ने विश्व दर्शन को अद्वैत दर्शन से समृद्ध किया। अल्प आयु में ही उन्होंने 11 प्रमुख उपनिषदों, गीता और ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया। सांस्कृतिक एकता के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। बौद्ध एवं अन्य विद्वानों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। उन्हें सभी स्थानों पर विजय मिली। शंकराचार्य के भ्रमण को उस समय दिग्विजय कहा गया। उन्होंने सांस्कृतिक विचारधारा को प्रवाहमान बनाने के लिए चार मठों की स्थापना की। कर्नाटक में शृंगेरी, उत्तराखंड में जोशीमठ, ओडिशा में पुरी और गुजरात में द्वारका। उनके चार विद्वान शिष्यों ने मठों का नेतृत्व किया। उन्होंने चारों वेदों को प्रतिष्ठा दी। सभी मठों को एक वेद से जोड़ा-शृंगेरी पीठ, कर्नाटक-यजुर्वेद, द्वारका पीठ, गुजरात-सामवेद, पुरी पीठ, ओडिशा-ऋग्वेद, ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड-अथर्ववेद। वे द्रष्टा थे। अद्वैत वेदांत उनका दर्शन था। डा. एस. राधाकृष्णन ने उन्हें असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति बताया था।

दुर्भाग्य से आधुनिक काल के शंकराचार्य अपने कार्य व्यवहार से निराश करते हैं। वे प्रेरित नहीं करते। उत्साह और उल्लास नहीं देते। वे व्यापक हिंदू समाज को कोई ठोस एवं प्रभावी दिशा नहीं देते। इन दिनों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रशासन और शासन से विवाद के कारण लगातार चर्चा में हैं। इस विवाद की शुरुआत प्रयागराज में माघ मेले में स्थानीय प्रशासन के बीच टकराव से हुई थी। मौनी अमावस्या पर्व पर स्वामी जी पारंपरिक पालकी से स्नान के लिए निकले। प्रशासन ने उनका ध्यान भीड़ प्रबंधन की ओर आकर्षित किया और उनसे पैदल चलने का अनुरोध किया। इसके बाद उनके अनुयायियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। आचार्य के अनुयायियों के अनुसार शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। स्वामी जी ने इसे शंकराचार्य का अपमान बताया और बिना स्नान किए लौट आए। प्रशासन ने स्वामी जी को लिखित चेतावनी दी। नोटिस में उन पर सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन आदेश का उल्लेख करते हुए पूछा गया कि वे अपने शिविर के बाहर बोर्ड पर शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं?

पता नहीं इस विवाद का पटाक्षेप कैसे और कब होगा, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि हम भारत के लोग साधु-संतों को सम्मान से देखते हैं। गीता में संन्यासी की परिभाषा है, 'जो इच्छारहित है, सभी द्वंद्वों से मुक्त है, वही संन्यासी है।' आदि शंकराचार्य ऐसे ही दार्शनिक संन्यासी थे। साधना की सिद्धि प्राप्त संत हैं। महतत्व के बोध वाला महंत है, लेकिन आज के

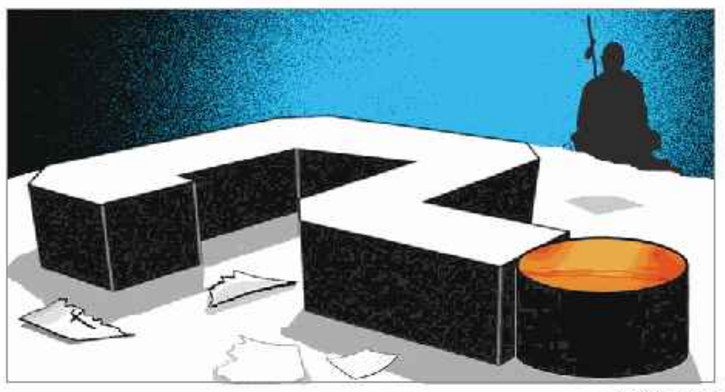

अवधेश राजपूत

शंकराचार्य संभवतः ऐसा नहीं मानते। वे स्वयं के सम्मान के लिए झगड़ा करते हैं। कोर्ट-कचहरी में पदों की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा पहले से भी होता आ रहा है। मठों-पीठों की संपदा को लेकर भी झगड़े होते रहे हैं और वे अंग्रेजी राज में ही प्रिवि काउंसिल तक जा चुके थे। पीवी काणे ने 'धर्मशास्त्र का इतिहास' में लिखा है कि मठों में अधिकार क्षेत्र आदि को लेकर झगड़े होते रहे हैं।

प्रथम शंकराचार्य ने मठों के संचालन के लिए 'मठाम्नाय महानुशासन' की नियमावली बनाई थी। मठाम्नाय का अर्थ है महानुशासन। शंकराचार्य दर्शन और अध्यात्म के परम विद्वान थे। उन्होंने काम करते हुए अनुभव कर लिया था कि सांसारिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में संलग्न व्यक्ति धर्म प्रचार का कार्य नहीं कर सकेगा। इसलिए उन्होंने संसार त्यागी सुयोग्य ब्रह्म पारायण संन्यासियों को धर्म प्रचार का कार्य सौंपा और सबके लिए अनुशासन पालन का नियम बनाया। शंकराचार्यों को उससे शासित होना चाहिए। आश्चर्य है कि हमारे शंकराचार्य कुंभ या अन्य अवसरों पर पहले स्नान के लिए झगड़ते हैं। राजनीतिक मामलों में वक्तव्य देते हैं। धार्मिक मामलों को राजनीतिक रंग देते हैं।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन अंतरराष्ट्रीय उत्सव था, लेकिन यह आयोजन राजनीतिक बहस का हिस्सा बना। इसका कारण कुछ शंकराचार्यों के बयान रहे। उनके बयानों से विपक्षी दलों को मसाला मिला। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर सबसे ज्यादा मुखर रहे। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री ही मूर्ति स्थापित करेंगे तो शंकराचार्य क्या वहां ताली बजाने के लिए बैठेंगे? अयोध्या और प्रयागराज के संदर्भ तो ताजा हैं। एक समय ज्योतिष्ठ पीठ बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सिविल जज ने वासुदेवानंद को स्वयं को शंकराचार्य घोषित करने पर रोक लगा दी थी। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के समय भी केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल भीम शंकर और शंकराचार्य स्वरूपानंद टकरा गए थे। एक शंकराचार्य ने साईं बाबा पर लगातार हमले किए।

जागृत समाज में आप जबरदस्ती सम्मान नहीं ले सकते। सम्मान का इच्छुक व्यक्ति राष्ट्र के जीवन मूल्यों के अनुसार जीवन-यापन करता है। समाज हर गतिविधि को ध्यान से देखता है। कोई यों ही आदि शंकराचार्य की तरह सुविख्यात नहीं हो जाता। उसे तप और साधना की अग्नि में स्वयं को तपाना होता है। वह इतिहास से सामग्री लेता है। अनुकरणीय तत्व छांटता है। वह सबको प्रेरित करता है, लेकिन कुछ शंकराचार्यों के कार्य और व्यवहार से देश और विशेष रूप से हिंदू समाज निराश हुआ है। शंकराचार्य संस्था यूरोप के पोप जैसी नहीं है। हिंदू शंकराचार्यों सहित देश की सभी धार्मिक परंपराओं का आदर करते हैं। शंकराचार्य नए समाज की आवश्यकता समझें। वे भारत के धर्म, अध्यात्म की परंपरा को व्यक्तिगत अहमान्यता से मुक्त होकर नए आकाश और नए पंख दें।

देश के सामने आदि शंकराचार्य का प्रेरक व्यक्तित्व है। उन आदर्शों के विपरीत आचरण समाज को दुखी करता है। सभी साधु, संत और महंत हिंदू मन की पुकार सुनें। हिंदू समाज को दार्शनिक और प्रगतिशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला समाज बनाने के लिए मार्गदर्शन करें। धर्म-दर्शन के स्तर पर विश्ववारा बनाने का दायित्व पूरा करने के लिए अगुआई करें, ताकि भारत की प्रतिष्ठा और बढ़े।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

# विकसित देश का मंत्र है वैज्ञानिक सोच

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों को याद करने का ही नहीं, बल्कि बच्चों, युवाओं से लेकर आमजन में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने का अवसर भी बनना चाहिए। अगर भारत को विकसित देश बनना है, तो उसमें विज्ञान की बड़ी अहम भूमिका होगी। यह भूमिका तभी सार्थक होगी, जब हम वैज्ञानिक शोधों को अपनी कार्यसंस्कृति का हिस्सा बना लें। इसके लिए आवश्यक होगा कि हम बुनियादी स्तर से ही बच्चों को ऐसी जानकारियां देने के उपाय करें, जो उनमें वैज्ञानिक सोच के विकास में सहायक बने। इसके लिए पारंपरिक ज्ञान के साथ ही वैज्ञानिक स्वाभाव भी विकसित करना होगा। इसके लिए बच्चों को हर तरह के सवाल पूछने के लिए भी प्रोत्साहित करना होगा। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए उनमें आसपास की चीजों को समझने के प्रति कौतूहल भी पैदा करना होगा। पढ़ाई में रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमारे बच्चे प्रयोगशालाओं में प्रयोग करें और अपनी गलतियों से सीखें। 'करके सीखने' अर्थात लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से छात्रों के सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक प्रयोगशाला के अनुभवों में सहायता मिलेगी। हालांकि यह सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा। इसके लिए हमें गांवों से लेकर शहरों तक स्कूलों में अच्छी विज्ञान प्रयोगशालाओं का व्यापक जाल बिछाना होगा। इसी सोच से प्रेरित भारत सरकार द्वारा गत वर्ष अक्टूबर तक 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा चुकी हैं और अगले पांच वर्षों में 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में स्थापित करने की योजना बनाई है।

नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत इन लैब्स का उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, रचनात्मकता और स्टेम (साइंस-टेक्नोलाजी-इंजीनियरिंग-मैथ) कौशल को बढ़ावा देना है। यह पहल हर जिले में तकनीक-आधारित नवाचार को बढ़ावा देगी। इस क्रम में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआइआर का 'जिज्ञासा' कार्यक्रम स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक चेतना और जिज्ञासा जगाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

डा. सुशील द्विवेदी

यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि शोध-अनुसंधान का मतलब केवल पीएचडी कर लेना नहीं होता और न ही होना चाहिए

वैज्ञानिक चेतना को प्रोत्साहन देना आवश्यक ● फाइल

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ''करके सीखने'' (लर्निंग बाय डूइंग) के माध्यम से छात्रों के सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक प्रयोगशाला के अनुभवों से जोड़ने में सहायक हो रहा है। इसरो का युविका (युवा विज्ञानी कार्यक्रम) स्कूली बच्चों में विज्ञान और अंतरिक्ष तकनीक के प्रति गहरी समझ और रुचि विकसित करने के लिए एक शानदार पहल है। इसे 'कैच देम यंग' यानी छोटी अवस्था में ही स्कूली छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के प्रति रुचि जगाकर उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से आकार दिया गया है। दो सप्ताह के इस आवासीय कार्यक्रम में छात्रों को प्रख्यात विज्ञानियों से मिलने, प्रयोगशालाओं का दौरा करने और व्यावहारिक प्रयोग (माडल राकेट्री) करने का अवसर भी मिलता है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भी बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह कार्यक्रम छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें वास्तविक दुनिया की समस्याओं को वैज्ञानिक पद्धति से सुलझाने के लिए प्रेरित करता है।

एनसीईआरटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी भी बच्चों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम बन गई है। यह प्रदर्शनी केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि युवा मस्तिष्कों में नवाचार और रचनात्मकता का संचार करने वाला एक उत्सव है। राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन के अनुरूप बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो रही है। इसी प्रकार स्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो स्कूली बच्चों में न केवल विज्ञान के प्रति रुचि पैदा कर रही है, बल्कि उनमें एक गहरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित कर रही है। यह योजना बच्चों को अपने आसपास की समस्याओं को पहचानने और उनके लिए मौलिक समाधान सोचने के लिए प्रेरित करती है। ये सब प्रयास तब और रंग लाएंगे, जब देश का उद्योग जगत अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वैज्ञानिक अध्ययन संस्थानों से गठजोड़ करके अनुसंधान का सिलसिला शुरू कर उसे गति प्रदान करे। अगर शिक्षा और उद्योग क्षेत्र में यह साझेदारी विकसित हो जाती है तो भारत को जल्द विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता।

भारत के कुछ गिने-चुने ऐसे संस्थान हैं, जिन्होंने अपनी प्रगति और कामयाबी से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसरो इनमें सबसे आगे है, लेकिन भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए इकलौते इसरो या आइआइटी से ही काम नहीं चलने वाला। हमें देश के अन्य उच्चस्तरीय संस्थानों में भी रिसर्च का एक बेहतर इकोसिस्टम विकसित करना होगा। यह भी ध्यान रखा जाए कि शोध-अनुसंधान का मतलब केवल पीएचडी कर लेना नहीं है। शोध तभी सफल है जब उसके केंद्र में यह बिंदु हो कि दैनिक जीवन को सुगम बनाने के लिए वह क्या योगदान कर सकता है? विज्ञान तभी सार्थक है जब कोई भी सामान्य समझ वाला व्यक्ति उसे आसानी से आत्मसात कर उसका उपयोग कर सके।

(लेखक शिक्षा मंत्रालय के पीएम-ई-विद्या कार्यक्रम में विज्ञान विषय के संसाधक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

## धर्म और विज्ञान

धर्म और विज्ञान की पद्धतियों में कुछ अंतर अवश्य हैं, किंतु दोनों का लक्ष्य है मनुष्य को परिष्कृत करते हुए उसे निरंतर प्रगति की ओर प्रशस्त रखना। विज्ञान को धर्मविरोधी मानना उचित नहीं। वैज्ञानिक सत्य विस्मयकारी होता है, किंतु नैतिक सत्य दैविक होता है। प्रकृति की विराटता और इसके अनंत रहस्यों को समझने की चेष्टाओं का नाम ही विज्ञान है। आस्था पर टिके धर्म और साक्ष्य पर टिके विज्ञान दोनों अपने तौर-तरीकों से घटनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट और बोधगम्य बनाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का अर्थ धर्म को नकारना नहीं है।

पृथ्वी और समुद्र की अंदरूनी परतों की छोड़ दें तो उपलब्ध ज्ञान के बावजूद ऊपरी सतह पर पलते जीवों और वनस्पतियों के मूलभूत तथ्यों का समुचित आकलन भी पर्याप्त संतोषजनक नहीं है। नियमित शोध इसीलिए हो रहे हैं, क्योंकि विकृतियों से राहत के लिए अभी तक प्राप्त ज्ञान सीमित है। प्रकृति को उत्कृष्ट अस्मिता मानते हुए शीर्ष विज्ञानियों की स्वीकारोक्ति है कि इस बाबत हम अत्यधिक अनभिज्ञ हैं। चूंकि मनुष्य का मूल स्वरूप दैविक है, इसलिए उसके मस्तिष्क और हृदय के कार्यसंचालन को वैज्ञानिक आधार पर नहीं समझ सकते। साक्ष्यों के अभाव में मनुष्य की दिव्यता को समझने-आंकने में वैज्ञानिक जुगत निष्फल रही हैं। यह संयोग नहीं कि विश्व के आधे से अधिक सुधी विज्ञानियों ने अपनी उपलब्धियों का श्रेय सीधे या परोक्ष रूप से धर्म या आध्यात्मिकता को दिया। शीर्ष विज्ञानी ईश्वर या दैविक शक्तियों के प्रति आस्थावान रहे हैं।

हम प्रेम, सौंदर्य, मित्रता जैसी जीवन की अहम अस्मिताओं को परिभाषित-मूल्यांकित नहीं कर सकते। धर्म ही है जो आज के विघटन भरे समाज में विज्ञान से डांवाडोल हो रही मानसिक एवं भावात्मक व्यवस्थाओं में संतुलन और सामंजस्य बनाता है। वही मनुष्य को संबल तथा स्थिरता प्रदान करता है।

हरीश बड़थ्वाल

## पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

### राहुल के नेतृत्व पर उठते सवाल

'गठबंधन को लेकर बेपरवाह कांग्रेस' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राज कुमार सिंह का कांग्रेस के नेतृत्व वाले आइएनडीआइए की निष्क्रियता का सटीक विश्लेषण पढ़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के चलते विपक्षी दलों ने सहजता के साथ राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का अवसर जरूर दिया, लेकिन वे गंभीरता के साथ इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी परिपक्व राजनेता की छवि बना पाने में असमर्थ दिख रहे हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस के भीतर सुगबुगाहट भी होती रहती है। कांग्रेस को असहज तब होना पड़ा, जब कुछ वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर ही प्रश्नचिह्न लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस के इस अंदरूनी विचलन से विपक्षी गठबंधन की सक्रियता प्रभावित हो रही है। इस गठबंधन के अब वैसे तेवर नहीं रहे, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिए थे। तब विपक्षी गठबंधन ने अपनी सक्रियता के चलते भाजपा को बहुमत से पीछे खड़ा कर दिया था, लेकिन अब जब चार राज्यों के साथ एक केंद्रशासित प्रदेश के चुनाव सिर पर हैं, तब आइएनडीआइए की निष्क्रियता विपक्षी दलों को हतोत्साहित कर रही है। अभी हाल में बिहार और महाराष्ट्र की शर्मनाक हार ने विपक्ष के मनोबल को तोड़ने का काम किया है। ऐसे में यदि समय रहते विपक्षी गठबंधन को मजबूत नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनावों में विपक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतने अल्प समय में आइएनडीआइए के दरकते ढांचे को दुरुस्त कर उसमें चुनावी ऊर्जा का संचार राहुल गांधी अथवा उनकी दरकती कांग्रेस कर पाएगी, इसमें संदेह है। ऐसे में, यदि विपक्षी दलों को विभिन्न राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों में कुछ हासिल करना है तो उसे विपक्षी गठबन्धन के नेतृत्व परिवर्तन पर गंभीरता से विचार करना ही होगा।

डा. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़ (उप्र)

### सकारात्मक सोच आवश्यक

भारत और कनाडा के रिश्ते अब पहले से बेहतर हो रहे हैं। अब वैश्विक हालात में कनाडा को भारत की अहमियत समझ आने लगी है। बीते कुछ समय से कनाडा के साथ भारत के रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे हैं। अब कनाडा ने रिश्तों में मधुरता दिखाने के लिए एक सकारात्मक संदेश दिया है। कनाडा भारत के साथ सहयोग करके विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों मे निकटता बढ़ाना चाहता है। इस मामले में भारत हमेशा से ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। भारत को कनाडा से यूरेनियम का आयात बढ़ाने की उम्मीद भी की जा रही है साथ ही कच्चे तेल और अन्य ऊर्जा उत्पादों की खरीद सहित व्यापक रूप में निवेश भी बढ़ाया जाएगा। इन दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की जमीन पहले से ही मजबूत है। जिसका फायदा दोनों मुल्कों को मिलेगा। बहरहाल, कनाडा और भारत के संबंध अब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव दिल्ली

### संतों का राजनीति झुकाव गलत

कोई भी शंकराचार्य या साधु-संत का राजनीति की ओर झुकाव नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर समाज में एक न एक दिन उस महात्मा की किरकिरी अवश्य होती है और उन्हें अपयश का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही अपने को उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ (बद्रीनाथ) के शंकराचार्य कहने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हो रहा है। उन पर लगाए गए आरोप की सत्यता जांच के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल उनकी छवि श्रद्धालुओं के मन में बदल गई है। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। स्वामी और उनके शिष्यों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांगने और गोमांस के मुद्दे पर सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद यह विवाद बढ़ा, जिसे कुछ लोग राजनीति से प्रेरित मानते हैं। उन्हें शक की निगाहों से देखा जा रहा है, जिससे संतों का राजनीति से दूर रहने का महत्व उजागर होता है। उत्तर प्रदेश सरकार से टकराव की शुरुआत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज के माघ मेले में पालकी पर बैठकर स्नान करने की परंपरा का हवाला दिया, जिसे पुलिस ने नियमों का उल्लंघन बताकर रोका था। प्रयागराज माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से मेला प्रशासन का टकराव चर्चा में है। इस मामले ने तूल पकड़ते हुए राजनीतिक रंग ले लिया है।

-युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

## पोस्ट

अफगानिस्तान और पाकिस्तान रमजान के महीने में एक-दूसरे से जंग में जुटे हैं। उनका यह कृत्य कितना शांतिपूर्ण एवं कितना इस्लामिक है?

इम्तियाज महमूद@ImtiazMadmood

भारत में तमाम लोग गाजा में हो रही मौतों पर आंसू बहाते नहीं थकते, लेकिन वे भी पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के लोगों की हत्या पर मौन साधे हुए हैं।

अभिजीत अय्यर मित्रा@Iyervval

अगर मुख्यमंत्री होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल 156 दिन और उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया 530 दिनों तक जेल में रह सकते हैं और उसके बाद अदालत उन्हें राहत दे तो जरा आम आदमी की हालत के बारे में सोचिए।

प्रयाग@theprayagtiwari

एक समय केजरीवाल ने तमाम लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिन्हें वे कभी साबित नहीं कर पाए। अब एक मामले में अदालती राहत मिली तो वे भावुक होकर रोने लगे। उन्हें उन नेताओं के लिए भी रोना चाहिए, जिन पर उन्होंने आरोप लगाए थे। कर्मों का सारा हिसाब यहीं होता है। संजय निरुपम@sanjaynirupam

## जनपथ

सीबीआई छीलती रहती हरदम घास,
उसके आरोपित सभी हो जाते हैं पास।
हो जाते हैं पास चलेगी वर्षों खिट पिट,
दे देता है कोर्ट अंत में साफ क्लीनचिट!
हम भारत के लोग टैक्स भरते हैं भाई,
उसी टैक्स को खाय निकम्मी सीबीआई!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक- संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा -201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 225

## हुरियारे बने ठाकुर बांकेविहारी...

ठाकुर बांकेविहारी ने शुक्रवार को रंगभरनी एकादशी पर श्वेत वस्त्र धारण कर दर्शन दिए तो भक्त आल्हादित हो गए। इसी के साथ ठाकुर जी के आंगन में रंगों की होली शुरू हो गई। मंदिर का आंगन रंग और गुलाल की सतरंगी आभा से नहा उठा। सेवायतों ने ठाकुर जी के प्रतिनिधि के रूप में पिचकारी से श्रद्धालुओं पर रंगों की वर्षा की ● जागरण

# विवादित किताब व उससे जुड़े अंश को हटवाने के लिए मंत्रालयों से मांगी मदद

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली:** एनसीईआरटी की विवादित सामाजिक विज्ञान भाग दो की किताब व उससे जुड़े अंश को प्रतिबंधित करने व इंटरनेट प्लेटफार्म से हटवाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रालयों से भी मदद मांगी है। स्कूली शिक्षा सचिव ने सूचना एवं प्रसारण, संचार और इलेक्ट्रानिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर विवादित किताब व उससे जुड़े अंश को इंटरनेट मीडिया के सभी प्लेटफार्मों से तत्काल हटवाने के लिए कहा है।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा सचिव की ओर से भेजे गए इस पत्र में इन सभी मंत्रालयों के सचिवों से कहा गया है कि 27 फरवरी की रात तक इससे जुड़ी सारी सामग्री को इंटरनेट के सभी प्लेटफार्मों से तुरंत हटवा दें। मंत्रालय ने बताया कि विवादित किताब को एनसीईआरटी पहले ही अपने डिजिटल प्लेटफार्म से हटा चुकी है। बिक्री को भी प्रतिबंधित कर चुकी है। जो हार्ड कापी जारी की गई थी, उसे भी जब्त कर लिया गया है। बावजूद इसके इंटरनेट मीडिया पर जो तथ्य चल रहे है उन्हें खोजकर हटाने में वह सहयोग दें।

इस दौरान विवादित अंश से जुड़े हिस्से व उससे जुड़े रिफरेंस को भी तुरंत हटवाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालयों को लिखे पत्र के साथ शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कापी भी सभी को भेजी है। प्रेट्र के अनुसार, एनसीईआरटी ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि कक्षा आठ की प्रतिबंधित पाठ्यपुस्तक की प्रतियां रखने वाले सभी लोग इसे परिषद मुख्यालय में लौटा दें।

**शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनसीईआरटी की विवादित किताब और उसके अंश को हटवाने के लिए लिखा पत्र**

### जिम्मेदारों की होगी पहचान

एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी पाठ्यपुस्तकों की तैयारी की उस प्रक्रिया की जांच कर रहे हैं, जिसके कारण "निर्णय की त्रुटि" हुई है। सूत्रों ने बताया कि जिम्मेदार व्यक्तियों, प्रक्रियाओं की पहचान भी कर रहे हैं।

### कार्रवाई न होने को लेकर खड़े हो रहे हैं सवाल

**जाब्यू, नई दिल्ली:** एनसीइआरटी कमेटी की बैठक के मिनट्स से तत्काल इसका पता लग सकता है कि विवादित अध्याय जोड़ने के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार थे। सुप्रीम कोर्ट में जब मिनट्स रखे जाएंगे तो पूरी सच्चाई आ ही जाएगी लेकिन फिर भी किसी तरह की कार्रवाई न होने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच जो जानकारी सामने आई है, उनमें आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की विवादित किताब को लिखने वाली 15 सदस्यीय कोर टीम में आलोक प्रसन्नाकुमार नाम के कानूनविद् भी थे, जो विधि सेंटर फार लीगल पालिसी के सह-संस्थापक हैं। कानून से जुड़े विषयों के शोधकर्ता है। ज्यादा संभव है कि जिस विषयवस्तु को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, उसमें उनकी राय ली गई हो। यदि कुछ गलत जोड़ा जा रहा था तो उन्हें इसका विरोध भी करना था।

## एक नजर में

### बंगाल में 'परिवर्तन यात्रा' को हाई कोर्ट से सशर्त अनुमति

**कोलकाता:** बंगाल में भाजपा की प्रस्तावित 'परिवर्तन यात्रा' को कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सशर्त अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ ने स्पष्ट किया कि एक और दो मार्च को दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक यात्रा निकाली जा सकेगी, लेकिन एक हजार से अधिक की भीड़ नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण 24 परगना जिले के रायदिघी से यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। (राब्यू)

### पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में डाक्टर को मिली जमानत

**नई दिल्ली:** सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में आरोपित डा. अजय तावड़े को जमानत दे दी। पुणे में एक मोटरसाइकिल को पोर्श कार से टक्कर मारकर दो लोगों की जान लेने के आरोपित 17 वर्षीय किशोर के रक्त के नमूनों से छेड़छाड़ करने के आरोप में डा. तावड़े को गिरफ्तार किया गया था। (प्रेट्र)

### जयललिता के भरोसेमंद रहे पन्नीरसेल्वम द्रमुक में शामिल

**चेन्नई:** दिवंगत अन्नाद्रमुक प्रमुख जे जयललिता के करीबी और तीन बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके ओ पन्नीरसेल्वम ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) का दामन थाम लिया। वह पार्टी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में द्रमुक में शामिल हुए। पन्नीरसेल्वम के साथ उनके बेटे पी रविंद्रनाथ कुमार और समर्थक भी पार्टी में शामिल हुए। (प्रेट्र)

# रिफार्म एक्सप्रेस पर सवार है देश, इनोवेशन के साथ आगे आए उद्योग जगत : प्रधानमंत्री

## बजट बाद के वेबिनार में कहा- विदेशी निवेश के फ्रेमवर्क को बना रहे और सरल

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली :** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश रिफार्म एक्सप्रेस पर सवार है और इस गति को बनाए रखने के लिए केवल नीतिगत कंटेंट पर ध्यान नहीं देना होगा बल्कि उसकी बेहतर डिलीवरी पर फोकस करना होगा। रिफार्म का मूल्यांकन घोषणा से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर उसके प्रभाव से होना चाहिए। उन्होंने उद्योग जगत से कहा है कि वे नए निवेश और इनोवेशन के साथ आगे आएं।

बजट के बाद विकसित भारत के लिए सुधार व तकनीकी विषय पर आयोजित वेबिनार में मोदी ने कहा, हम विदेशी निवेश फ्रेमवर्क को और सरल बनाने जा रहे हैं। लंबे समय की वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बांड मार्केट को और ज्यादा सक्रिय बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। बांड की खरीद-बिक्री प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है।

मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक से सरकार सार्वजनिक पूंजीगत खर्च में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। 11 साल पहले पूंजीगत खर्च के लिए बजट में दो लाख रुपए का प्रविधान था जो मौजूदा बजट में बढ़कर 12 लाख करोड़ के पार हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश निजी सेक्टर के लिए स्पष्ट संकेत है। हमें निजी सेक्टर से इन्फ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा भागीदारी चाहिए। वित्तीय माडल में ज्यादा इनोवेशन चाहिए और उभरते हुए सेक्टर में मजबूत सहभागिता चाहिए।

वेबिनार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि बांड मार्केट के सुधार कार्यक्रम को लंबे समय के विकास के टूल के रूप में देखना होगा। हमें बांड मार्केट को लेकर अनुमान को सुनिश्चित करना होगा। नए-नए तरीके लाने होंगे और जोखिम का प्रभावी प्रबंधन करना होगा। तभी हम सतत रूप से विदेशी पूंजी को आकर्षित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि निजी सेक्टर को व्यावहारिक सोल्यूशन तैयार करने में मदद करनी होगी और बाजार के भरोसे को मजबूत करना होगा।

### मंत्रियों को रिफार्म पर एजेंडा तैयार करने को कहा

प्रेट्र के अनुसार प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से आगामी वर्षों में अपने-अपने मंत्रालयों में की जाने वाली पहलों के बारे में विस्तृत नोट तैयार करने को कहा है। मंत्रियों को निर्देश दिया गया था कि वे स्वयं नोट तैयार करें ताकि वे इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेश कर सकें और संबंधित मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों और सुधार के दृष्टिकोण के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे सकें। मंत्रियों को अपने-अपने मंत्रालयों के सुधार के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से बताना होगा, यह बताना होगा कि इसे कब लागू किया गया था या कब इसे लागू किया जा सकता है और इससे क्या परिणाम अपेक्षित हैं। प्रत्येक मंत्रालय को तुरंत अपनी सुधार प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि इसके परिणाम जमीनी स्तर पर दिखे। यह पूरी कवायद 2047 तक देश को विकसित बनाने के सरकार के व्यापक रोडमैप का हिस्सा है।

विकसित भारत के लिए सुधार व तकनीकी विषय पर आयोजित वेविनार को संबोधित करते पीएम● एएनआइ

### जब साथ आगे बढ़ते हैं तब आते हैं रिफार्म से परिणाम

मोदी ने कहा, जब सरकार, उद्योग जगत व नालेज पार्टनर साथ आगे बढ़ते हैं तब रिफार्म से परिणाम आते हैं। घोषणाएं जमीन पर उपलब्धि में तब्दील हो जाती हैं। उन्होंने स्पष्ट रिफार्म पार्टनरशिप चार्टर विकसित करने का सुझाव दिया जो सरकार, उद्योग, वित्तीय संस्था व विशेषज्ञों का साझा संकल्प हो। पीएम ने कहा कि आपकी भागीदारी से योजनाओं पर अमल करना और बेहतर होगा।

### हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा चंद्रशेखर आजाद का बलिदान: प्रधानमंत्री

**नई दिल्ली, एएनआइ :** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि मातृभूमि के लिए उनका बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी, 1931 को देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जीवन बताता है कि अन्याय के खिलाफ अडिग रहने का संकल्प ही सच्चा पराक्रम है।

# शाह बोले- एसआइआर भी बनेगा घुसपैठियों की पहचान का आधार

- सीमांचल प्रवास के अंतिम दिन गृह मंत्री ने सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक
- मतदाता सूची से हटे लोगों की पहचान और वर्तमान स्थिति की होगी जांच, घर-घर होगा सर्वे

**जागरण संवाददाता, पूर्णिया :** बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुआ एसआइआर अब घुसपैठियों की पहचान का अहम आधार बनेगा। सीमावर्ती जिलों के साथ-साथ पूरे बिहार में जनसांख्यिकीय बदलाव की गहराई से जांच की जाएगी। इसके तहत 1951-52 से लेकर 2011 तक के बसाव और जनसांख्यिकीय बदलाव के साथ उनके कारणों का विस्तार से विश्लेषण होगा। इस मुद्दे पर सभी जिलों के अधिकारी अब एक्शन मोड में रहेंगे। केंद्र व राज्य सरकार मिलकर काम करेगी।

तीन दिवसीय सीमांचल प्रवास के अंतिम दिन शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्णिया प्रमंडल के चारों जिलों के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की हुई बैठक में इस बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सूत्रों के मुताबिक शाह ने अधिकारियों से पूछा कि आखिर एसआइआर के दौरान मतदाता सूची से विलोपित हुए लोग कौन थे और अब कहां हैं। कहा, इसकी पड़ताल बेहद जरूरी है। तय हुआ कि विधानसभा चुनाव से पहले हुए एसआइआर के आधार पर दर्ज मृत्यु के मामलों का विधिसम्मत व विस्तृत सत्यापन कराया जाएगा। पुष्टि होने पर यूआइडी डाटाबेस, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सहित अन्य सरकारी दस्तावेज को हटाया जाएगा या उन्हें अपडेट किया जाएगा, ताकि रिकार्ड की शुद्धता बनी रहे। साथ ही सत्यापन के दौरान अनुपस्थित पाए गए प्रवासित व्यक्तियों की पुष्टि के लिए घर-घर सर्वे कराया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से न हटे। भारत-नेपाल सीमा से सटे बिहार के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर सख्ती बढ़ाने के लिए सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है।

बिहार के पूर्णिया में बैठक में मौजूद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी व अन्य● जागरण

### न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण पर बंगाल सरकार की आपत्ति खारिज

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली :** बंगाल एसआइआर में दावों और जांच के लिए नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा प्रशिक्षण देने पर बंगाल सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दीं। कहा, न्यायिक अधिकारियों को काम करने दें, वे स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। शीर्ष अदालत ने आपत्तियों को दरकिनार करते हुए मौखिक टिप्पणियों में यह भी कहा कि प्रक्रिया को समझने के लिए अगर चुनाव आयोग उन्हें प्रशिक्षित नहीं करेगा तो कौन करेगा। ये टिप्पणियां प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने उस समय कीं जब बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुबह अदालत शुरू होते ही बंगाल एसआइआर में नियुक्त न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण माड्यूल पर सवाल उठाते हुए उन्हें प्रशिक्षण देने पर आपत्ति व्यक्त की।

# संसद को कानून बनाने का अधिकार, केंद्र के शपथपत्र से बाध्य नहीं : कोर्ट

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि संसद के पास कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है और वह केंद्र सरकार द्वारा अदालत में दिए गए किसी भी शपथपत्र से बाध्य नहीं है। यह टिप्पणी चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने की।

यह पीठ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। यह धारा देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने से जुड़ी है। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि धारा 152 पूर्व की भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (देशद्रोह) को फिर से प्रस्तुत करती है। मई, 2022 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने उचित सरकारी फोरम द्वारा देशद्रोह कानून को परखे जाने तक इस पर रोक लगा दी थी और केंद्र व राज्यों को देशद्रोह के लिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया था। वकील ने शुक्रवार को बताया कि 2022 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दिया था कि वह देशद्रोह कानून की समीक्षा करेगी। सरकार बीएनएस में इस प्रविधान को फिर से प्रस्तुत नहीं कर सकती। पीठ ने कहा, 'केंद्र ने भले शपथपत्र दिया हो सकता है, लेकिन संसद इससे बाध्य नहीं है। उसके पास कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है।' शीर्ष अदालत होली की छुट्टी के बाद मामले में सुनवाई करेगी।

- देशद्रोह से जुड़ी बीएनएस की धारा 152 के मामले में टिप्पणी
- याचिकाओं में इस धारा की वैधता पर उठाए गए हैं सवाल

# भारत-पाक सीमा पर राष्ट्रपति मुर्मु ने भरी उड़ान

**जागरण संवाददाता, जैसलमेर:** देश की राष्ट्रपति एवं सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को इतिहास रचते हुए स्वदेशी लाइट कांबैट हेलिकाप्टर प्रचंड में बतौर को-पायलट उड़ान भरी। वे इस लड़ाकू हेलिकाप्टर में को-पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। आलिव ग्रीन फ्लाइंग सूट व हेलमेट पहने राष्ट्रपति ने उड़ान से पहले पायलट से ब्रीफिंग ली। उड़ान के दौरान सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति ने काकपिट से देशवासियों को संदेश दिया। कहा कि प्रचंड आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रतीक है।

राष्ट्रपति भारतीय वायु सेवा के युद्ध अभ्यास वायु शक्ति में बतौर मुख्य अतिथि जैसलमेर पहुंची थी। राष्ट्रपति ने शुक्रवार सवेरे जैसलमेर वायु सेवा स्टेशन पहुंचने के बाद अधिकारियों से प्रचंड हेलिकाप्टर की क्षमताओं और मिशन प्रोफाइल के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद वे पायलट यूनिफार्म में काकपिट में बैठीं और ग्रुप कैप्टन एन. एस. बहुआ के साथ उड़ान भरी। हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इस आधुनिक कांबैट हेलिकाप्टर में उन्होंने देश की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज तथा परमाणु परीक्षण स्थल का हवाई मुआयना किया। उड़ान के दौरान राष्ट्रपति ने हेलिकाप्टर से सैल्यूट कर जवानों और अधिकारियों का अभिवादन स्वीकार किया। उनके साथ दूसरे हेलिकाप्टर में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी मौजूद रहे।

जैसलमेर में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टर 'प्रचंड' में उड़ान भरने से पूर्व राष्ट्रपति मुर्मु● एएनआइ

# 'तमिलनाडु में एक चरण में चुनाव कराने के सुझाव पर होगा विचार'

**चेन्नई, प्रेट्र:** मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु में राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराने का सुझाव दिया है, सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ पता चल जाएगा कि चुनाव कितने चरण में होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव बिहार के चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करने का रिकार्ड बनाएगा।

तमिलनाडु में हाल में संपन्न मतदाता सूची के एसआइआर का उल्लेख करते हुए ज्ञानेश कुमार ने इसे देश के लिए एक आदर्श और बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि एसआइआर का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि कोई भी योग्य व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अयोग्य व्यक्ति उसमें शामिल न हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य के 75 हजार मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। नई पहलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि ईवीएम की गिनती से पहले दो दौर में डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दक्षिण भारत में प्रचलित रही 'कुदावोलाई' व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि तमिलनाडु का लोकतंत्र के लिहाज से गौरवशाली अतीत रहा है। 'कुदावोलाई' का शाब्दिक अर्थ मतदान पात्र होता है। दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में 10वीं सदी में चोल साम्राज्य के दौरान घड़े में मतपत्र डालकर मतदान की यह प्रथा प्रचलित थी।

चेन्नई में शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार● प्रेट्र

# 2035 तक बड़ी ताकत बनेगी नौसेना, 200 से ज्यादा युद्धपोत होंगे

- नौसेना प्रमुख बोले- 2047 तक पूर्ण आत्मनिर्भर समुद्री शक्ति बनने की दिशा में तेजी
- आइएनएस अंजदीप को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया, इस वर्ष 15 जहाज होंगे शामिल

**चेन्नई, प्रेट्र :** भारतीय नौसेना ने वर्ष 2035 तक 200 से अधिक युद्धपोतों वाली समुद्री शक्ति बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने शुक्रवार को चेन्नई बंदरगाह पर आइएनएस अंजदीप के कमीशनिंग समारोह के बाद यह जानकारी दी। कहा कि नौसेना 2026 में लगभग 15 नए जहाज शामिल करने की तैयारी कर रही है, जो अब तक की सबसे तेज इंडक्शन दर होगी। इसके अलावा देशभर के शिपयार्ड में 50 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है।

77 मीटर लंबा युद्धपोत 'आइएनएस अंजदीप' उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने, उनका पीछा करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिसके कारण इसे "डाल्फिन हंटर" कहा जा रहा है। यह पोत तटीय निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान तथा खोज एवं बचाव अभियानों में भी सक्षम है और भारत की तटीय सुरक्षा व अंडर-सी युद्ध क्षमता को मजबूत करेगा। एडमिरल त्रिपाठी ने बताया कि नौसेना का दीर्घकालिक लक्ष्य जहाज निर्माण में पुर्जों के स्तर तक आत्मनिर्भरता हासिल करना व वर्ष 2047 तक पूर्णतः आत्मनिर्भर बल के रूप में विकसित होना है।

आइएनएस अंजदीप को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किए जाने के अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी (दाएं से तीसरे) व अन्य अधिकारी● पीआइबी

### अंजदीप की प्रमुख विशेषताएं

- 77 मीटर लंबा पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत, डाल्फिन हंटर के रूप में डिजाइन
- 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित, आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
- दुश्मन पनडुब्बियों की पहचान, ट्रैकिंग, निष्क्रिय करने में सक्षम
- स्वदेशी 'अभय' हल-माउंटेड सोनार से लैस
- हल्के टारपीडो और एंटी-सबमरीन राकेट प्रणाली से सुसज्जित
- उन्नत कांबैट मैनेजमेंट सिस्टम से एकीकृत युद्ध संचालन क्षमता

# एस-400 से सैन्य इतिहास में सबसे अधिक दूरी पर लक्ष्य को बनाया निशाना

**जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली:** भारतीय वायुसेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें लंबी दूरी की वायुरक्षा मिसाइल प्रणाली एस-400 सुदर्शन चक्र को कार्रवाई करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में रडार काफी दूर हवा में मौजूद लक्ष्य का पता लगाती है। फिर मिसाइल लांच होती है और लंबी दूरी पर उस लक्ष्य को नष्ट कर देती है। इस वीडियो पर वायुसेना ने लिखा, "सैन्य इतिहास में अब तक का सबसे अधिक दूरी का लक्ष्य भेदन।" साथ ही लिखा, "दुश्मन नजर से दूर हो सकता है, लेकिन पहुंच से बाहर कभी नहीं।"

वायुसेना ने यह वीडियो शुक्रवार को राजस्थान के पोखरण में सैन्य अभ्यास 'वायु शक्ति-2026' से पहले जारी किया। वीडियो में आपरेशन सिंदूर का भी जिक्र है। वायुसेना अधिकारियों का कहना है कि एस-400 ने उस आपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी और इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी इलाके में लगभग 300 किलोमीटर अंदर एक लक्ष्य पर हमला करने के लिए किया गया था। इसका संचालन वायुसेना करती है। इसे हवाई खतरों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें युद्धक विमान, निगरानी विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं।

'वायु शक्ति' सैन्य अभ्यास के दौरान वायुरक्षा मिसाइल प्रणाली एस-400 से निकलती मिसाइल● वीडियोग्रैब

# डीआरडीओ ने किए शार्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के तीन सफल परीक्षण

**जासं, बालेश्वर:** डीआरडीओ ने शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर में शार्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम (वीएसएचओआरएडीएस) के लगातार तीन सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल सिस्टम को खासतौर पर कम दूरी से आने वाले हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इसने हाई-स्पीड से आ रहे टारगेट को बीच हवा में ही रोककर पूरी तरह तबाह कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शार्ट रेंज रक्षा प्रणाली के सफल परीक्षण पर सेना, डीआरडीओ व इसके निर्माण से जुड़ी एजेंसियों व विज्ञानियों को बधाई दी है। चांदीपुर में हुए परीक्षण का मकसद मिसाइल की क्षमता को दोबारा परखना था। परीक्षण में हाई-स्पीड वाले ऐसे टारगेट इस्तेमाल किए गए जो दुश्मन के फाइटर जेट्स की नकल कर रहे थे। मिसाइल ने अलग-अलग स्पीड, रेंज और ऊंचाई पर उड़ रहे इन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक मार गिराया। परीक्षण के दौरान रक्षा मानकों पर यह प्रणाली खरी उतरी।

### इस प्रकार है खासियत

- वीएसएचओआरएडीएस को सैनिक आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और फायर कर सकते हैं।
- यह सिस्टम भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- दुर्गम पहाड़ी इलाकों या सीमा की अग्रिम चौकियों पर इसे तैनात करना बहुत आसान होगा।
- यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों को आसानी से नष्ट करने में सक्षम है।

चिंतन

# हाई-प्रोफाइल मामलों में सीबीआई जांच पर सवाल

कूटनीति
अरविंद जयतिलक

हाई-प्रोफाइल मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका हमेशा से जनचर्चा और राजनीतिक बहस का केंद्र रही है। जब जांच किसी मौजूदा या पूर्व मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर रहे व्यक्तियों के खिलाफ हो, तब जांच एजेंसी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में हर कदम कानून की कसौटी पर परखा जाता है और जरा सी चूक एजेंसी की साख पर गहरा असर डाल सकती है। हालिया फैसलों ने एक बार फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी किया जाना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने यह कहते हुए आरोप तय करने से इनकार कर दिया कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त और ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। अदालत की टिप्पणी कि साजिश का सिद्धांत अनुमान पर आधारित था, जांच एजेंसी की तैयारी और तथ्यों के संकलन पर सीधा प्रश्नचिह्न लगाती है। सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, किंतु निचली अदालत में मिली इस असफलता ने उसकी पेशेवर विश्वसनीयता को चुनौती दी है। इसी तरह, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व हरियाणा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को पंचकूला प्लॉट पुनः आवंटन मामले में बड़ी राहत देते हुए सीबीआई के आरोपों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया अपराध का मामला नहीं बनता और आगे की कार्रवाई अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी। यह टिप्पणी न केवल मामले की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करती है, बल्कि जांच एजेंसी की विवेचना पद्धति पर भी सवाल खड़े करती है। इन दोनों मामलों की पृष्ठभूमि और राजनीतिक संदर्भ भिन्न हो सकते हैं, लेकिन एक समान तत्व उभरकर सामने आता है हाई-प्रोफाइल मामलों में जांच की गुणवत्ता और निष्पक्षता को लेकर संदेह। जब किसी मामले में 20 से अधिक आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है और अदालत आरोप तय करने से ही इनकार कर देती है तो यह केवल तकनीकी चूक नहीं मानी जा सकती। यह संकेत है कि या तो सबूतों का पर्याप्त परीक्षण नहीं हुआ या फिर जांच की दिशा ही कमजोर आधार पर खड़ी थी। किसी भी मुख्यमंत्री चाहे वह सत्तारूढ़ दल से हो या विपक्ष से, गिरफ्तारी अत्यंत गंभीर कदम है। यह कदम तभी उठाया जाना चाहिए, जब जांच एजेंसी के पास पुख्ता और अदालत में टिक सकने वाले प्रमाण हों। अन्यथा, गिरफ्तारी स्वयं में राजनीतिक विवाद का कारण बन जाती है और एजेंसी की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं। हाई-प्रोफाइल मामलों में विफलता का एक और आयाम है राजनीतिक ध्रुवीकरण। जब अदालतें आरोपों को खारिज करती हैं, तो विपक्ष को यह कहने का अवसर मिल जाता है कि जांच राजनीतिक प्रेरणा से की गई थी। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ पक्ष एजेंसी की कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बताता है। इस खींचतान में सबसे अधिक क्षति न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसी की साख को होती है। सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह पेशेवर दक्षता, पारदर्शिता और कानूनी मजबूती के साथ काम करे। जांच अधिकारियों के प्रशिक्षण, साक्ष्य संकलन की वैज्ञानिक पद्धति और अभियोजन पक्ष के साथ बेहतर समन्वय जैसे पहलुओं पर गंभीरता से ध्यान देना होगा।

# भारत-इजराइल संबंधों का सुनहरा अध्याय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा न सिर्फ दोनों देशों के ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंधों में मिठास घोलने वाली है बल्कि इस यात्रा के ढेर सारे कूटनीतिक, रणनीतिक और सामरिक मायने भी हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मजबूत रिश्ते की पैरोकारी करते हुए आपसी कारोबार व सामरिक लक्ष्य को हासिल करने के निमित्त तकनीक एआई, स्टार्ट अप, क्रिटिकल और इमरजिंग टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इकोनॉमी, कृषि और अनुसंधान समेत कुल 16 करारों और सहमति पत्रों पर मुहर लगाई है।

दोनों देशों ने विज्ञान और तकनीक पर मौजूद जॉइंट कमिशन को मंत्रीस्तरीय दर्जे तक ले जाने के निर्णय के साथ ही भारत में इजराइल की मदद से चल रहे 43 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विस्तार देकर 100 करने पर भी हामी भरी है। इजराइल की मदद से भारत में एग्रीकल्चर इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना का भी निर्णय लिया है। दोनों देश एफटीए यानि (मुक्त व्यापार समझौता) पर आगे बढ़ते हुए दूसरे दौर की बातचीत मई माह में करने जा रहे हैं। इस यात्रा में पहले दौर की बातचीत का चरण पूरा हो चुका है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों ने एफटीए के टर्म्स और रेफरेंस को लेकर गत वर्ष नवंबर माह में हस्ताक्षर कर चुके हैं। गौर करें तो दोनों देशों का आपसी कारोबार वित्त वर्ष 2024-25 में तकरीबन 3.62 बिलियन डॉलर का था और अब अगर एफटीए मूर्त रूप लेता है तो दोनों देशों के कारोबार में कई गुना वृद्धि होगी। अच्छी बात है कि अब भारत का यूपीआइ पेमेंट सिस्टम इजराइल में भी चलेगा। दोनों देशों के बीच भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमइसी) और आईटूयूटू (भारत-इजराइल-यूएई-अमेरिका समूह) के तहत सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा है कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति और स्थिरता भारत के हित जुड़े हैं इसलिए हम आतंकवाद और इसके समर्थकों का विरोध करते रहेंगे।

दोनों देशों ने बढ़ते कट्टरपंथ और आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी कंधा जोड़ने की जरूरत पर बल दिया है। गौर करें तो 2018 और उससे पहले 2002 में दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय समझौते को आकार देते हुए आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्यदल का गठन किया था। आज वह कार्यबल, सूचनाओं के आदान-प्रदान से लेकर आतंकवाद की भयावहता से निपटने की तकनीक को सीखने में भरपूर मददगार साबित हो रहा है। बहरहाल आतंकवाद से जूझ रहे इन दोनों देशों की परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं, लेकिन समस्या एक जैसी है। जहां भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित है, वहीं इजराइल सीमा पार से फिलिस्तीन में डेरा जमाए आतंकी संगठन फतह और हमास से जूझ रहा है। अब दोनों देश मिलकर आतंक के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में एक मंच पर हैं। यहां ध्यान देना होगा कि अभी तक इजराइल से भारत की अति निकटता को दोधारी तलवार सरीखा माना जाता था।

यह कारण गिनाया जाता था कि चूंकि इजराइल और ईरान एक-दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लिहाजा भारत को इजराइल से संबंध जोड़ने के मामले में फूंककर कदम रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल

यात्रा और बेंजामिन नेतान्याहू की भारत यात्रा ने इस मिथक को तोड़ दिया है। दोनों देश तेजी से एक-दूसरे के निकट आ रहे हैं। हालांकि भारत की घरेलू राजनीति में कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम वोटयुक्ति के लिए नेतान्याहू और मोदी की युगलबंदी पर लगातार तंज कसते रहे हैं ,लेकिन आम जनमानस दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते रिश्ते से खुश है। किसी से छिपा नहीं है कि भारत के अधिकांश राजनीतिक दल फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल के निकट जाकर मुसलमानों की नाराजगी मोल लेने से बचते हैं। गौर करें तो प्रधानमंत्री मोदी से पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल जाने की जहमत नहीं उठायी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतान्याहू ने पूर्वाग्रह के खोल से बाहर निकलकर भारत-इजराइल संबंधों को परवान चढ़ाया है। यहां ध्यान देना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान की भी यात्रा कर उसे भरोसा दे चुके हैं कि इजराइल से उसकी दोस्ती उसकी कीमत पर नहीं होगी। बदलते कूटनीतिक परिदृश्य में ईरान भी भारत की रणनीतिक सोच से अच्छी तरह अवगत है। उसका भारत पर विश्वास का ही नतीजा है कि वह चाबहार समझौते के लिए तैयार हुआ, जिसके जरिए भारत को चीन व पाकिस्तान पर नकेल कसने में मदद मिल रही है। गौर करें तो भारत-इजराइल दोनों देश उपनिवेशवाद के परवर्ती युग की उपज हैं और आज की तारीख में दोनों ही अपने शत्रुभाव रखने वाले पड़ोसी देशों से पीड़ित हैं। ऐसे में अगर दोनों देश प्रतिरक्षा और आर्थिक संबंधों को गति देते हैं तो निःसंदेह यह दोनों देशों के हित में होगा। गौर करें तो भारत और इजराइल के बीच प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।

भारत इजराइली हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत रक्षा हार्डवेयर के आयात में विश्व के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, जबकि इजराइल इसका एक प्रमुख निर्यातक है। आज इजराइल ने उच्च तकनीक वाले रक्षा उपकरणों के आपूर्तिकर्ता के रूप में स्वयं को एक बड़े विकल्प के रूप में उभार लिया है। यहां ध्यान देना होगा कि इजराइल जिसकी अर्थव्यवस्था फिलिस्तीन युद्ध के कारण डांवाडोल होती रही है, को भी भारत के रूप में रक्षा उपकरणों के लिए एक बड़ा बाजार चाहिए। यही वजह है कि भारत के प्रति इजराइल की दिलचस्पी बनी हुई है। प्रतिरक्षा के अलावा व्यापार-कारोबार के क्षेत्र में भी दोनों देश नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। इजराइल भारत में निवेश करने वाले शीर्ष देशों में शुमार है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच इजराइल से 334.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ। इजराइल को कृषि विकास के क्षेत्र में महारत हासिल है।

दोनों देशों द्वारा औद्योगिक व प्रौद्योगिकी नवोन्मेश कोश के लिए आधी-आधी राशि का भुगतान, गंगा की सफाई, जल संरक्षण, परमाणु घड़ी के लिए सहयोग, जीईओ-एलईओ ऑप्टिकल लिंक, नैनो सेटलाइट को ऊर्जा इत्यादि पर भी तेजी से काम चल रहा है। भारत में निजी क्षेत्र ने भी इजराइली तकनीक में दिलचस्पी दिखायी है तथा बागवानी एवं सिंचाई के क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई प्रणाली के उत्पादन के लिए टीवीएस का गठन किया गया है। फिलहाल दोनों देश आयात-निर्यात संतुलन को लेकर भी संजीदा हैं ताकि दोनों को कारोबार का समान लाभ मिले। भारत इजराइल को जेवरात, दवाइयां, औषधीय सामग्रियां, सूती धागे, वस्त्र, प्लास्टिक तथा लाइनोलियम इत्यादि निर्यात करता है। वहीं, इजराइल से मोती, कीमती पत्थर इत्यादि आयात करता है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदा यात्रा से अब दोनों देशों के प्रतिरक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी तथा दोनों देश आतंकवाद और दहशतगर्दी के खिलाफ हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा न सिर्फ दोनों देशों के ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंधों में मिठास घोलने वाली है बल्कि इस यात्रा के ढेर सारे कूटनीतिक, रणनीतिक और सामरिक मायने भी हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मजबूत रिश्ते की पैरोकारी करते हुए आपसी कारोबार व सामरिक लक्ष्य को हासिल करने के निमित्त तकनीक एआई, स्टार्ट अप, क्रिटिकल और इमरजिंग टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इकोनॉमी, कृषि और अनुसंधान समेत कुल 16 करारों और सहमति पत्रों पर मुहर लगाई है। अब दोनों देशों के प्रतिरक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी तथा दोनों देश आतंकवाद और दहशतगर्दी के खिलाफ हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

विवादित पाठ
प्रमोद भार्गव

# न्यायपालिका के साथ विधायिका व कार्यपालिका भी जवाबदेह बनें

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) की पाठ्य पुस्तकों में धर्म, इतिहास और प्राचीन भारतीय विज्ञान व ज्ञान परंपरा से संबंधित यदि कोई पाठ जोड़ा जाता है, तो वह अक्सर विवाद का कारण बनता है। यहां तक कि लोकसभा में हंगामा होता है और बदली गई पाठों वाली पुस्तकें जलाई जाती हैं। अब एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में एक नया पाठ जोड़कर 'आ बैल मुझे मार' वाली कहावत को चरितार्थ कर किया है। इस पाठ के जरिए अब विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम उम्र से ही न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और लंबित मामलों के साथ-साथ वास्तविक चुनौतियों से भी परिचित कराया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की अदालतों में खूब भ्रष्टाचार है। कुछ समय पहले ही एक न्यायाधीश के निवास पर करोड़ों रुपये मिलने के बाद उन पर महाभियोग चलाने की बात भी उठी थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में है। शायद इसीलिए इस पाठ में जवाबदेही के साथ महाभियोग प्रक्रिया का भी ज्ञान दिया गया है। क्या इससे भी बदतर स्थिति कार्यपालिका और विधायिका में नहीं है? यदि इस पाठ में संविधान के इन स्तंभों को भी जोड़ दिया जाता तो शायद यह पहल निर्विवादित रहती? लेकिन ऐसा न करके एनसीईआरटी में बेवजह एक नए विवाद को आमंत्रित कर दिया है। हालांकि, वकीलों द्वारा आपत्ति जताई जाने और सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में ले लिए जाने के बाद इस पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। न्यायपालिका ने इसे न्यायपालिका को सुनियोजित ढंग से बदनाम करने की साजिश माना है। न्यायालयों में पर्याप्त भ्रष्टाचार है, लेकिन बिना किसी साक्ष्य के उस पर बात करना उचित नहीं है। जहां तक न्यायालयों में लंबित मुकदमों और न्यायाधीशों की कमी की बात है तो अदालतें स्वयं ही आंकड़े प्रस्तुत करती रहती हैं। इन कमियों को सामने लाना न्यायपालिका की पारदर्शिता को जताता है। विधायिका में तो कई सांसद और विधायक सदन में सवाल पूछने की रिश्वत लेते समाचार चैनलों द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए हैं। ऐसे में यदि कार्यपालिका और विधायिका को भी इस पाठ में सम्मिलित कर दिया जाता तो विद्यार्थियों को यह पता चलता कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ भ्रष्टाचार से किस हद तक प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह पंचायत पदाधिकारियों और राजस्व मामलों का निराकरण राजस्व न्यायालयों में न होने के कारण न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और बिजली बिलों का विभाग स्तर पर नहीं निपटना भी अदालतों पर बोझ बढ़ा रहे हैं। कई प्रांतों के भू-राजस्व कानून विसंगतिपूर्ण हैं। इनमें नाजायज कब्जे को वैध ठहराने के उपाय हैं। जबकि जिस व्यक्ति के पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं, वह भटकता रहता है। इन विसंगतिपूर्ण धाराओं का विलोपीकरण करके अवैध कब्जों से संबंधित मामलों से निजात पाई जा सकती है, लेकिन नौकरशाही ऐसे कानूनों का वजूद बने रहना चाहती है, क्योंकि इनके बने रहने पर ही इनके रौब-रुतबा और पौ-बारह सुनिश्चित हैं। अलबत्ता आज भी ब्रिटिश परंपरा के अनुसार अनेक न्यायाधीष ग्रीष्म ऋतु में छुट्टियों पर चले जाते हैं। सरकारी नौकरियों में जब से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हुआ है, तब से हरेक विभाग में महिलाकर्मियों की संख्या बढ़ी है। इन महिलाओं को 26 माह के प्रसूति अवकाश के साथ दो बच्चों की 18 साल की उम्र तक के लिए दो वर्ष का 'बाल सुरक्षा अवकाश' भी दिया जाता है। अदालत से लेकर अन्य सरकारी विभागों में मामलों के लंबित होने में ये अवकाश एक बड़ा कारण बन रहे हैं। इधर, कुछ समय से लोगों के मन में यह भ्रम भी पैठ कर गया है कि न्यायपालिका से डंडा चलवाकर विधायिका और कार्यपालिका से छोटे से छोटा काम भी कराया जा सकता है। इस कारण न्यायालयों में जनहित याचिकाएं बढ़ रही हैं, जो न्यायालय के बुनियादी कामों को प्रभावित कर रही हैं। सरकारी नौकरी में आर्थिक सुरक्षा और प्रतिष्ठा निर्मित हो जाने से बौद्धिक योग्यता और पद प्रतिष्ठा की एक नई संस्कृति पनपी है। यदि कोई युवक या युवती सिविल जज बन जाता है, तो वे सिविज जज से ही शादी करने लग गए हैं। शादी के बाद दपंत्ति की अलग-अलग जगह पदस्थापना इन्हें मिलने में रोड़ा बनती है, अतएव ये लोग किसी न किसी बहाने छुट्टी लेकर एक-दूसरे से मिलने चले जाते हैं। ये नई संस्कृति अदालतों में काम का बोझ बढ़ाने का नया कारण बन गई है। अतएव, इस तरह के बिंदु नए पाठ में शामिल कर दिए जाते तो विद्यार्थियों को अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार और मुकदमों की बढ़ती संख्या की व्यापक जानकारी मिलती।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

# निंदा का परित्याग

संकलित
दर्शन

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में निर्वहन के लिए व्यक्ति के सामाजिक गुणों का अत्यंत महत्व है। गुणी व्यक्ति को प्रत्येक जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। संसार के प्रत्येक प्राणी में कुछ गुण तो कुछ अवगुण पाए जाते हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो दूसरे के अवगुणों को ही देखते हैं। वे किसी भी सकारात्मक पक्ष में नकारात्मकता देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। प्रायः ऐसे लोगों में निंदा की प्रवृत्ति पाई जाती है। वे ऐसा करके खुद को समाज में श्रेष्ठ एवं दूसरे को नीचा साबित करना चाहते हैं। निंदा एक नशे की भांति है, जो एक बार इसका आदी हो गया, वह दिन-प्रतिदिन इसके पाश में जकड़ता चला जाता है। मनीषियों ने निंदा को दुर्व्यसन के समान माना है, जो निंदा करने वाले व्यक्ति को अंदर ही अंदर नैतिक रूप से समाप्त करती रहती है। एक बार एक आचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। शिक्षा प्राप्ति के दौरान एक शिष्य अन्य शिष्यों की ओर संकेत करते हुए आचार्य से कहने लगा कि 'वे अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों को कार्य करना ही नहीं आता।' आचार्य बोले, 'तुमको छोड़ अन्य सारे शिष्य सही से कार्य कर रहे हैं।' इस पर शिष्य असहज हो गया। उसने आचार्य से पूछा, 'वह कैसे?' आचार्य बोले, 'क्योंकि वे लोग अपने कार्य में संलग्न हैं, किंतु तुम अपने कार्य पर ध्यान न देकर, दूसरों के कार्य की निंदा करने में अपने समय की बर्बादी कर रहे हो।'

# जरूरतमंदों की मदद ही सबसे बड़ी सेवा

संकलित
प्रेरणा

एक वैद्य गुरु गोविंद सिंह के दर्शन के लिए आनन्दपुर गया। वहां गुरुजी से मिलने पर उन्होंने कहा कि जाओ और जरूरतमंदों को सेवा करो। वापस आकर वह रोगियों की सेवा में जुट गया। शीघ्र ही वह पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। एक बार गुरु गोविंद सिंह स्वयं उसके घर पर आए। वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन गुरुजी ने कहा कि वे कुछ देर ही ठहरेंगे। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आया और बोला- वैद्य जी, मेरी पत्नी की तबियत बहुत खराब है। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। वैद्य जी असमंजस में पड़ गए। एक ओर गुरु थे, जो पहली बार उनके घर आए थे। दूसरी ओर एक जरूरतमंद रोगी था। अंततः वैद्यजी ने कर्म को प्रधानता दी और इलाज के लिए चले गए। लगभग दो घण्टे के इलाज और देखभाल के बाद रोगी की हालत में सुधार हुआ। तब वे वहाँ से चले, उदास मन से उन्होंने सोचा कि गुरुजी के पास समय नहीं था। अबतक तो वे चले गए होंगे फिरभी वैद्यजी भागते हुए वापस घर पहुँचे। घर पहुँचकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। गुरुजी बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वैद्यजी उनके चरणों पर गिर पड़े। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा- तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। सबसे बड़ी सेवा जरूरतमंदों की मदद करना है।

## अंतर्मन

## आज की पाती

### बदलता मौसम और अनिश्चित भविष्य

फरवरी का महीना कभी सर्द हवाओं, हल्की धूप और पहाड़ों पर जमी बर्फ के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर चल रहा है। कश्मीर घाटी, जिसे बर्फ और ठंड की धरती माना जाता है, वहां अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह फरवरी के इतिहास में असामान्य माना जा रहा है। 24 फरवरी 2016 को 20.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था, लेकिन इस वर्ष उससे भी अधिक गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। श्रीनगर के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डा. मुख्तार अहमद के अनुसार इस बार कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ, जिससे सामान्य शीतकालीन वर्षा और बर्फबारी नहीं हो सकी। यह केवल एक मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि वायुमंडलीय असंतुलन का संकेत है।

-परेश कौशिक, रायपुर

## ट्रेंड

### पुण्यतिथि पर नमन

संघ से लेकर भाजपा तक, राष्ट्रसेवा व समाज-कल्याण के लिए समर्पित 'भारत रत्न' नानाजी देशमुख ने ग्रामोदय को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा के आजीवन पथप्रदर्शक रहे। नानाजी देशमुख को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं।

- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

### शांतिपूर्ण विरोध 'अपराध'

आज भारत में कंप्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना सबसे बड़ा "अपराध" बना दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे-धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है, जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है।

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

### जनविश्वास का प्रतिबिंब

हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पिछले एक साल में दिल्ली के लिए किए गए कार्यों का लेखा-जोखा है और विकसित दिल्ली का रोडमैप भी है। यह उत्तर-पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में हुए ठोस कार्यों, बुनियादी सुविधाओं, बढ़ते जनविश्वास का प्रतिबिंब है।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

### कट्टर ईमानदार

एक बार फिर डा. आम्बेडकर की दूरदर्शी सोच और उनके बनाए संविधान पर फख्र महसूस हो रहा है। बीजेपी व सारी एजेंसियों की हमें बेईमान साबित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज साबित हो गया कि केजरीवाल-सिसोदिया कट्टर ईमानदार है।

- मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री, आप

## करंट अफेयर

# चीन में विधायिका के 19 सदस्य बर्खास्त किए गए

चीन की विधायिका ने अपनी वार्षिक बैठक शुरू होने से एक सप्ताह पहले 19 सदस्यों को बर्खास्त कर दिया है, जिनमें नौ सैन्य अधिकारी शामिल हैं। देर बृहस्पतिवार की गई इस घोषणा में यह नहीं बताया गया कि इस सदस्यों को क्यों हटाया गया है, लेकिन आमतौर पर इस तरह की कार्रवाई को भ्रष्टाचार संबंधी जांच से जोड़कर देखा जाता है। चीन के नेता शी चिनफिंग द्वारा शुरू किया गया भ्रष्टाचार रोधी अभियान एक दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा है। हाल के वर्षों में इस अभियान के दायरे में सेना भी आयी है। ऐसे में पिछले महीने सेना के शीर्ष जनरल को हटाए जाने की कार्रवाई भी इसी क्रम का हिस्सा मानी जा रही है, जब शी सशस्त्र बलों में सुधार और आधुनिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। शी चिनफिंग 14 साल से सत्ता में हैं और विश्लेषकों का कहना है कि यह अभियान संभावित प्रतिद्वंद्वियों को हटाने और अपने अधीनस्थों के बीच निष्ठासुनिश्चित करने का एक तरीका भी है। इन बर्खास्तियों का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बैठक पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, जो अगले बृहस्पतिर को शुरू होगी और इसके एक सप्ताह तक चलने की उम्मीद है।

## ऑफ बीट

# रेन कोट की पानी से बचाव की क्षमता घटने के कारण

तेज बारिश में बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद यदि रेन कोट के अंदर कपड़े भीगने लगें, तो अक्सर लगता है कि 'वाटरप्रूफ' कोट ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर रेन कोट अचानक खराब नहीं होता, बल्कि उसकी बाहरी परत, गंदगी और लंबे उपयोग का असर धीरे-धीरे उसकी क्षमता कम करता है। अधिकतर गुणवत्तापूर्ण रेन कोट के भीतर एक विशेष वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन लगी होती है। गोर-टेक्स जैसी तकनीक में पीटीएफई या ईपीटीएफई की अत्यंत पतली परत होती है, जिसमें सूक्ष्म छिद्र बने होते हैं। ये छिद्र पानी की बूंदों को भीतर आने से रोकते हैं, लेकिन शरीर से निकलने वाली जलवाष्प को बाहर जाने देते हैं।

कुछ अन्य कोट ठोस, गैर-छिद्रयुक्त मेम्ब्रेन का उपयोग करते हैं, जो नमी को अवशोषित कर अणु-दर-अणु बाहर निकालती हैं। रेन कोट के बाहरी कपड़े पर 'ड्यूरेबल वाटर रिपेलेंट' (डीडब्ल्यूआर) नामक रासायनिक परत लगाई जाती है, जिससे पानी बूंदों के रूप में फिसल जाता है। पहले इन परतों में पीएफओएस जैसे 'फॉरएवर केमिकल्स' का इस्तेमाल होता था, लेकिन पर्यावरणीय चिंताओं के कारण अब सिलिकॉन या हाइड्रोकार्बन आधारित विकल्प अपनाए जा रहे हैं।

## अपने विचार

### हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

कांग्रेस के कॉम्प्रोमाइज सरेंडर से कैलेंडर भरा

# पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कॉम्प्रोमाइज कृत्यों को देश के सम्मुख रखना आवश्यकः सुधांशु

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल से जुड़े अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों, संस्मरणों और पुस्तकों का हवाला देते हुए शीत युद्ध के दौर में विदेशी खुफिया एजेंसियों के भारत पर प्रभाव और आर्थिक व कूटनीतिक निर्णयों तथा राजनीतिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कॉम्प्रोमाइज और सरेंडर से देश का कैलेंडर भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित किया।

डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि आजकल 'कंप्रोमाइज्ड गवर्नमेंट' विषय को लेकर प्रायोजित और संगठित दुष्प्रचार किया जाता है, इसलिए आज कांग्रेस पार्टी की सर्वकालीन, सर्वशक्तिशाली माने जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कॉम्प्रोमाइज कृत्यों को देश के सम्मुख रखना आवश्यक है। ब्रिटिश इतिहासकार पॉल मैकगैर की पुस्तक 'स्पाइंग इन साउथ एशियाः ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड द सीक्रेट कोल्ड वॉर' में उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारतीय व्यवस्था का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था, जो उस समय अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की पहुंच से बाहर न रहा हो।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि किताब में यह भी उल्लेख है कि वी. के. कृष्ण मेनन का इंदिरा गांधी पर काफी प्रभाव था और उनके विचार कई बार सोवियत संघ की सोच से मेल खाते थे। इसलिए उस दौर में सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों और नीतिगत झुकाव पर भी सवाल उठते हैं। जब सीआईए से जुड़े आरोपों की चर्चा होती है, तो शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के साथ निकटता के मुद्दे को भी उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मित्रोखिन आर्काइव्स में केजीबी के संदर्भ में यह भी लिखा है कि सोवियत पॉलिटब्यूरो की ओर से 1976 में कांग्रेस पार्टी को 20 लाख रुपए और बाद में 10 लाख रुपए दिए गए थे। आज से लगभग 50 वर्ष पहले 10–20 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी और यह विवरण वहां के पूर्व अधिकारियों के लिखित अभिलेखों में दर्ज है। उन्होंने कहा कि इस विषय को और आगे समझने की आवश्यकता है। वसीली मित्रोखिन, केजीबी के एक अधिकारी था, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद कई गोपनीय दस्तावेज लेकर लंदन चला गया और उसने दुनिया भर में केजीबी के ऑपरेशन्स को लेकर वर्ष 2006 में दो भागों में पुस्तक लिखी, 'मित्रोखिन आर्काइवः केजीबी एंड द वर्ल्ड (भाग-1 और भाग-2)।' दूसरे भाग में भारत के संदर्भ में उल्लेख है कि मई 1976 में मॉस्को के आग्रह पर भारत ने सोवियत वस्तुओं के आयात के लिए रूबल की विनिमय दर 8.33 रुपए प्रति रूबल से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति रूबल कर दी। यानी सीधे केजीबी के प्रभाव में कॉम्प्रोमाइज करके भारत की रुपए की विनिमय दर रूबल के संदर्भ में बढ़ाकर 8.33 से 10 कर दी गई ताकि सोवियत संघ से अधिकाधिक आयात हो सके और उसकी कीमत भारत के लोगों को चुकानी पड़े।

भाजपा सांसद ने कहा कि वर्ष 1977 में कांग्रेस की हार के बाद मॉस्को में इस विषय पर बैठक हुई कि इतने प्रयासों के बावजूद चुनावी पराजय क्यों हुई। यदि इसके बाद भी 'कॉम्प्रोमाइज' का अर्थ समझ में नहीं आता, तो तथ्यों को और ध्यान से देखने की आवश्यकता है। विकीलीक्स में जो विवरण सामने आए हैं, वे पूरी तरह सत्य हैं या नहीं, इसका अब तक कांग्रेस ने स्पष्ट खंडन नहीं किया है। 1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान जिस संभावित परमाणु परीक्षण की दिशा में बढ़ रहा था, उसे लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं थीं।

राष्ट्रीय प्रवक्ता ने 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत द्वारा आधिकारिक घोषणा से पहले ही रूस और अमेरिका की ओर से इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई थी। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत की गोपनीय से गोपनीय जानकारी, भारत से पहले उस समय की विदेशी शक्तियों के पास थी और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने बड़े विनम्र स्वर में झुककर कहा था, हमने यह हथियार के लिए नहीं किया है, बल्कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है। 1998 में 11 मई को दोपहर सवा तीन बजे जब अटल जी ने घोषणा की थी कि भारत ने पोखरण रेंज में परमाणु परीक्षण किया है, तो यह अमेरिका और रूस दोनों के लिए बड़ा झटका था।

डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि आज देश यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता है कि विदेशी एजेंसियों से धन लेने संबंधी जो बातें विभिन्न पुस्तकों में दर्ज हैं, और जिनका उल्लेख स्वयं उनके ही पूर्व अधिकारियों द्वारा किया गया है, उन पर कांग्रेस पार्टी ने अब तक न तो कोई ठोस स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? स्पष्टीकरण तो छोड़िए, उन पर कोई सवाल भी नहीं उठाया गया। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उस शक्ति के रूप में उभर रहा है कि विश्व का हर देश यह कह रहा है कि भारत आज नए स्वरूप में है। कल ही इजराइल के नेसेट में सभी ने देश के सम्मान को देखा। वहीं, दूसरी ओर जो किताबों का हिसाब निकल कर सामने आया है, उसने राजनीतिक विमर्श का वातावरण बहुत खराब कर दिया है। कांग्रेस पार्टी यह उत्तर दे कि, कांग्रेस ने कौन-कौन से कॉम्प्रोमाइज किए? उनके कॉम्प्रोमाइज और सरेंडर से देश का कैलेंडर भरा हुआ है।

---

सांसद बोलीः एससी, एसटी, बीसी वर्गों, दिहाड़ी

## बीपीएल राशन कार्डों में 24% कटौती पर जवाब दे हरियाणा सरकार

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

सिरसा की सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा ने हरियाणा में बीपीएल राशन कार्डों की संख्या में आई भारी कमी को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के जो आंकड़े सामने आए हैं वे चिंताजनक हैं और यह गरीबों के साथ अन्याय का संकेत देते हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि जनवरी 2024 में प्रदेश में 44.99 लाख बीपीएल राशन कार्ड थे, जो मार्च 2025 में बढ़कर 52.50 लाख हो गए, लेकिन जनवरी 2026 तक यह संख्या घटकर 39.88 लाख रह गई। उन्होंने कहा कि लगभग 24 प्रतिशत की यह कमी कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। क्या वास्तव में प्रदेश में गरीबी इतनी तेजी से कम हुई है या फिर पात्र परिवारों को विभिन्न प्रशासनिक कारणों से सूची से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एससी, एसटी, बीसी वर्गों, दिहाड़ी मजदूरों, विधवाओं और अनाथों के राशन कार्ड परिवार पहचान पत्र में कथित त्रुटियों के आधार पर काटे गए हैं।

- कहा, जनवरी 2024 में प्रदेश में 44.99 लाख बीपीएल राशन कार्ड थे, जो घटे

### गरीबों के लिए जीवन का आधार बना

कुमारी सैलजा ने कहा कि गरीब परिवारों के लिए राशन जीवन का आधार है और यदि पात्र लोगों को योजनाओं से वंचित किया गया है तो यह उनके अधिकारों का हनन है। उन्होंने प्रदेश सरकार से बीपीएल राशन कार्डों में हुई कटौती पर श्वेत पत्र जारी करने, अपील के बाद बहाल किए गए कार्डों का विवरण सार्वजनिक करने तथा पीपीपी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन पात्र परिवारों के कार्ड गलत डेटा के कारण कटे हैं, उनकी शीघ्र बहाली सुनिश्चित की जानी चाहिए।

---

'विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त' पर बोले पीएम मोदी

# बजट कोई शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट नहीं यह विकसित भारत का दीर्घकालिक रोडमैप

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

## बजट का मूल्यांकन उन नीतियों से होना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त" विषय पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार में कहा कि राष्ट्रीय बजट कोई शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि दीर्घकालिक पॉलिसी रोडमैप होता है। उन्होंने कहा कि बजट का मूल्यांकन उन नीतियों से होना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, क्रेडिट फ्लो आसान बनाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएं, गवर्नेंस में पारदर्शिता लाएं और नागरिकों का जीवन सरल बनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि हर बजट राष्ट्र निर्माण की सतत प्रक्रिया का एक चरण है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है।

बजट के बाद होने वाले वेबिनार केवल विचार-विमर्श तक सीमित न रहें, बल्कि व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित प्रभावी ब्रेनस्टॉर्मिंग का मंच बनें। उन्होंने उद्योग, शिक्षाविदों, विश्लेषकों और नीति-निर्माताओं की संयुक्त भागीदारी को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और सटीक परिणामों के लिए आवश्यक बताया।

**वेबिनार को प्रभावी बनाने पर जोर**

बजट वेबिनार को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी

नागरिकों का जीवन सरल बनाएगा

### सुधारों से बनी आर्थिक मजबूती

पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का एक चौथाई बीतने के साथ भारत तेज आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण चरण में है। पिछले एक दशक में देश ने असाधारण लचीलापन दिखाया है, जो संयोग नहीं बल्कि दृढ़ नीतिगत सुधारों का परिणाम है। प्रक्रियाओं के सरलीकरण, टेक्नोलॉजी-आधारित गवर्नेंस और मजबूत संस्थागत ढांचे ने अर्थव्यवस्था को नई गति दी है।

**दीर्घकालिक उत्पादकता बढ़ी**

उन्होंने कहा कि पिछले दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष फोकस रखा गया है। हाईवे, रेलवे, पोर्ट, डिजिटल नेटवर्क और पावर सिस्टम जैसे ठोस परिसंपत्तियों से दीर्घकालिक उत्पादकता पैदा होगी। 11 साल पहले सार्वजनिक पूंजीगत व्यय लगभग 2 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।

### निजी क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों की भूमिका अहम

प्रधानमंत्री ने उद्योग और वित्तीय संस्थानों से इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, फाइनेंसिंग मॉडल में नवाचार और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया और मूल्यांकन पर जोर दिया।

### विदेशी निवेश और बॉन्ड मार्केट सुधार

पीएम मोदी ने कहा कि विदेशी निवेश ढांचे को अधिक सरल और निवेशक-अनुकूल बनाया जा रहा है। लॉन्ग-टर्म फाइनेंस को मजबूत करने के लिए बॉन्ड मार्केट को सक्रिय बनाने और लेनदेन प्रक्रिया को आसान करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

### रिफॉर्म पार्टनरशिप चार्टर का सुझाव

उन्होंने कहा कि किसी भी नीति की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। सरकार, उद्योग, वित्तीय संस्थानों के साझा संकल्प के रूप में रिफॉर्म पार्टनरशिप चार्टर विकसित करने पर उन्होंने कहा यह विकसित भारत की यात्रा का महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेगा।

**आज जाएंगे गुजरात**

### माइक्रोन की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का करेंगे लोकार्पण

प्रधानमंत्री मोदी शनिवारको गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की नई सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे।

**प्रधानमंत्री का आज राजस्थान दौरा**

### कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

प्रधानमंत्री मोदी शनिवारको राजस्थान के अजमेर का दौरा करेंगे। वे 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे।

**महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू करेंगे**

प्रधानमंत्री 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे।

**प्रमुख हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे**

प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें बांदीकुई-जयपुर 4 लेन है।

---

स्पीकर बिरला ने इंदौर में श्री वैष्णव विद्यापीठ विवि के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित किया

# युवा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं

लोक सभा अध्यक्ष ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होने और नए आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में कार्य करने का किया आग्रह

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे परिवेश में भारत के युवा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह बदलते और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है तथा विचारशील दृष्टिकोण, नवोन्मेषी सोच और शोध करने में सक्षम इस युग के विद्यार्थी भारत को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए तत्पर हैं ।

बिरला ने इंदौर, मध्य प्रदेश में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय यह विचार व्यक्त किए । उन्होंने कहा कि युवा ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं; और इन युवाओं का आत्मविश्वास, नवीन दृष्टिकोण और नवोन्मेषी सोच राष्ट्र निर्माण का आधार बन गई हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि उनके अच्छे भविष्य के लिए ज्ञान अर्जित करना, व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना, नवोन्मेषी पद्धतियों को अपनाना और तकनीक में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है।

बिरला ने विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि यह विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालने में युवाओं को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है ।

बिरला ने बताया कि अपनी विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने देखा है कि अनेक देश भारत, विशेष रूप से इसकी युवा आबादी को बड़ी उम्मीद के साथ देखते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ कई देशों में युवा आबादी कम हो रही है, वहीं भारत की युवा आबादी और उनकी क्षमताएं अपार अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने इस बात की सराहना की कि स्टार्टअप्स, नवाचार और शोध कार्यों के माध्यम से, भारतीय युवाओं ने पहले ही राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास भारत की क्षमता और भावी नेतृत्व में मजबूत विश्वास को दर्शाते हैं। बिरला ने यह आशा व्यक्त की कि शैक्षणिक यात्रा के दौरान युवाओं को प्राप्त ज्ञान और अनुभव अंततः राष्ट्र के काम आएगा। बिरला ने कहा कि मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना से ओतप्रोत प्रत्येक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह नए भारत के निर्माण और एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति में पूरे तन-मन से योगदान दें। इस अवसर पर इंदौर से सांसद शंकर लालवानी और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट भी उपस्थित रहे ।

---

# पी. चिदंबरम के खिलाफ दो मामलों में अभियोजन स्वीकृति षड्यंत्र कर सौदों को मंजूरी दी, ईडी ने विशेष अदालत में रखा

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ दो अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

एयरसेल-मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया सौदों से जुड़े इन मामलों में स्वीकृति आदेश विशेष अदालत में पेश कर दिया गया है, ताकि सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। माना जा रहा है अब चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस घटनाक्रम को तमिलनाडु चुनाव से जोड़ कर देख रही है।

ईडी के अनुसार, दोनों सौदे कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए थे, जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे। एयरसेल-मैक्सिस मामले में ईडी ने 2018 में और आईएनएक्स मीडिया मामले में 2020 में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिनमें चिदंबरम का नाम शामिल है। अदालत ने 2021 में आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया था।

दोनों मामलों में सुनवाई अभियोजन स्वीकृति के अभाव में रुकी हुई थी। अब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) -जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत आती है, उसके तहत स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। ईडी ने यह आदेश राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है।

ईडी का आरोप है कि पूर्व वित्त मंत्री ने विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के माध्यम से एयरसेल-मैक्सिस को मंजूरी देने में कथित रूप से अनियमितता बरती। एजेंसी का कहना है कि 20 मार्च 2006 को दी गई मंजूरी उस सीमा से अधिक थी, जिसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अनुमति आवश्यक थी। आरोप है कि यह मंजूरी कथित रूप से एक बड़े षड्यंत्र के तहत दी गई।

ईडी ने यह भी दावा किया है कि जांच में सामने आया है कि कथित तौर पर 1.16 करोड़ की अवैध राशि

### पवन खेड़ा ने कहा, भाजपा इच्छाधारी नाग

एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा। भाजपा कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि रूप बदलने वाला 'इच्छाधारी नाग' है।
उसका एक ही जुनूनी लक्ष्य है -कांग्रेस मुक्त भारत।
12 साल तक टीएमसी पर जहर उगला और अब नरेंद्र मोदी उसी की तारीफ कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस पर सस्ता वार करने के लिए।
चुनाव आते ही कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले तेज कर दिए जाते हैं।
तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए पी. चिदंबरम को फिर से सुर्खियों में लाया गया है।
वहीं आम आदमी पार्टी और अन्य 'सुविधाजनक सहयोगियों' के खिलाफ कार्रवाई गुजरात और पंजाब चुनाव के मद्देनजर धीमी पड़ जाती है।

---


**उत्तर रेलवे**

**ई–निविदा (ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम) के माध्यम से निविदा आमंत्रण**

| | |
|---|---|
| एनआईटी | 90, 94 - 2025-26-डब्ल्यू–5 |
| काम का नाम (स्थान के साथ) | (90) सहायक मंडल अभियंता/दिल्ली सराय रोहिल्ला के क्षेत्र में विभिन्न कम ऊंचाई वाली सबवे से पानी निकालना और कम ऊंचाई वाली सबवे और पुलों के जलमार्ग की सफाई कराने का कार्य। (94) वरिष्ठ मंडल अभियंता पंचम के क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति कराने का कार्य। **समान कार्य की प्रकृति** : कोई भी सिविल कार्य। |
| | (90) Rs.2806792.01 (94) Rs.6498626.56 |
| अग्रिम राशि (रुपये) | (यह नेट बैंकिंग के रूप में होना चाहिए या केवल भुगतान गेटवे द्वारा 1) (नोटः–रेलवे बोर्डों के पत्र संख्या 2015/सीई–आई/सीटी/5/1 दिनांक 31.08.2016 के अनुसार जो टेंडर आईआरईपीएस पर आमंत्रित किया गया है उसमें एफडीआर को निविदा के लिए ईएमडी के रूप में, स्वीकार नही किया जाएगा। |
| | (90) Rs.56100.00 (94) Rs.130000.00 |
| | (90) 06 महीने (94) 06 महीने |
| निविदा प्रस्तुत करने और निविदा खोलने के लिए दिनांक और समय | 24.03.2026 को 15.00 बजे तक तथा 24.03.2026 को 15.00 बजे निविदा खुलना है |
| वेबसाइट के विवरण का नोटिस बोर्ड स्थान निविदा का पूरा | यह निविदा आईआरईपीएस वेबसाइट अर्थात www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। |

No. 128-W/280/OET/2025-26/W-V/NIT-90 & 94 - 2025-26
Date : 26.02.2026 667/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ


---


**अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा**

धारा 82 सीआरपीसी / 84 बीएनएसएस देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **1. आरिफ उर्फ आसिफ** पुत्रः **इकबाल 2. दानिश पुत्रः असलम** दोनों निवासीः **1457, आई–ब्लॉक, गली नं. 1500, जहाँगीरपुरी, दिल्ली** ने **case FIR No. 625/2024 U/s 307/317(2) / 3(5) BNS, थानाः सब्जी मंडी, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उन्होंने किया है) और उन पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **1. आरिफ उर्फ आसिफ 2. दानिश** मिल नहीं रहे हैं और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **1. आरिफ उर्फ आसिफ 2. दानिश** फरार हो गए है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे हैं।)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **case FIR No. 625/2024 U/s 307/317(2) / 3(5) BNS, थानाः सब्जी मंडी, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **1. आरिफ उर्फ आसिफ 2. दानिश** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद/मुकदमा का उत्तर देने के लिए **दिनांक 07.04.2026** को या उससे पूर्व हाज़िर हो।

आदेशानुसार
**सुश्री प्रीति राजोरिया**
**न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी–07**
**केन्द्रीय, रूम नं. 32**
**तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली**

DP/2525/N/2026 (Court Matter)


---

एचपीवी के खिलाफ जंगः राजस्थान के अजमेर से होगी शुरुआत

# प्रधानमंत्री मोदी आज से शुरू करेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान

शिशिर सोनी ⏭ नई दिल्ली

देश में गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के अजमेर से मानव पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) टीकाकरण के विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार इस अभियान के तहत 14 वर्ष की सभी बालिकाओं तथा अगले 90 दिनों के भीतर 15 वर्ष की होने वाली किशोरियों को यह टीका निःशुल्क लगाया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एचपीवी संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है। भारत में महिलाओं में यह कैंसर का दूसरा सबसे आम प्रकार है, जिससे हर वर्ष लगभग 1.25 लाख नए मामले सामने आते हैं और करीब 75 हजार महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कम उम्र में टीकाकरण से भविष्य में इस घातक बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

### देशभर में 30 हजार से अधिक केंद्रों पर सुविधा

सरकार ने इस अभियान के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। देशभर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में स्थापित लगभग 30,000 टीकाकरण केंद्रों पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। इन केंद्रों पर कोल्ड चेन की व्यवस्था, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी और आपात स्थिति से निपटने की सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। पहले 90 दिनों तक सभी पात्र बालिकाओं के लिए रोजाना टीकाकरण उपलब्ध रहेगा, उसके बाद नियमित टीकाकरण दिवसों में सप्ताह में दो बार यह सेवा जारी रहेगी। राज्यों को आवश्यक खुराक का वितरण शुरू कर दिया गया है। बड़े राज्यों को उनकी आवश्यकता का लगभग आधा स्टॉक पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है ताकि अभियान में कोई बाधा न आए।

### पात्रता और दिशा-निर्देश

14 वर्ष की सभी बालिकाएं या अभियान शुरू होने के 90 दिनों के भीतर 15 वर्ष की होने वाली किशोरियां टीका लगवा सकती हैं। अभिभावक 'यू-विन' ऐप के माध्यम से सहमति दे सकते हैं या इंटरनेट उपलब्ध न होने पर लिखित सहमति भी स्वीकार की जाएगी।

जिन बालिकाओं को मध्यम या गंभीर बीमारी हो, पहले टीकों से एलर्जी रही हो या यीस्ट से एलर्जी हो, उन्हें टीकाकरण से पहले चिकित्सकीय परामर्श लेना होगा। लक्ष्य आयु वर्ग से बाहर की बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं या पहले से एचपीवी टीका ले चुकीं किशोरियां इस चरण में पात्र नहीं होंगी।

### केंद्रों पर विशेष सावधानियां

टीकाकरण केंद्रों पर आने वाली बालिकाएं अपने अभिभावकों के साथ वॉक-इन कर सकती हैं या पूर्व अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। टीकाकरण से पहले हल्का नाश्ता करने की सलाह दी गई है। टीका लगने के बाद 30 मिनट तक केंद्र पर रुककर निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया की स्थिति में तुरंत उपचार दिया जा सके। सामान्य दुष्प्रभावों में हल्का दर्द, लालिमा, बुखार या सिरदर्द शामिल हो सकते हैं। एचपीवी टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा जाएगा, जो कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अन्य टीकों के समान है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि भंडारण और आपूर्ति में कोई अतिरिक्त चुनौती नहीं है।

संपादकीय जागरण

शनिवार, 28 फरवरी, 2026 : फाल्गुन शुक्ल - 12 वि. 2082

आसक्ति से मुक्ति ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है

# आगे आए उद्योग जगत

**बजट के** बाद 'विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त' विषय एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय कंपनियों को नए निवेश एवं नवाचार के साथ आगे आना चाहिए, उस पर उन्हें सकारात्मकता के साथ सक्रियता का परिचय देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से बजट घोषणाओं का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। कायदे से तो ऐसे किसी आग्रह की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। उद्योग जगत को स्वतः सक्रिय हो जाना चाहिए। यह पहली बार नहीं, जब प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को नवाचार के जरिये अपनी क्षमता प्रदर्शित करने को कहा हो। वे इसके साथ ही यह भी कहते रहे हैं कि उद्योग जगत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनना चाहिए और शोध एवं विकास में निवेश करना चाहिए। विडंबना यह है कि हमारे ऐसे बड़े कारोबारी भी यह काम नहीं कर रहे हैं, जिनके पास पूंजी की कोई कमी नहीं। वे नवाचार के नाम पर ऐसे नए काम अधिक हाथ में लेते हैं, जिनसे कम समय में आसानी से धन अर्जित किया जा सके। यही कारण है कि वे ऐसे कोई उत्पाद तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी देश के साथ दुनिया में भी मांग हो।

यह सामान्य बात नहीं कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने के बाद भी चंद भारतीय उत्पाद ही ऐसे हैं, जिनकी विश्व में थोड़ी-बहुत पहचान और प्रतिष्ठा है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि भारतीय उद्योग जगत शोध एवं विकास में पैसा खर्च न कर पाने के कारण न तो चीनी उत्पादों का मुकाबला कर पा रहे हैं और न ही अपने उत्पाद विश्व बाजार में आसानी से खपा पा रहे हैं। जहां चीन में उद्योग जगत आर्थिक विकास का नेतृत्व करते दिखता है, वहीं भारत में कारोबारी सरकार के प्रोत्साहन पर भी तत्परता नहीं दिखाते। एक-दो कारोबारी समूहों को छोड़ दिया जाए तो आम तौर पर हमारे कारोबारी वैश्विक स्तर की उत्पादकता हासिल करने के लिए सक्रिय नहीं। वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता भी विश्वस्तरीय बनाने के लिए उत्साही नहीं हैं। एक ऐसे समय जब सरकार एक के बाद एक देशों से मुक्त व्यापार समझौते कर रही हैं और इसके चलते शीघ्र ही कई विकसित देशों के बाजार भी भारतीय उद्योग जगत की पहुंच में होंगे, तब तो उन्हें इन समझौतों का पूरा लाभ उठाने के लिए कमर कसनी ही चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि सरकार प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही है। उचित यह होगा कि प्रधानमंत्री ने सरकार, उद्योग जगत, वित्तीय संस्थानों और शिक्षाविदों के बीच सहयोग स्थापित करने वाले जिस 'रिफार्म पार्टनरशिप चार्टर' की बात की, उस पर गंभीरता से काम हो, ताकि वह विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बन सके।

# जांच एजेंसी पर सवाल

**दिल्ली में** आबकारी घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री समेत सभी 23 आरोपितों को बरी कर दिया गया है। अदालत ने आरोपितों को बरी करते हुए सीबीआइ पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने कहा है कि जांच एजेंसी ने ऐसे कोई सुबूत नहीं दिए जिनसे प्रथमदृष्टया स्थापित होता हो कि आरोपितों ने कोई साजिश रची थी। यही नहीं, अदालत ने आरोपित नंबर एक को बिना सुबूत आरोपित बनाए जाने पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं और इस मामले में जांच अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निश्चित तौर पर यह मामला गंभीर है कि जांच एजेंसी जिन्हें आरोपित बताती रही वह आरोप पत्र में उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं पेश कर सकी।

**जांच में खामियों को लेकर संबंधित अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई की जाए, ताकि निष्पक्षता बरकरार रह सके**

ऐसा नहीं है कि सीबीआइ पर पहली बार कोई सवाल खड़े हुए हैं। पूर्व में भी कई मामलों में सीबीआइ की किरकिरी हो चुकी है। आबकारी घोटाले के इस मामले में भी जांच एजेंसी को कठघरे में खड़ा किया जाना सर्वथा उचित है। यह सही है कि सीबीआइ ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट गई है, लेकिन निचली अदालत से सभी आरोपित बरी हैं, ये सीबीआइ की जांच पर बड़ा सवाल है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि जांच में खामियों को लेकर संबंधित अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाए, ताकि जांच एजेंसी की निष्पक्षता बरकरार रखी जा सके।

## कह के रहेंगे

माधव जोशी

## जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा पर कांग्रेस की आपत्ति उचित है?

**आज का सवाल**

क्या अदालती राहत के बाद अरविंद केजरीवाल राजनीतिक रूप से और मजबूत होकर उभरेंगे?

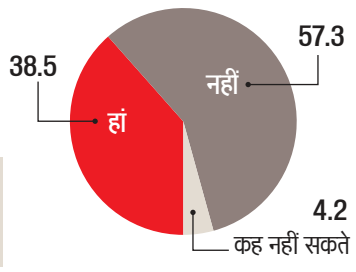


परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

# विवादों के केंद्र में शंकराचार्य

हृदयनारायण दीक्षित

**यह दुखद है कि आज के शंकराचार्य स्वयं के सम्मान के लिए झगड़ा करते हैं और कोर्ट-कचहरी में पदों की लड़ाई लड़ते हैं**

शंकराचार्य भारत की अनोखी त्याग परंपरा का विस्तार हैं। आदि शंकराचार्य ने विश्व दर्शन को अद्वैत दर्शन से समृद्ध किया। अल्प आयु में ही उन्होंने 11 प्रमुख उपनिषदों, गीता और ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया। सांस्कृतिक एकता के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। बौद्ध एवं अन्य विद्वानों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। उन्हें सभी स्थानों पर विजय मिली। शंकराचार्य के भ्रमण को उस समय दिग्विजय कहा गया। उन्होंने सांस्कृतिक विचारधारा को प्रवाहमान बनाने के लिए चार मठों की स्थापना की। कर्नाटक में श्रृंगेरी, उत्तराखंड में जोशीमठ, ओडिशा में पुरी और गुजरात में द्वारका। उनके चार विद्वान शिष्यों ने मठों का नेतृत्व किया। उन्होंने चारों वेदों को प्रतिष्ठा दी। सभी मठों को एक वेद से जोड़ा-श्रृंगेरी पीठ, कर्नाटक-यजुर्वेद, द्वारका पीठ, गुजरात-सामवेद, पुरी पीठ, ओडिशा-ऋग्वेद, ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड-अथर्ववेद। वे द्रष्टा थे। अद्वैत वेदांत उनका दर्शन था। डा. एस. राधाकृष्णन ने उन्हें असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति बताया था।

दुर्भाग्य से आधुनिक काल के शंकराचार्य अपने कार्य व्यवहार से निराश करते हैं। वे प्रेरित नहीं करते। उत्साह और उल्लास नहीं देते। वे व्यापक हिंदू समाज को कोई ठोस एवं प्रभावी दिशा नहीं देते। इन दिनों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रशासन और शासन से विवाद के कारण लगातार चर्चा में हैं। इस विवाद की शुरुआत प्रयागराज में माघ मेले में स्थानीय प्रशासन के बीच टकराव से हुई थी। मौनी अमावस्या पर्व पर स्वामी जी पारंपरिक पालकी से स्नान के लिए निकले। प्रशासन ने उनका ध्यान भीड़ प्रबंधन की ओर आकर्षित किया और उनसे पैदल चलने का अनुरोध किया। इसके बाद उनके अनुयायियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। आचार्य के अनुयायियों के अनुसार शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। स्वामी जी ने इसे शंकराचार्य का अपमान बताया और बिना स्नान किए लौट आए। प्रशासन ने स्वामी जी को लिखित चेतावनी दी। नोटिस में उन पर सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन आदेश का उल्लेख करते हुए पूछा गया कि वे अपने शिविर के बाहर बोर्ड पर शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं?

पता नहीं इस विवाद का पटाक्षेप कैसे और कब होगा, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि हम भारत के लोग साधु-संतों को सम्मान से देखते हैं। गीता में संन्यासी की परिभाषा है, 'जो इच्छारहित है, सभी द्वंद्वों से मुक्त है, वही संन्यासी है।' आदि शंकराचार्य ऐसे ही दार्शनिक संन्यासी थे। साधना की सिद्धि प्राप्त संत हैं। महतत्व के बोध वाला महंत है, लेकिन आज के

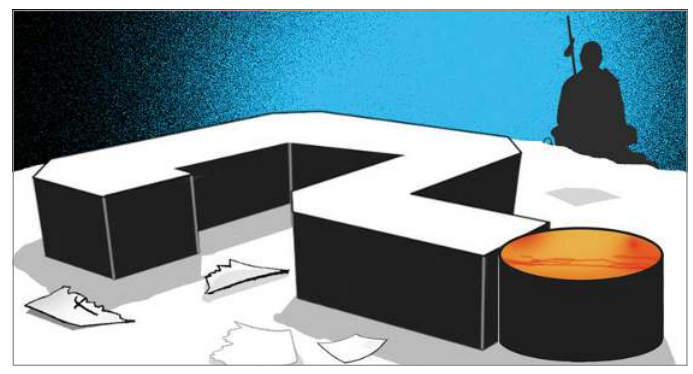

अवधेश राजपूत

शंकराचार्य संभवतः ऐसा नहीं मानते। वे स्वयं के सम्मान के लिए झगड़ा करते हैं। कोर्ट-कचहरी में पदों की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा पहले से भी होता आ रहा है। मठों-पीठों की संपदा को लेकर भी झगड़े होते रहे हैं और वे अंग्रेजी राज में ही प्रिवि काउंसिल तक जा चुके थे। पीवी काणे ने 'धर्मशास्त्र का इतिहास' में लिखा है कि मठों में अधिकार क्षेत्र आदि को लेकर झगड़े होते रहे हैं।

प्रथम शंकराचार्य ने मठों के संचालन के लिए 'मठाम्नाय महानुशासन' की नियमावली बनाई थी। मठाम्नाय का अर्थ है महानुशासन। शंकराचार्य दर्शन और अध्यात्म के परम विद्वान थे। उन्होंने काम करते हुए अनुभव कर लिया था कि सांसारिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में संलग्न व्यक्ति धर्म प्रचार का कार्य नहीं कर सकेगा। इसलिए उन्होंने संसार त्यागी सुयोग्य ब्रह्म पारायण संन्यासियों को धर्म प्रचार का कार्य सौंपा और सबके लिए अनुशासन पालन का नियम बनाया। शंकराचार्यों को उससे शासित होना चाहिए। आश्चर्य है कि हमारे शंकराचार्य कुंभ या अन्य अवसरों पर पहले स्नान के लिए झगड़ते हैं। राजनीतिक मामलों में वक्तव्य देते हैं। धार्मिक मामलों को राजनीतिक रंग देते हैं।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन अंतरराष्ट्रीय उत्सव था, लेकिन यह आयोजन राजनीतिक बहस का हिस्सा बना। इसका कारण कुछ शंकराचार्यों के बयान रहे। उनके बयानों से विपक्षी दलों को मसाला मिला। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर सबसे ज्यादा मुखर रहे। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री ही मूर्ति स्थापित करेंगे तो शंकराचार्य क्या वहां ताली बजाने के लिए बैठेंगे? अयोध्या और प्रयागराज के संदर्भ तो ताजा हैं। एक समय ज्योतिष्ठ पीठ बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सिविल जज ने वासुदेवानंद को स्वयं को शंकराचार्य घोषित करने पर रोक लगा दी थी। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के समय भी केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल भीम शंकर और शंकराचार्य स्वरूपानंद टकरा गए थे। एक शंकराचार्य ने साईं बाबा पर लगातार हमले किए।

जागृत समाज में आप जबरदस्ती सम्मान नहीं ले सकते। सम्मान का इच्छुक व्यक्ति राष्ट्र के जीवन मूल्यों के अनुसार जीवन-यापन करता है। समाज हर गतिविधि को ध्यान से देखता है। कोई यों ही आदि शंकराचार्य की तरह सुविख्यात नहीं हो जाता। उसे तप और साधना की अग्नि में स्वयं को तपाना होता है। वह इतिहास से सामग्री लेता है। अनुकरणीय तत्व छांटता है। वह सबको प्रेरित करता है, लेकिन कुछ शंकराचार्यों के कार्य और व्यवहार से देश और विशेष रूप से हिंदू समाज निराश हुआ है। शंकराचार्य संस्था यूरोप के पोप जैसी नहीं है। हिंदू शंकराचार्यों सहित देश की सभी धार्मिक परंपराओं का आदर करते हैं। शंकराचार्य नए समाज की आवश्यकता समझें। वे भारत के धर्म, अध्यात्म की परंपरा को व्यक्तिगत अहमान्यता से मुक्त होकर नए आकाश और नए पंख दें।

देश के सामने आदि शंकराचार्य का प्रेरक व्यक्तित्व है। उन आदर्शों के विपरीत आचरण समाज को दुखी करता है। सभी साधु, संत और महंत हिंदू मन की पुकार सुनें। हिंदू समाज को दार्शनिक और प्रगतिशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला समाज बनाने के लिए मार्गदर्शन करें। धर्म-दर्शन के स्तर पर विश्ववारा बनाने का दायित्व पूरा करने के लिए अगुआई करें, ताकि भारत की प्रतिष्ठा और बढ़े।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

# विकसित देश का मंत्र है वैज्ञानिक सोच

डा. सुशील द्विवेदी

**यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि शोध-अनुसंधान का मतलब केवल पीएचडी कर लेना नहीं होता और न ही होना चाहिए**

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों को याद करने का ही नहीं, बल्कि बच्चों, युवाओं से लेकर आमजन में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने का अवसर भी बनना चाहिए। अगर भारत को विकसित देश बनना है, तो उसमें विज्ञान की बड़ी अहम भूमिका होगी। यह भूमिका तभी सार्थक होगी, जब हम वैज्ञानिक शोधों को अपनी कार्यसंस्कृति का हिस्सा बना लें। इसके लिए आवश्यक होगा कि हम बुनियादी स्तर से ही बच्चों को ऐसी जानकारियां देने के उपाय करें, जो उनमें वैज्ञानिक सोच के विकास में सहायक बने। इसके लिए पारंपरिक ज्ञान के साथ ही वैज्ञानिक स्वाभाव भी विकसित करना होगा। इसके लिए बच्चों को हर तरह के सवाल पूछने के लिए भी प्रोत्साहित करना होगा। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए उनमें आसपास की चीजों को समझने के प्रति कौतूहल भी पैदा करना होगा। पढ़ाई में रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमारे बच्चे प्रयोगशालाओं में प्रयोग करें और अपनी गलतियों से सीखें। 'करके सीखने' अर्थात लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से छात्रों के सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक प्रयोगशाला के अनुभवों में सहायता मिलेगी। हालांकि यह सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा। इसके लिए हमें गांवों से लेकर शहरों तक स्कूलों में अच्छी विज्ञान प्रयोगशालाओं का व्यापक जाल बिछाना होगा। इसी सोच से प्रेरित भारत सरकार द्वारा गत वर्ष अक्टूबर तक 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा चुकी हैं और अगले पांच वर्षों में 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में स्थापित करने की योजना बनाई है।

नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत इन लैब्स का उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, रचनात्मकता और स्टेम (साइंस-टेक्नोलाजी-इंजीनियरिंग-मैथ) कौशल को बढ़ावा देना है। यह पहल हर जिले में तकनीक-आधारित नवाचार को बढ़ावा देगी। इस क्रम में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआइआर का 'जिज्ञासा' कार्यक्रम स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक चेतना और जिज्ञासा जगाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

वैज्ञानिक चेतना को प्रोत्साहन देना आवश्यक ● फाइल

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य "करके सीखने" (लर्निंग बाय डूइंग) के माध्यम से छात्रों के सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक प्रयोगशाला के अनुभवों से जोड़ने में सहायक हो रहा है। इसरो का युविका (युवा विज्ञानी कार्यक्रम) स्कूली बच्चों में विज्ञान और अंतरिक्ष तकनीक के प्रति गहरी समझ और रुचि विकसित करने के लिए एक शानदार पहल है। इसे 'कैच देम यंग' यानी छोटी अवस्था में ही स्कूली छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के प्रति रुचि जगाकर उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से आकार दिया गया है। दो सप्ताह के इस आवासीय कार्यक्रम में छात्रों को प्रख्यात विज्ञानियों से मिलने, प्रयोगशालाओं का दौरा करने और व्यावहारिक प्रयोग (माडल राकेट्री) करने का अवसर भी मिलता है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भी बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह कार्यक्रम छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें वास्तविक दुनिया की समस्याओं को वैज्ञानिक पद्धति से सुलझाने के लिए प्रेरित करता है।

एनसीईआरटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी भी बच्चों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम बन गई है। यह प्रदर्शनी केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि युवा मस्तिष्कों में नवाचार और रचनात्मकता का संचार करने वाला एक उत्सव है। राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन के अनुरूप बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो रही है। इसी प्रकार स्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो स्कूली बच्चों में न केवल विज्ञान के प्रति रुचि पैदा कर रही है, बल्कि उनमें एक गहरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित कर रही है। यह योजना बच्चों को अपने आसपास की समस्याओं को पहचानने और उनके लिए मौलिक समाधान सोचने के लिए प्रेरित करती है। ये सब प्रयास तब और रंग लाएंगे, जब देश का उद्योग जगत अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वैज्ञानिक अध्ययन संस्थानों से गठजोड़ करके अनुसंधान का सिलसिला शुरू कर उसे गति प्रदान करे। अगर शिक्षा और उद्योग क्षेत्र में यह साझेदारी विकसित हो जाती है तो भारत को जल्द विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता।

भारत के कुछ गिने-चुने ऐसे संस्थान हैं, जिन्होंने अपनी प्रगति और कामयाबी से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसरो इनमें सबसे आगे है, लेकिन भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए इकलौते इसरो या आइआइटी से ही काम नहीं चलने वाला। हमें देश के अन्य उच्चस्तरीय संस्थानों में भी रिसर्च का एक बेहतर इकोसिस्टम विकसित करना होगा। यह भी ध्यान रखा जाए कि शोध-अनुसंधान का मतलब केवल पीएचडी कर लेना नहीं है। शोध तभी सफल है जब उसके केंद्र में यह बिंदु हो कि दैनिक जीवन को सुगम बनाने के लिए वह क्या योगदान कर सकता है? विज्ञान तभी सार्थक है जब कोई भी सामान्य समझ वाला व्यक्ति उसे आसानी से आत्मसात कर उसका उपयोग कर सके।

(लेखक शिक्षा मंत्रालय के पीएम-ई-विद्या कार्यक्रम में विज्ञान विषय के संसाधक हैं)
response@jagran.com

## ऊर्जा

### धर्म और विज्ञान

धर्म और विज्ञान की पद्धतियों में कुछ अंतर अवश्य हैं, किंतु दोनों का लक्ष्य है मनुष्य को परिष्कृत करते हुए उसे निरंतर प्रगति की ओर प्रशस्त रखना। विज्ञान को धर्मविरोधी मानना उचित नहीं। वैज्ञानिक सत्य विस्मयकारी होता है, किंतु नैतिक सत्य दैविक होता है। प्रकृति की विराटता और इसके अनंत रहस्यों को समझने की चेष्टाओं का नाम ही विज्ञान है। आस्था पर टिके धर्म और साक्ष्य पर टिके विज्ञान दोनों अपने तौर-तरीकों से घटनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट और बोधगम्य बनाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का अर्थ धर्म को नकारना नहीं है।

पृथ्वी और समुद्र की अंदरूनी परतों की छोड़ दें तो उपलब्ध ज्ञान के बावजूद ऊपरी सतह पर पलते जीवों और वनस्पतियों के मूलभूत तथ्यों का समुचित आकलन भी पर्याप्त संतोषजनक नहीं है। नियमित शोध इसीलिए हो रहे हैं, क्योंकि विकृतियों से राहत के लिए अभी तक प्राप्त ज्ञान सीमित है। प्रकृति को उत्कृष्ट अस्मिता मानते हुए शीर्ष विज्ञानियों की स्वीकारोक्ति है कि इस बाबत हम अत्यधिक अनभिज्ञ हैं। चूंकि मनुष्य का मूल स्वरूप दैविक है, इसलिए उसके मस्तिष्क और हृदय के कार्यसंचालन को वैज्ञानिक आधार पर नहीं समझ सकते। साक्ष्यों के अभाव में मनुष्य की दिव्यता को समझने-आंकने में वैज्ञानिक जुगत निष्फल रही हैं। यह संयोग नहीं कि विश्व के आधे से अधिक सुधी विज्ञानियों ने अपनी उपलब्धियों का श्रेय सीधे या परोक्ष रूप से धर्म या आध्यात्मिकता को दिया। शीर्ष विज्ञानी ईश्वर या दैविक शक्तियों के प्रति आस्थावान रहे हैं।

हम प्रेम, सौंदर्य, मित्रता जैसी जीवन की अहम अस्मिताओं को परिभाषित-मूल्यांकित नहीं कर सकते। धर्म ही है जो आज के विघटन भरे समाज में विज्ञान से डांवाडोल हो रही मानसिक एवं भावात्मक व्यवस्थाओं में संतुलन और सांमजस्य बनाता है। वही मनुष्य को संबल तथा स्थिरता प्रदान करता है।

हरीश बड़थ्वाल

## पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

### राहुल के नेतृत्व पर उठते सवाल

'गठबंधन को लेकर बेपरवाह कांग्रेस' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राज कुमार सिंह का कांग्रेस के नेतृत्व वाले आइएनडीआइए की निष्क्रियता का सटीक विश्लेषण पढ़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के चलते विपक्षी दलों ने सहजता के साथ राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का अवसर जरूर दिया, लेकिन वे गंभीरता के साथ इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी परिपक्व राजनेता की छवि बना पाने में असमर्थ दिख रहे हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस के भीतर सुगबुगाहट भी होती रहती है। कांग्रेस को असहज तब होना पड़ा, जब कुछ वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर ही प्रश्नचिह्न लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस के इस अंदरूनी विचलन से विपक्षी गठबंधन की सक्रियता प्रभावित हो रही है। इस गठबंधन के अब वैसे तेवर नहीं रहे, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिए थे। तब विपक्षी गठबंधन ने अपनी सक्रियता के चलते भाजपा को बहुमत से पीछे खड़ा कर दिया था, लेकिन अब जब चार राज्यों के साथ एक केंद्रशासित प्रदेश के चुनाव सिर पर हैं, तब आइएनडीआइए की निष्क्रियता विपक्षी दलों को हतोत्साहित कर रही है। अभी हाल में बिहार और महाराष्ट्र की शर्मनाक हार ने विपक्ष के मनोबल को तोड़ने का काम किया है। ऐसे में यदि समय रहते विपक्षी गठबंधन को मजबूत नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनावों में विपक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतने अल्प समय में आइएनडीआइए के दरकते ढांचे को दुरुस्त कर उसमें चुनावी ऊर्जा का संचार राहुल गांधी अथवा उनकी दरकती कांग्रेस कर पाएगी, इसमें संदेह है। ऐसे में, यदि विपक्षी दलों को विभिन्न राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों में कुछ हासिल करना है तो उसे विपक्षी गठबन्धन के नेतृत्व परिवर्तन पर गंभीरता से विचार करना ही होगा।

डा. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़ (उप्र)

### सकारात्मक सोच आवश्यक

भारत और कनाडा के रिश्ते अब पहले से बेहतर हो रहे हैं। अब वैश्विक हालात में कनाडा को भारत की अहमियत समझ आने लगी है। बीते कुछ समय से कनाडा के साथ भारत के रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे हैं। अब कनाडा ने रिश्तों में मधुरता दिखाने के लिए एक सकारात्मक संदेश दिया है। कनाडा भारत के साथ सहयोग करके विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों मे निकटता बढ़ाना चाहता है। इस मामले में भारत हमेशा से ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। भारत को कनाडा से यूरेनियम का आयात बढ़ाने की उम्मीद भी की जा रही है साथ ही कच्चे तेल और अन्य ऊर्जा उत्पादों की खरीद सहित व्यापक रूप में निवेश भी बढ़ाया जाएगा। इन दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की जमीन पहले से ही मजबूत है। जिसका फायदा दोनों मुल्कों को मिलेगा। बहरहाल, कनाडा और भारत के संबंध अब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव दिल्ली

### संतों का राजनीति झुकाव गलत

कोई भी शंकराचार्य या साधु-संत का राजनीति की ओर झुकाव नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर समाज में एक न एक दिन उस महात्मा की किरकिरी अवश्य होती है और उन्हें अपयश का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही अपने को उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ (बद्रीनाथ) के शंकराचार्य कहने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हो रहा है। उन पर लगाए गए आरोप की सत्यता जांच के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल उनकी छवि श्रद्धालुओं के मन में बदल गई है। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। स्वामी और उनके शिष्यों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांगने और गोमांस के मुद्दे पर सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद यह विवाद बढ़ा, जिसे कुछ लोग राजनीति से प्रेरित मानते हैं। उन्हें शक की निगाहों से देखा जा रहा है, जिससे संतों का राजनीति से दूर रहने का महत्व उजागर होता है। उत्तर प्रदेश सरकार से टकराव की शुरुआत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज के माघ मेले में पालकी पर बैठकर स्नान करने की परंपरा का हवाला दिया, जिसे पुलिस ने नियमों का उल्लंघन बताकर रोका था। प्रयागराज माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से मेला प्रशासन का टकराव चर्चा में है। इस मामले ने तूल पकड़ते हुए राजनीतिक रंग ले लिया है।

-युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

## पोस्ट

अफगानिस्तान और पाकिस्तान रमजान के महीने में एक-दूसरे से जंग में जुटे हैं। उनका यह कृत्य कितना शांतिपूर्ण एवं कितना इस्लामिक है?

इम्तियाज महमूद@ImtiazMadmood

भारत में तमाम लोग गाजा में हो रही मौतों पर आंसू बहाते नहीं थकते, लेकिन वे भी पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के लोगों की हत्या पर मौन साधे हुए हैं।

अभिजीत अय्यर मित्रा@Iyervval

अगर मुख्यमंत्री होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल 156 दिन और उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया 530 दिनों तक जेल में रह सकते हैं और उसके बाद अदालत उन्हें राहत दे तो जरा आम आदमी की हालत के बारे में सोचिए।

प्रयाग@theprayagtiwari

एक समय केजरीवाल ने तमाम लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिन्हें वे कभी साबित नहीं कर पाए। अब एक मामले में अदालती राहत मिली तो वे भावुक होकर रोने लगे। उन्हें उन नेताओं के लिए भी रोना चाहिए, जिन पर उन्होंने आरोप लगाए थे। कर्मों का सारा हिसाब यहीं होता है। संजय निरुपम@sanjaynirupam

## जनपथ

सीबीआई छीलती रहती हरदम घास,
उसके आरोपित सभी हो जाते हैं पास।
हो जाते हैं पास चलेगी वर्षों खिट पिट,
दे देता है कोर्ट अंत में साफ क्लीनचिट!
हम भारत के लोग टैक्स भरते हैं भाई,
उसी टैक्स को खाय निकम्मी सीबीआई!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा -201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : **0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90** समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। **वर्ष 36 अंक 225**

## एक नजर में

### कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से 17 पैसे लुढ़का रुपया

**मुंबई:** विदेशी फंडों की ताजा निकासी, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और भूराजनीतिक अनिश्चितता के चलते शुक्रवार को अमेरिकी डालर के मुकाबले भारतीय रुपया 17 पैसे गिरकर 91.08 के स्तर पर बंद हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार, घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली का भी भारतीय मुद्रा पर दबाव दिखा है। मिरे एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी का कहना है कि आने वाले समय में रुपया 90.70 से 91.20 के बीच बना रह सकता है। (प्रेट्र)

### विदेशी मुद्रा भंडार में 2.11 अरब डालर की गिरावट

**मुंबई:** देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बीते सप्ताह 2.119 अरब डालर की गिरावट रही है। आरबीआइ के अनुसार, अब कुल विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 723.608 अरब डालर रह गया है। आरबीआइ के अनुसार, 20 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियों में 1.039 अरब डालर की कमी आई है और अब कुल विदेशी मुद्रा आस्तियां 572.564 अरब डालर रह गई हैं। इसी तरह, स्वर्ण भंडार के मूल्य में 97.7 करोड़ डालर की कमी आई है और यह घटकर 127.489 अरब डालर रह गया है। (प्रेट्र)

### पहले नौ महीनों में 47.87 अरब डालर एफडीआइ मिला

**नई दिल्ली:** चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों यानी अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान भारत को मिले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही है। शुक्रवार को जारी सरकारी डाटा के अनुसार, इस दौरान कुल 47.87 अरब डालर का एफडीआइ मिला है। अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान भारत को 40.67 अरब डालर का एफडीआइ मिला था। इस दौरान अमेरिका से मिलने वाले एफडीआइ 7.8 अरब डालर रहा है, जो अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 3.73 अरब डालर रहा है। पहले नौ माह में सिंगापुर से सबसे अधिक 17.65 अरब डालर एफडीआइ मिला है। (प्रेट्र)

# अगले वित्त वर्ष में 7.4 प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान

## मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में चार लाख करोड़ डालर हो जाएगा भारतीय आर्थिकी का आकार

- नए आधार वर्ष को ध्यान में रखते हुए अगले वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया
- आधार वर्ष 2011-12 से अगले वित्त वर्ष में 6.8-7.2 प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान था



**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली:** मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को बताया कि अगले वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार चार लाख करोड़ डालर का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए आधार वर्ष को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी में 7-7.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि पुराने आधार वर्ष (2011-12) के आधार पर यह विकास दर 6.8-7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

पिछले दो साल से आधार वर्ष को बदलने का काम किया जा रहा था। नए आधार वर्ष के तहत कृषि सेक्टर में कई नए फल-सब्जी को जोड़ा गया है। खेती के दौरान डीजल व बिजली की खपत के पैटर्न में पिछले दस सालों में काफी बदलाव हुआ है, इसलिए उनकी औसत लागत में भी बदलाव हुआ है और उसके हिसाब से उत्पादन की दर को मापा गया है। सांख्यिकीय विभाग का अनुमान है कि आधार वर्ष बदलने से चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5 प्रतिशत तक जा सकता है, जबकि पुराने आधार वर्ष में यह अनुमान 4.3 प्रतिशत का था।

शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आकार 84.53 लाख करोड़ रुपये रहा है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में जीडीपी का आकार 78.40 लाख करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की विकास दर भले ही 8.4 प्रतिशत रही, लेकिन इस अवधि में कुल जीडीपी का आकार 75.38 लाख करोड़ रुपये था।

**तीसरी तिमाही में सेक्टरवार वृद्धि (% में)**

| | |
|---|---|
| कृषि व मत्स्य | 1.4 |
| खनन | 4.7 |
| मैन्यूफैक्चरिंग | 13.3 |
| बिजली, गैस, पानी व अन्य उपभोग सेवा | 1.5 |
| कंस्ट्रक्शन | 6.6 |
| व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार सेवा | 11 |
| वित्त सेवा, रियल एस्टेट, आइटी | 11.2 |
| लोक सेवा, रक्षा व अन्य सेवाएं | 4.5 |

### मैन्यूफैक्चरिंग में सबसे अधिक 13.3 प्रतिशत रही बढ़ोतरी

तीसरी तिमाही के दौरान मैन्यूफैक्चरिंग में सबसे अधिक 13.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। सर्विस सेक्टर की विकास दर 9.5 प्रतिशत रही, लेकिन कृषि सेक्टर की विकास दर मात्र 1.7 प्रतिशत दर्ज की गई। अच्छी बात है कि निजी खपत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। तीसरी तिमाही में निजी खपत की हिस्सेदारी 48.17 लाख करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 44.31 लाख करोड़ रुपये थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भी निजी खपत 40.45 लाख करोड़ रुपये रही थी।

### आधार वर्ष में बदलाव के उद्देश्य

- डाटा के नए माध्यम को जोड़ना
- अर्थव्यवस्था के प्रारूप में होने वाले बदलाव को शामिल करना
- ताजा अंतरराष्ट्रीय मानकों के स्तर का मुकाबला करना
- राज्यों की जीडीपी के साथ जिला स्तर की जीडीपी की विस्तृत समीक्षा
- राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के उत्पादन की विस्तृत समीक्षा
- कंपनी की अलग-अलग गतिविधियों को अलग-अलग करके मापना। पहले इसे एक साथ मापा जाता था, ताकि यह पता लग सके कि जीडीपी में किन गतिविधियों का योगदान है

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

### जनवरी तक लक्ष्य के 63 प्रतिशत पर पहुंचा केंद्र का वित्तीय घाटा

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** जनवरी 2026 के अंत तक केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा 9.8 लाख करोड़ रुपये या चालू वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक लक्ष्य 63 प्रतिशत पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष समान अवधि में यह 74.5 प्रतिशत पर पहुंचा था।

केंद्र सरकार ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय घाटा (खर्च और आय के बीच का अंतर) जीडीपी का 4.4 प्रतिशत या 15.58 लाख करोड़ रुपपये रहेगा। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) की ओर से शुक्रवार को जारी डाटा के अनुसार, केंद्र को अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक 27.08 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। इस दौरान कुल खर्च 36.9 लाख करोड़ रुपये रहा है। इसमें 28.47 लाख करोड़ रुपये राजस्व खाते और 8.42 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खाते से खर्च हुए हैं। कुल खर्च में से 9.88 लाख करोड़ रुपये ब्याज भुगतान और 3.54 लाख करोड़ रुपये सब्सिडी पर खर्च हुए हैं।

## अमेरिकी टैरिफ से जुड़े नए घटनाक्रमों पर हमारी नजर

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के घटनाक्रमों पर भारत की नजर है। एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते पर संयुक्त बयान में परिस्थितियां बदलने पर समझौते का संतुलन फिर से स्थापित करने का प्रविधान है।

केंद्रीय मंत्री का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सभी व्यापारिक साझेदारों पर 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले के बाद आया है। यह अस्थायी 10 प्रतिशत टैरिफ 24 फरवरी को लागू किया गया, जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के अप्रैल 2025 में सभी आयातों पर प्रतिकारी टैरिफ लगाने के निर्णय को खारिज कर दिया था। 24 फरवरी को ही ट्रंप ने टैरिफ को 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की भी घोषणा की थी।

पीयूष गोयल

**वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, संयुक्त बयान में हालात बदलने पर समझौते का संतुलन फिर स्थापित करने का प्रविधान**

सात फरवरी को जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया था कि यदि किसी भी देश की सहमति से तय किए गए टैरिफ में कोई बदलाव होता है, तो अमेरिका और भारत सहमत हैं कि दूसरा देश अपनी प्रतिबद्धताओं को संशोधित कर सकता है।

## एसटीटी की मांग वाले फर्जी नोटिस से सतर्क रहें निवेशक : सेबी

**मुंबई, आइएएनएस:** कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) की मांग करने वाले फर्जी नोटिस और 'खाता प्रबंधन' से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि को लेकर निवेशकों को सतर्क किया है। सेबी ने कहा है कि धोखेबाजों ने फर्जी नोटिस जारी किए हैं, जिनमें बकाया एसटीटी देनदारियों का भुगतान करने की मांग की गई है। इन नोटिस में सेबी के फर्जी लेटरहेड, लोगो और मुहर का इस्तेमाल किया गया है।

सेबी ने स्पष्ट किया है कि एसटीटी को वित्त अधिनियम, 2004 के तहत प्रत्येक व्यापार के समय ब्रोकरों द्वारा स्वचालित रूप से एकत्र किया जाता है और वह एसटीटी पर मांग नोटिस जारी नहीं करता है। निवेशकों से आग्रह है कि वे ऐसे किसी भी नोटिस पर प्रतिक्रिया देने से पहले पुष्टि कर लें। सेबी के आधिकारिक ईमेल के अंत में @ sebi.gov.in होता है।

## ताजा विदेशी निकासी से लुढ़के भारतीय शेयर बाजार

**961** अंक गिरकर 81,287 पर बंद हुआ बीएसई सेंसेक्स

**317** अंक लुढ़ककर 25,178 पर आया एनएसई निफ्टी

**पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से भी सतर्कता बरत रहे निवेशक, एआइ की अनिश्चितता सुरक्षित निवेश का कर रही समर्थन**

**मुंबई, प्रेट्र:** विदेशी फंडों की ताजा निकासी और बढ़ती भूराजनीतिक चिंताओं के बीच वैश्विक संकेतों में नरमी के कारण शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स 961.42 अंक या 1.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,287.19 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में यह 1,089.46 अंक गिरकर 81,159.15 के निचले स्तर पर पहुंचा था। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 317.90 अंक या 1.25 प्रतिशत गिरकर 25,178.65 पर बंद हुआ।

जानकारों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु से जुड़े मुद्दे पर वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसने पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि कमजोर वैश्विक संकेतों और बढ़ती भू-राजनीतिक चिंताओं के बीच भारतीय बाजारों में गिरावट आ रही है, जिससे निवेशक भावना अधिक सतर्क हो गई है। एआइ से संबंधित निरंतर अनिश्चितता भी सुरक्षित निवेश की प्रवृत्तियों का समर्थन कर रही है।

सेंसेक्स में सन फार्मा, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, इंटरग्लोब एविएशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति के शेयरों में गिरावट रही। दूसरी ओर, एचसीएल टेक, ट्रेंट, इन्फोसिस और एटरनल के शेयर बढ़कर बंद हुए। एक्सचेंज डाटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) ने शुक्रवार को 2,429 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री की। बीएसई स्मालकैप सेलेक्ट सूचकांक में 0.84 प्रतिशत और मिडकैप सेलेक्ट सूचकांक में 0.71 प्रतिशत की गिरावट रही है। इस गिरावट से निवेशकों की संपत्ति में 4.98 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है। अब बीएसई का कुल पूंजीकरण घटकर 463.50 लाख करोड़ रुपये रह गया है। साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स में 1,527.51 अंक और निफ्टी में 392.6 अंक की गिरावट रही है।

**सेक्टरवार गिरावट (%में)**

| | |
|---|---|
| रियल्टी | 2.25 |
| दूरसंचार | 1.83 |
| आटो | 1.81 |
| धातु | 1.57 |
| कमोडिटीज | 1.56 |
| एफएमसीजी | 1.52 |
| वित्तीय सेवाएं | 1.50 |

### सोना 1,800 रुपये बढ़ा, चांदी दूसरे दिन भी टूटी

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** ज्वेलर्स की ताजा खरीदारी की बदौलत शुक्रवार को सोने की कीमतों में 1,800 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, अब दिल्ली में सोने का मूल्य 1,64,700 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया है। दूसरी ओर, चांदी की कीमत में लगातार दूसरे दिन 2,500 रुपये की गिरावट दर्ज की गई और अब इसका मूल्य 2.68 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।



# परमाणु ऊर्जा एक्ट के प्रविधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट आफ न्यूक्लियर एनर्जी फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया (शांति) एक्ट, 2025 के कई प्रविधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने मामले को संवेदनशील बताते हुए कहा कि इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे दूसरे देशों की तुलनात्मक नियामक व्यवस्था प्रस्तुत करें। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि 2025 का यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह निजी कंपनियों को 3000 करोड़ रुपये से अधिक के दायित्व से छूट प्रदान करता है। जबकि परमाणु दुर्घटना में नुकसान 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, भारत में पर्याप्त ऊर्जा संसाधनों की कमी है, विकास एवं इन उद्योगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। हम कोयले पर आधारित ऊर्जा संयंत्र की अनुमति नहीं देते, जंगलों से हम समझौता कर नहीं सकते, गैस हमारे पास है नहीं।

## प्रस्तावित मुख्य न्यायाधीशों का तबादला पहले होगा

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने एक नीतिगत निर्णय लिया है। जिसके अनुसार जिस जज को किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव हो, उनका तबादला पद रिक्त होने से काफी पहले, बेहतर होगा कि रिक्ति के लगभग दो महीने पूर्व ही कर दिया जाए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि संबंधित जज इस बीच उस हाई कोर्ट के कामकाज से अच्छी तरह परिचित हो सकें और निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभाल सकें। इस निर्णय के बाद, कोलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की न्यायाधीश, जस्टिस लिसा गिल को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने और रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि से उन्हें उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करने का प्रस्ताव दिया है। कोलेजियम ने केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की भी सिफारिश की है, जो पांच मार्च, 2026 को उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद प्रभावी होगा।

### न्यायाधीश बोले-मैं भूखा-थका, अब फैसले नहीं लिखा सकता

**विधि संवाददाता, जागरण, लखनऊ :** इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मंगलवार को एक दिन में अत्यधिक संख्या में सूचीबद्ध मामलों के कारण न्यायाधीश को खुली अदालत में ही अपनी असमर्थता व्यक्त करनी पड़ी। न्यायमूर्ति ने कहा- 'वह भूखे हैं और शारीरिक रूप से अत्यधिक थकान महसूस कर रहे हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लिखाना संभव नहीं है और आदेश सुरक्षित रखा जाता है।' यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने चंद्रलेखा सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की। न्यायमूर्ति विद्यार्थी के समक्ष कुल 235 मामले सूचीबद्ध थे, जिनमें 92 नए मामले, 101 नियमित, 39 ताजा विविध आवेदन व अतिरिक्त सूची में तीन मामले शामिल थे। अपराह्न सवा चार बजे तक वह केवल 29 ताजा मामलों की ही सुनवाई कर सके थे।

## यात्रा

**महाभारत अनुभव केंद्र, पंचजन्य स्मारक और लाइट एंड साउंड शो बने नई डेस्टिनेशन, पैनोरमा व श्रीकृष्ण संग्रहालय में प्राचीन भारतीय विज्ञान की दिखती है झलक**

रात में लगभग आधे घंटे चलने वाले विशेष शो में श्रीकृष्ण को विराट स्वरूप में दिखाया जाता है उपदेश देते • जागरण



पंचजन्य शंख पवित्रता और धर्म की विजय का है प्रतीक।





श्रीकृष्ण को करीब से जानना है तो संग्रहालय का रुख किया जा सकता है • जागरण

### प्रधानमंत्री ने किया था अनुभव केंद्र का उद्घाटन

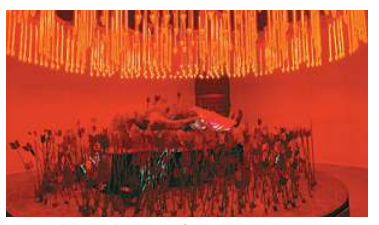

ज्योतिसर स्थित अनुभव केंद्र का उद्घाटन 16 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आनलाइन किया था। गीता जयंती के दौरे के दौरान 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अवलोकन भी किया। इसके बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया।

### भद्रकाली मंदिर से पांडवों की विजय कथा जुड़ी

आस्था का पारंपरिक केंद्र भद्रकाली शक्तिपीठ भी इस यात्रा का अहम पड़ाव है। 52 शक्तिपीठों में से एक माने जाने वाले इस मंदिर से पांडवों की विजय कथा जुड़ी है। निर्माणाधीन गीता ज्ञान मंदिर आने वाले समय में यहां की नई पहचान बनेगा।

विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

## कुरुक्षेत्र में धर्म, इतिहास और एआइ का अद्भुत अनुभव कर रहा आपका इंतजार

जीतेंद्र सिंह जीत • जागरण

**कुरुक्षेत्र:** कुरुक्षेत्र अब केवल आस्था का तीर्थ नहीं, बल्कि अनुभवों की नई डेस्टिनेशन बन चुका है। यदि आप ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां महाभारत की गूंज, आधुनिक तकनीक की चमक और इतिहास की गहराई एक साथ महसूस हो, तो यह यात्रा आपके लिए खास हो सकती है। यहां धर्म के साथ विज्ञान और एआइ का ऐसा संगम दिखाई देता है, जो तीर्थयात्रा को एक नए रूप में बदल देता है।

सबसे पहले बात नई पहचान बन चुके महाभारत अनुभव केंद्र की। ज्योतिसर स्थित इस केंद्र में महाभारत को अत्याधुनिक एलईडी, डिजिटल इंस्टालेशन और एआइ तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। पांच ब्लाक में विभाजित इस परिसर में महाभारत के 18 दिनों का युद्ध, द्रौपदी स्वयंवर, श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद, भीष्म पितामह की शैय्या और गीता उपदेश जैसे प्रसंग प्रभावी चलचित्रों में जीवंत हो उठते हैं। ई-ब्लाक की खासियत एआइ आधारित इंटरएक्टिव प्रणाली है, जहां दर्शक सवाल पूछते हैं और उन्हें डिजिटल माध्यम से जवाब मिलते हैं। लगभग पांच मीटर ऊंचा पंचजन्य शंख, जिस पर गीता के 18 श्लोक अंकित हैं, धर्म की विजय का प्रतीक बनकर खड़ा है। वहीं, 40 फीट ऊंचा और 35 टन वजनी श्रीकृष्ण का विराट स्वरूप रात के प्रकाश और ध्वनि संयोजन में महाभारत के प्रसंगों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। शाम ढलते ही ज्योतिसर का लाइट एंड साउंड शो यात्रा को और रोचक बना देता है। तालाब के जल पर रंगीन रोशनियों से उभरते दृश्य और आधुनिक साउंड सिस्टम के साथ महाभारत की कथा इस तरह प्रस्तुत होती है कि पात्र मानो सामने जीवित हों।



अनुभव केंद्र में शैय्या पर भीष्म पितामह • जागरण

शहर के मध्य, ब्रह्मसरोवर के निकट बना कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र भी देखने योग्य है। बेलनाकार इमारत में स्थापित इस केंद्र में परमाणु संरचना, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, सर्जरी और गणित से जुड़ी अवधारणाओं को इंटरेक्टिव माडलों के जरिये समझाया गया है।

श्रीकृष्ण संग्रहालय संग्रहालय श्रीकृष्ण, महाभारत और कुरुक्षेत्र से जुड़े पौराणिक और पुरातात्विक साक्ष्यों को समेटे है।

जगमगाता ब्रह्मसरोवर

### ऐसे पहुंचें धर्मनगरी और ये हैं ठहरने की व्यवस्थाएं

निजी वाहन से नेशनल हाईवे-44 से कुरुक्षेत्र पहुंचा जा सकता है। यहां के लिए बस, टैक्सी की सुविधा भी आसानी से मिल जाती है। दिल्ली से ट्रेन के माध्यम से कुरुक्षेत्र पहुंचा जा सकता है। विमान यात्रियों के लिए नजदीकी एयरपोर्ट चंडीगढ़ है। पर्यटकों के लिए बजट होटल और अच्छी धर्मशालाएं हैं।

## आज का भविष्यफल: 28 फरवरी, 2026 शनिवार

पं. के.ए. दुबे पद्मेश

**आज की ग्रह स्थिति:** फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी का राशिफल।
**आज का राहुकाल:** प्रातः 09 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक।
**आज का दिशाशूल:** पूर्व।
**विशेष:** श्याम वाले खाटू बाबा का मेला निकट जयपुर।

**कल 01 मार्च, 2026 का पंचांग**

**कल का दिशाशूल:** पश्चिम
**कल का पर्व एवं त्योहार:** रवि प्रदोष व्रत
**विशेष:** शुक्र मीन में।
विक्रम संवत 2082 शके 1947 उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तत्पश्चात चतुर्दशी, पुष्य नक्षत्र तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र, शोभन योग तत्पश्चात अतिगंड योग, कर्क में चंद्रमा।

**मेष:** शुक्र, शनि की युति स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। मौसमी रोग के प्रति सचेत रहें।

**वृष:** आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा।

**मिथुन:** अधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। प्रयास फलीभूत होगा।

**कर्क:** बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा।

**सिंह:** स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में सचेत रहें।

**कन्या:** व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।

**तुला:** पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। प्रयास फलीभूत होंगे। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा।

**वृश्चिक:** सुखद समाचार मिलेगा। गुरु का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी।

**धनु:** अनचाही यात्रा भी करनी पड़ सकती है। पारिवारिक कार्यों में व्यस्त भी हो सकते हैं।

**मकर:** जीवनसाथी का सहयोग और सान्निध्य भी मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी।

**कुंभ:** स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यात्रा देशाटन के प्रति सचेत रहें।

**मीन:** व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सेहत से सचेत रहें।

## वर्ग पहेली-3263

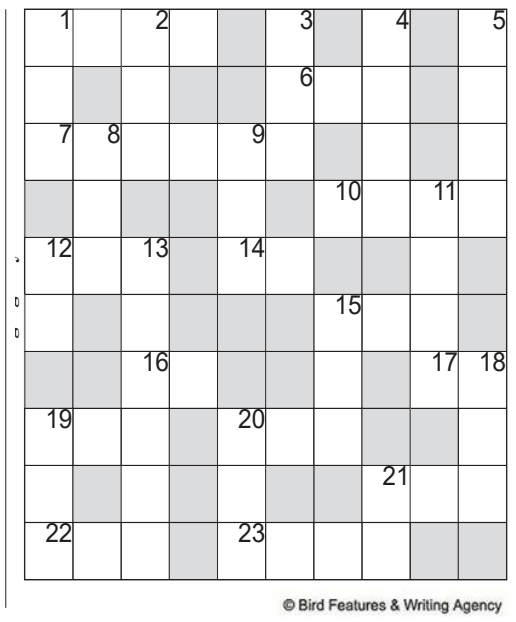



© Bird Features & Writing Agency

**बाएं से दाएं**
1 एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के नाम का पहला शब्द (4)।
6 उमंग, तरंग (3)।
7 मान-मर्यादा की रक्षा करना (2,2,2)। 10 पत्नी, भार्या (4)।
12 बिना नाम का (3)।
14 समय, मृत्यु (2)।
15 अत्यंत, प्रधान (3)।
16 माता लक्ष्मी (2)।
17 अल्प, थोड़ा सा (2)।
19 एक प्रसिद्ध समाजसेवी के नाम का उपनाम (3)।
20 आग, अग्नि (3)।
21 भीरु, डरा हुआ (3)।
22 एक देवी का नाम (3)।
23 मनाने की कार्य (4)।

**ऊपर से नीचे**
1 एक अभिनेत्री के नाम का पहला शब्द (3)।
2 रांगा को यह भी कहते हैं (3)।
3 सुंदर नारी या स्त्री (3)।
4 चिंता, फिक्र (4)।
5 रामायण में वर्णित कैकसी की बहू (4)।
8 कार्य में लगना (3)। 9 लेखक का स्त्री रूप (3)। 11 बच्चों की एक पत्रिका (4)।
12 अभी, इस समय (2)। 13 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक समाज सेविका (3,3)। 15 शुरुआत (3)। 18 घड़ियाल, परंतु, लेकिन (3)। 19 संसार, दुनिया, विश्व (3)। 20 इस राज्य की राजधानी दिसपुर है (3)। 21 पांच ज्ञानेंद्रियों में से एक (2)।

**कल का हल**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रा | ज | दं | ड | | मा | त | | |
| | श | | | रा | | | र | ज | नी |
| म | न | सा | | व | गै | र | ह | | लां |
| य | | म्य | | ना | | | | | ब |
| | | वा | | | | क | च | ना | र |
| लं | बो | द | र | | | | ह | | |
| का | | | | | अ | | क | | त |
| प | | त | र | स | ना | | ना | थ | ना |
| ति | मि | र | | | ग | | | म | |
| | | ह | रा | | त | रे | र | ना | |

## सुडोकू-3263

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 6 | | 2 | | 9 | 8 | |
| | 2 | | | | | | | 6 |
| | | 9 | | | 4 | 1 | | 3 |
| 8 | | | 5 | | | | | |
| | 3 | | | 1 | | 6 | | 5 |
| 5 | | 1 | 4 | | | | 9 | |
| | 4 | | | | 5 | | 3 | 1 |
| | 1 | | 2 | | 6 | | | |
| 9 | | 2 | | 3 | | | 6 | |

**कल का हल**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| 3 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 |
| 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 |

महाराष्ट्र टाइम्स

# आखाती संतुलनाचे आव्हान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इस्रायल दौरा हा दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये पुढचे पाऊल टाकणारा ठरला. सध्याच्या गढूळ आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमध्ये पार पडलेल्या या दौऱ्याने शांतता आणि आखातातील संतुलनाचे महत्त्व दृगोच्चर होते, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. एकीकडे गाझापट्टीतील दीर्घ काळ लांबलेले युद्ध आणि दुसरीकडे अमेरिका-इराण यांच्यातील युद्धस्थितीचे दाटून आलेले ढग, या पार्श्वभूमीवर भारतीय पंतप्रधानांच्या दौऱ्यास मोठे महत्त्व प्राप्त झाले होते. या वेगवेगळ्या तणावांमध्ये भारत नेमकी कोणती भूमिका घेणार, याबाबत अनेक देशांना उत्सुकता होती. मोदी यांनी आपल्या दौऱ्यात काही प्रश्नांवर ठोस, तर काही विषयांवर संतुलित भूमिका मांडली. 'दहशतवादाच्या विरोधात दुटप्पी भूमिका घेता येणार नाही,' असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला आहे. भारत आणि इस्रायलमधील विरोधकांकडून हा दौरा आणि मोदींचे भाषण यांवरून झालेला विरोध हा या विषयावरील संमिश्र भावनांची साक्ष देतो. मात्र, हे वादाचे विषय वगळता विविध क्षेत्रांमधील दोन्ही देशांचे सहकार्य या दौऱ्याने वाढीस लागेल, अशी आशा आहे. विशेषतः भारत-इस्रायलमधील मुक्त व्यापार कराराचे सूतोवाच, हे मोदी यांच्या भेटीचे फलित म्हणावे लागेल.

इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्या संघर्षात पूर्वीपासून भारत पॅलेस्टिनींचा पक्ष घेत आहे. तीन दशकांपूर्वी बदलत्या परिस्थितीत भारताने यामध्ये संतुलित भूमिका घेतली. विशेषतः संरक्षण आणि कृषी अशा क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांचे सहकार्य वाढीस लागले असून दहशतवादाचा सामना करतानाही भारताला वेळोवेळी इस्रायलचा सक्रिय पाठिंबा लाभला आहे. अपेक्षेप्रमाणे या दौऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. त्यामध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञानातील संशोधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम फिजिक्स आणि दुर्मीळ खनिजे अशा विषयांमध्ये सहकार्य, वस्तू व सेवांची देवाणघेवाण, सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करणे आणि बौद्धिक स्वामित्वाच्या नियमांसारखे व्यापारातील अडथळे दूर करणे अशा मुद्द्यांचा समावेश आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील सहकार्यवाढीसाठी मंत्रालय पातळीवर समिती, आर्थिक संवाद आणि कृषी संशोधनाबाबत फेलोशिप, याबरोबरच येत्या काळात ५० हजार भारतीयांना इस्रायलमध्ये प्रवेश आणि शैक्षणिक सहकार्याचे व्यासपीठ आणि संसदीय मैत्री गटाची स्थापना अशी पावले उचलण्यात येणार आहेत. संरक्षण क्षेत्रात प्रगत इस्रायली तंत्रज्ञानाचा भारताला वेळोवेळी उपयोग झाला असल्याने या दौऱ्यात त्याविषयी चर्चा झाली. त्यासह भारतीय 'युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस'चा (यूपीआय) इस्रायलमध्ये वापराचा मार्गही खुला झाला आहे. दुसरीकडे गाझामधील मानवाधिकार उल्लंघनावरून जगभरात टीकेचे धनी बनलेले इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना भारतासारख्या देशाचा नैतिक पाठिंबा या दौऱ्यातून मिळाला असून भारताच्या मोठ्या बाजारपेठेतील त्यांचा मार्गही सुकर होणार आहे.

एकीकडे दहशतवादविरोधी लढ्यातील सहकारी इस्रायलशी सहकार्य आणि दुसरीकडे इस्रायलशी उभे वैर असलेल्या आखाती देशांशी पूर्वीपासून असलेले मैत्रिपूर्ण संबध राखणे, या पार्श्वभूमीवर सन २०१७नंतर झालेल्या पंतप्रधानांच्या इस्रायल भेटीमध्ये उत्सुकता होती. मोदी यांनी 'हमास' च्या हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबीयांशी सहवेदना व्यक्त केली; तसेच गाझा शांतता मंडळाच्या पावलांचे



समर्थनही केले. मात्र, गाझामध्ये इस्रायलकडून करण्यात आलेल्या नरसंहारामध्ये ७२ हजार जणांचा बळी गेला असून, त्यामध्ये महिला व लहान मुलांचाही समावेश आहे. त्याबाबत मोदी यांनी स्पष्ट उल्लेख केला नाही. त्याबाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. नेतान्याहू यांच्या विरोधकांनी मोदी यांच्या भाषणापूर्वी सभात्याग केला; तसेच भारतातही काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे. 'गाझामध्ये हजारो पॅलेस्टिनींना उपासमारीची शिक्षा देणाऱ्या राजवटीचे समर्थन करणारा देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाऊ नये,' अशी अपेक्षा विरोधकांकडून व्यक्त झाली आहे. अर्थात, जगातील अनेक संघर्षांमध्ये भारताने 'शांततेचा पक्ष' निवडला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारताने पॅलेस्टाइनमध्ये हाती घेतलेले २१ कोटी डॉलरचे प्रकल्प हे या संतुलनाचे साक्षीदार आहेत. सौदी अरेबिया आणि कतारसारखे देश भारताचे विश्वासू भागीदार असून, लाखो भारतीयांना आखाती देशांमध्ये रोजगार मिळत आहे. या देशांनीही भारताच्या भूमिकेबाबत आक्षेप घेतलेला नाही, हे महत्त्वाचे. इराणमधील चाबहार बंदरासह भारताचे प्रदेशातील हितसंबंध कळीचे आहेत. इराण व अमेरिकेतील तणाव आणि त्यातील इस्रायलची सक्रिय भूमिका यांचाही विचार महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच दहशतवादाला ठाम विरोध, मानवाधिकारांचे रक्षण आणि इस्रायल-आखाती देशांमधील हितसंबंधांची जोपासना असे संतुलन आवश्यक आहे. केवळ 'हिंदू-मुस्लिम'सारख्या चष्म्यातून याकडे पाहणे उथळपणाचे ठरेल.

# विश्वासार्हतेवरील ओरखडे

साक्षेप

■ पराग करंदीकर @ParagKMT





गेल्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय या विषयावरील जागतिक परिषद पार पडली. जगभरातील धोरणकर्ते, तंत्रज्ञ, संशोधक, उद्योगपती आणि धोरणविशारद एका छताखाली जमले होते. येत्या काळात एआयमुळे जगण्यामध्ये काय बदल होणार, रोजगाराचे स्वरूप कसे बदलेल, आरोग्य, शेती, शिक्षण, संरक्षण या क्षेत्रांमध्ये कोणती क्रांती घडू शकते, डेटा सार्वभौमत्व आणि नैतिकता यांचे प्रश्न कसे हाताळायचे—अशा असंख्य मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

ही परिषद भारतासाठी एक प्रकारे जागतिक स्तरावर आपली ताकद दाखविण्याची मोठी संधी होती. जग एआयच्या नव्या पर्वात प्रवेश करत असताना भारत स्वतःला केवळ ग्राहक नव्हे तर निर्माता म्हणून स्वतःची प्रतिमा जगासमोर या निमित्ताने मांडणार होता. मात्र या परिषदेदरम्यान घडलेल्या दोन घटनांनी या परिषदेतील मूळ गाभा बाजूला राहिला आणि चर्चा भलतीकडेच भरकटली.

पहिली घटना—एका खासगी विद्यापीठाने आपल्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेला यंत्रमानव म्हणून सादर केलेली यंत्रणा प्रत्यक्षात चिनी बनावटीची असल्याचे उघड झाले. आणि दुसरी घटना—युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेशी केलेल्या व्यापार करारामध्ये भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचा सौदा केल्याच्या आरोपावरून केलेली अर्धनग्न निदर्शने.

या दोन घटना वरवर वेगळ्या दिसतात. एक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील, दुसरी राजकीय आंदोलनाची. पण त्या दोन्ही आपल्या देशातील दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांची मानसिकता उघड करतात. एआय परिषद म्हणजे ज्ञान, नवोन्मेष, प्रामाणिक संशोधन आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेचा मंच. अशा वेळी एका संस्थेने चिनी बनावटीचा यंत्रमानव स्वतःच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केला असल्याचे सांगणे, आणि तो बनाव लगेचच उघडा पडणे—ही केवळ एक चूक नाही. तर देशाच्या विश्वासार्हतेवरील ओरखडा उठविण्यासारखी घटना होती. आपण 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्टार्ट-अप इंडिया' या घोषणांमधून आत्मविश्वासाचा संदेश देत असताना परकीय उत्पादनाला 'आपले' म्हणून मिरवावे लागत असेल, तर आपण नक्की कोठे उभे आहोत असा प्रश्न निर्माण होतो. संशोधन आणि विकास ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असते. त्यामध्ये वेळ लागतो, अपयश येते, पुनरावलोकन करावे लागते. पण शॉर्टकट घेण्याची मानसिकता वाढत आहे का? जागतिक मंचावर चमकण्यासाठी आपण कृत्रिम चमक तयार करतो आहोत का, असे प्रश्न पडतात.

या परिषदेपूर्वी दावोस येथे झालेल्या गुंतवणूक परिषदेमध्ये भारताचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राच्या विकासासाठी भारत सरकार काय करते आहे, हे सविस्तर सांगितले होते. भारत ही या पुढे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या जागतिक कंपन्यांसाठी बाजारपेठ नसेल तर या क्षेत्रामध्ये योगदान देणारा एक महत्त्वाचा देश असेल, असे वातावरण या परिषदेपूर्वी करण्यामध्ये भारताने यश मिळविले होते. त्याचाच परिणाम म्हणून जागतिक स्तरावर या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या बहुतेक सर्व कंपन्यांचे सीईओ या परिषदेमध्ये सहभागी झाले होते, पण एका बनावट सादरीकरणाने या सगळ्यावर पाणी पडते की काय असे वातावरण तयार झाले. तंत्रज्ञानातील प्रगतीपेक्षा प्रामाणिकतेची पायाभरणी महत्त्वाची आहे, हेच या निमित्ताने अधोरेखित झाले असे म्हणण्याची वेळ या विद्यापीठाने देशावरच नव्हे तर जगावर आणली.

> 'या' दोन्ही घटना एकत्रित पाहिल्या तर एक विचित्र चित्र दिसते. एका बाजूला तंत्रज्ञानाच्या शिखरावर पोहोचण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि दुसऱ्या बाजूला विश्वासार्हतेतील ढासळलेली पायाभरणी...

दुसरी घटना होती ती युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केलेल्या अर्धनग्न निदर्शनांची. लोकशाहीमध्ये आंदोलनाचा अधिकार मान्य आहे. एखाद्या व्यापार कराराविषयी मतभेद असू शकतात. शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रश्न उपस्थित करणे हे राजकीयदृष्ट्या वैध असू शकते. पण एआयसारख्या जागतिक परिषदेमध्ये, जगाचे लक्ष लागले असताना, अशा प्रकारे अर्धनग्न निदर्शने करणे—यातून नेमका कोणता संदेश गेला, याचाही गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. आपण पंतप्रधानांना विरोध करण्यासाठी जागतिक स्तरावर आपल्या देशाच्या प्रतिमेशी खेळतो आहोत का, याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे.

आपण एआयच्या भविष्यावर चर्चा करतो आहोत, आणि त्याच मंचावर आपले राजकीय मतभेद अशा नागड्या स्वरूपात व्यक्त होतात, हे दृश्य जगाने पाहिले. आंदोलन योग्य की अयोग्य, हा प्रश्न नाही; मुद्दा आहे तो आंदोलनाची पद्धत आणि संदर्भ किती विचारपूर्वक निवडले गेले, हा. एआय परिषद ही केवळ सरकारची नव्हे, तर देशाची होती. अशा वेळी आपण जागतिक प्रतिमेचा विचार करणार की नाही? प्रत्येक मंच हा तात्कालिक राजकीय स्पर्धा करण्यासाठी व आपली वैयक्तिक लढाई लढण्यासाठी असावा का, याचा विचार या देशावर अनेक वर्षे राज्य करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने करायला नको? एकेकाळी या काँग्रेसचे पंतप्रधान असलेल्या नरसिंह राव यांनी विरोधी पक्षनेते असलेल्या भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी यांना संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताची बाजू मांडण्यासाठी गेलेल्या शिष्यमंडळाचे नेतृत्व सोपवून वेगळा संदेश दिला होता.

अगदी अलीकडे झालेल्या ऑपरेशन सिंदूर नंतर जगातील विविध देशांमध्ये गेलेल्या शिष्टमंडळामध्ये विविध पक्षांचे खासदार सहभागी झाले होते. काही विरोधी पक्षातील खासदारांनी या शिष्टमंडळांचे नेतृत्वही केले. आपला देश कसा चालवायचा याबद्दल मतमतांतरे असूच शकतात. ती असलीही पाहिजेत, पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या देशाची प्रतिमा टिकविण्याची जबाबदारी सर्वांनीच घेतली पाहिजे.

या दोन्ही घटना एकत्रित पाहिल्या तर एक विचित्र चित्र दिसते. एका बाजूला तंत्रज्ञानाच्या शिखरावर पोहोचण्याची महत्त्वाकांक्षा; दुसऱ्या बाजूला विश्वासार्हतेतील ढासळलेली पायाभरणी. एका बाजूला जागतिक नेतृत्वाचे स्वप्न; दुसऱ्या बाजूला अंतर्गत राजकीय अस्वस्थतेचे प्रात्यक्षिक. आपण एआयच्या नैतिकतेवर चर्चा करतो, पण आपल्या कृतींची नैतिकता तपासतो का? जगात एआयमुळे रोजगार बदलतील, निर्णयप्रक्रिया वेगवान होईल, प्रशासन डेटा-आधारित होईल, असे सांगितले जाते. पण या तंत्रज्ञानाला स्वीकारण्यासाठी समाजाची मानसिक तयारी आहे का? एआय म्हणजे फक्त तांत्रिक कौशल्य नाही; तो विश्वासाचा विषय आहे. डेटा कोणाचा, नियंत्रण कोणाचे, उत्तरदायित्व कोणाचे—हे प्रश्न तितकेच महत्त्वाचे. आणि अशा वेळी जर आपल्या संस्थांकडूनच प्रामाणिकतेचा अभाव दिसला, तर आपण एआयच्या नैतिक चौकटीबद्दल काय संदेश देतो?

राजकीय क्षेत्रातही तेच लागू होते. लोकशाहीतील असहमती महत्त्वाची आहे. पण ती व्यक्त करताना काही मर्यादा पाळणेही तितकेच आवश्यक आहे. संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या सत्रामध्ये झालेल्या घटना, पंतप्रधानांचे टळलेले भाषण हे सगळेच या मर्यादा ओलांडल्या जात असल्याचेच निदर्शक आहे.

एआय येणाऱ्या काळात आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग होणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग, प्रशासन—सर्वत्र त्याचा प्रभाव वाढणार आहे. पण तंत्रज्ञानाची प्रगती ही समाजाच्या परिपक्वतेशी जोडलेली असते. आपण एआयमध्ये आघाडी घेण्याची भाषा करतो आहोत. पण आपण स्वतःशी प्रामाणिक राहण्याची तयारी दाखवतो आहोत का? एआय परिषद संपली. चर्चेचे मुद्दे कागदावर राहतील. करार पुढे सरकतील. पण त्या मंचावर घडलेल्या दोन घटनांनी एक वेगळाच प्रश्न उपस्थित केला आहे - तंत्रज्ञानाने आपल्याला स्मार्ट बनविले तरीही समाज म्हणून ते स्वीकारण्याची आपली तयारी पूर्ण झाली आहे का? कदाचित पुढील काही वर्षांत एआय आपल्या शहरांना, उद्योगांना आणि प्रशासनाला अधिक कार्यक्षम करील. पण आपल्या सार्वजनिक जीवनाला अधिक जबाबदार, अधिक प्रामाणिक आणि अधिक सुसंस्कृत बनवण्याचे काम कोण करणार, हा प्रश्न आज अनुत्तरितच आहे.

parag.karandikar@timesofindia.com

## बहुतांची अंतरे

### 'कलासंगम'मध्ये मराठीचा जागर

ज्येष्ठ साहित्यिक कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून २७ फेब्रुवारीला महाराष्ट्रात 'मराठी भाषा दिन' मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यावर्षी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शिवाजी महाराज यांची जयंती व मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून 'महाराष्ट्र टाइम्स' तर्फे 'माय मराठी कला संगम' हा आयोजित केलेला सोहळा म्हणजे 'अभिमान संस्कृतीचा, ध्यास प्रगतीचा' या घोषवाक्याने झालेला मराठी संस्कृतीचा पुनर्जन्म होय. या सोहळ्यात 'मराठी पाऊल पडते पुढे' हा पोवाडा प्रत्यक्ष अवतरला. दुसरीकडे मराठी भाषेला मिळालेला अभिजात दर्जा हा केवळ कागदोपत्री आहे. बंद पडलेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळा पुन्हा नव्या जोमाने चालू होतील तेव्हाच वैभवशाली मराठी खऱ्या अर्थाने जिवंत होईल.

**– सूर्यकांत भोसले,** मुलुंड (पूर्व)

### शेख यांचे काम स्पृहणीय

मराठी भाषा दिना निमित्ताने मधुरा वेलणकर यांच्या 'इनक्रेडिबल मराठी' या यू-ट्यूब चॅनलवर गेले आठवडाभर खास मराठी भाषेविषयी भाग चालू होते. त्यातला शंभरावा भाग फारच विशेष होता कारण मधुरा वेलणकर यांनी १०१ वर्षांच्या मराठी भाषा तपस्विनी यास्मिन शेख यांच्याबरोबर झालेल्या प्रत्यक्ष भेटीतील मराठी भाषेविषयीच्या मुलाखतीचा संदर्भ होता. यास्मिन शेख यांनी मुलाखतीत मराठी भाषा बोलताना लिहिताना होणाऱ्या चुका सांगितल्या. त्यातील एक लक्षणीय चूक म्हणजे आपण मराठी 'भाषिक' नाही, आपण मराठी बोलणारे 'भाषक' आहोत. भाषक हे नाम आहे तर भाषिक हे विशेषण आहे. यास्मिन शेख यांचे मराठी विषयीचे ज्ञान खरच गौरवास्पद आहे.

**– श्रीनिवास डोंगरे,** दादर

### प्रसाद ओक यांचे कौतुक

अलीकडेच मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी अभिमानाची बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध अभिनेते प्रसाद ओक यांना धर्मवीर या चित्रपटातील उत्कृष्ट अभिनयासाठी अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. या चित्रपटाला एकाच वेळी सर्वाधिक पुरस्कार मिळाल्याची नोंद झाली असून 'इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स' आणि 'ग्लोबल बुक ऑफ एक्सलन्स, इंग्लंड' या दोन्ही ठिकाणी या विश्वविक्रमाची नोंद करण्यात आली आहे. ही खरंच अभिमानाची बाब आहे.

**– सुभाष बबन जगताप,** ठाणे

### रटाळ 'बिग बॉस'

अगोदरच्या पाच सीझनच्या तुलनेत सहावा सीझन अतिशय रटाळ होत आहे. स्पर्धकांना वादविवाद करताच येत नाही, केवळ आक्रस्ताळेपणा व गोंगाट याच अस्त्राचा उपयोग कुठलाच खेळ व्यवस्थित पूर्ण न करता विस्कळीत करत आहेत. नुकताच संपलेला हिंदी बिग बॉस स्पर्धकांनी अतिशय रोचक केला होता, किमान त्याचे तरी अनुकरण करावे.

**– दिलीप श्रीपत कदम,** कांदिवली

# उलटलेली 'गोळी'

धावते जग

आपल्या देशात सन १९६१मध्ये केंद्र सरकारने 'राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद' (एनसीईआरटी) स्थापन केली. या संस्थेपुढील एक उद्दिष्ट, देशात गुणात्मक शैक्षणिक विकास साधण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांना सल्ला देणे, हे आहे. हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवणाऱ्या या संस्थेला 'न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार' अशा शीर्षकांतर्गत एक दीर्घ वेचा आठवीच्या पुस्तकात देण्याची दुर्बुद्धी का झाली असावी? अर्थात, अशी दुर्बुद्धी 'एनसीईआरटी'ला आजवर अनेकदा झालेली आहे. मात्र, या वेळी थेट न्यायपालिकेवरच 'एनसीईआरटी'ने गोळी झाडल्याने त्याचे अतितीव्र पडसाद उमटले. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने 'एनसीईआरटी'ला धारेवर धरत संबंधित पुस्तकावर बंदीचे आदेश दिले. वास्तविक याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तातडीने त्याबाबत दिलगिरी व्यक्त करणे आवश्यक होते. मात्र, त्यासाठी प्रधान बहुदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या उग्रावताराची प्रतीक्षा करत असावेत! 'एनसीईआरटी' ही 'स्वायत्त' संस्था असली तरी असल्या संस्थांची 'स्वायत्तता' काय दर्जाची आहे, हे गेल्या काही वर्षांत ठळकपणे समोर येत आहे. 'सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल भूमिका घेणे' असा नवा अर्थ अनेक स्वायत्त संस्थांनी सध्या लावलेला दिसतो; 'एनसीईआरटी' त्यातलीच एक. या साऱ्या गदारोळात कळीचा मुद्दा न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा. न्यायव्यवस्थेभोवती संरक्षणाची कितीही तटबंदी असली तरी त्यातील भ्रष्टाचारावर टीका होतच आली आहे नि होतच राहणार. या टीकेस भरभक्कम आधारही आहे. खालच्या न्यायालयांपासून वरच्या न्यायालयांपर्यंत त्याचे दाखले मिळतात. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेने स्वतःवरील टीकेबाबत अतिहळवे असू नये. येथे मुद्दा आहे तो 'एनसीईआरटी'ने आठवीच्या समाजशास्त्र विषयाच्या पुस्तकात अशा विषयाला हात घालण्याचा. असले धडे शिकवून विद्यार्थ्यांच्या मनात न्यायव्यवस्थेविषयी अविश्वास, तुच्छता निर्माण होऊ शकते, याची जाणीव 'एनसीईआरटी'मधील अतिशहाण्यांना नसावी? मुळात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराकडे अंगुलिनिर्देश करणाऱ्या 'एनसीईआरटी'ला शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आजवर दिसलेला नाही का? इथे दुःख भ्रष्टाचाराच्या वेच्याचे नाही; दुःख असल्या संस्था सोकावतात, हे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, 'ही न्यायव्यवस्थेवर झाडलेली गोळी आहे'. ही गोळी 'एनसीईआरटी'वरच उलटली आहे; त्यातून तेथील अतिशहाणे काही धडा घेतील, ही अपेक्षा.

# कागाळी

शब्दकळा

'अमका ढमका माझ्याविरुद्ध विनाकारण तक्रारी करतोय' ही भावना तुम्ही जगातल्या कुठल्याही भाषेत ओवून बघा. त्यासाठी चपखल शब्द हुडकून बघा. त्यास आपल्या मराठीतील 'कागाळी' या शब्दाइतका चपखल शब्द मिळाला कुठल्या भाषेत तर पैज हरायला तय्यार! (अर्थात, आपल्या मराठीतच चुगली, कळ लावणे, लावालावी असे कागाळी या शब्दाचे भाऊबंद मुबलक प्रमाणात आहेत. तेदेखील कागाळीइतकेच इरसाल आहेत. कागाळीप्रमाणेच स्वतःचे ठसठशीत व्यक्तिमत्त्व असलेले आहेत. त्यांचा मुबलक वापरदेखील केला जातो.) कारण कागाळी हा शब्द आहेच तसा. त्यात केवळ तक्रार येत नाही. तक्रार म्हणजे कसे शिस्तशीर वाटते. या शब्दास एक सरकारी, औपचारिक ढब आहे. पण, कागाळी म्हटली की ज्याच्यावर कागाळी केल्याचा ठपका ठेवला जातो, त्याच्याविरोधातच तक्रारीचा सूर असतो! म्हणजे, तो ज्या काही तक्रारी करतोय त्या एक तर खोट्या आहेत, किंवा मग तक्रारी करण्यामागे काही वाईट हेतू आहेत, ही धारणा असते. या शब्दाचा उगम शोधताना, वेगवेगळे संदर्भ मिळतात. 'कळ लावणे' आणि 'कागाळी' या दोन शब्दांतील साम्य चटकन लक्षात येणारे. दुसरा एक संदर्भ अगदीच वेगळ्या रीतीने हाती लागतो. 'काग' या शब्दापासून त्याचा उगम झाला असावा, असेही मानले जाते. 'काग' म्हणजे कावळा, हे तर सगळ्यांना ठाऊक असेलच. कावळा ज्या पद्धतीने कावकाव असा कर्कश आवाज करतो... विनाकारण ओरडतो... कर्कश आवाज करीत सगळ्यांना त्रास देतो, त्या संदर्भाने 'कागाळी' हा शब्द आला असावा, नि प्रचलित झाला असावा, असे काही जण सुचवतात. आता हा बिचारा कावळा त्याच्या बोलीने ओरडतो तर तो कोणाविरोधात तरी ओरडतो आहे, अशी धारणा कुणाची नि का झाली असेल, ते कळायला मार्ग नाही. कावळ्याच्या दृष्टीला 'काकदृष्टी' असा शब्द वापरतात, पण तो चांगल्या अर्थाने. त्यामुळे या कागाळीसारख्या कृतीसाठी लोकांनी बिचाऱ्या कावळ्याला वेठीस का धरले असावे, याचा अंदाज येत नाही. कुणास ठाऊक, या अशा कृतीसाठी कावळा देखील कागाळी करीत असेल!

रोहन पोरे



# एका पुतळ्याच्या निमित्तानं...

राजधानीतून

■ मंगेश वैशंपायन

> राजधानीतील ल्युटियन्स यांचा पुतळा हटवून तेथे राजाजी यांचा पुतळा बसवण्यात आला; पण भारताच्या राष्ट्रप्रमुखांसाठी याच ल्युटियन्सनं उभारलेल्या राष्ट्रपती भवनाला पर्याय शोधण्याचा विचार अद्याप तरी समोर आलेला नाही! पुतळ्यांपेक्षा मूल्यं जपणं महत्त्वाचं, हा सांगावा ल्युटियन्स ते राजाजी या प्रवासानं दिलाय.

राजधानीतल्या मुघल गार्डनला 'अमृत उद्यान' असं नाव देण्यात आलं, त्यापाठोपाठ राष्ट्रपती भवन परिसरातला ब्रिटिश वास्तुशिल्पकार एडविन ल्युटियन्स यांचा पुतळा हटवून त्या ठिकाणी स्वतंत्र भारताचे पहिले व एकमेव भारतीय गव्हर्नर-जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उर्फ राजाजी यांचा पुतळा उभारण्यात आला. तिथून जेमतेम एका किलोमीटरवर किंग जॉर्जच्या नावाच्या रस्त्यालाही राजाजींचं नाव दिलं गेलं. या ताज्या घटनेकडे केवळ 'एक पुतळा गेला, दुसरा आला' असं वरवर पाहता येणार नाही. सार्वजनिक स्मृतीच्या केंद्रस्थानी कोण असावं, हा प्रश्न यातून पुन्हा ऐरणीवर येतो, या अंगानं या छोट्या वाटणाऱ्या घटनेकडं पहायला हवं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती भवनातील अलीकडील इतर बदलांकडेही लक्ष वेधले, ज्यात ब्रिटीश अधिकाऱ्यांच्या छायाचित्रांच्या जागी परमवीरचक्र विजेत्यांची छायाचित्रं लावणं यासारख्या निर्णयांचा समावेश आहे.

ल्युटियन्स यांचे पणतू, ब्रिटिश विज्ञान लेखक मॅट रिडले यांनी या बदलाबद्दल खंत व्यक्त करताना, त्यांच्या पणजोबांचं नाव पुतळ्याच्या पट्टीवरून आधीच काढून टाकण्यात आलं होतं, याकडेही लक्ष वेधलं. एखादा पुतळा हा त्या त्या देशाच्या सत्ता, स्मृती आणि मूल्यांचाही दृश्यमान पुरावा असतो. कोणत्याही राष्ट्रीय राजधानीच्या मध्यभागी कोणाचा पुतळा उभा आहे, त्यावर त्या त्या देशाच्या आत्मभानाचा उद्गार एका रीतीने ठरत असतो. केवळ तत्कालीन संसदेतले भव्य खांब जवळून पाहिले तरी ल्युटियन्स यांनी नवी दिल्लीची रचना करताना उभारलेल्या वास्तुशैलीच्या भव्यतेचा अंदाज येतो. ल्युटियन्स यांचा पुतळा हटवून त्याजागी राजाजींचा पुतळा उभारणं हा वसाहतवादी,



गुलामगिरीच्या मानसिकतेला मूठमाती देण्याच्या प्रवासातील पुढचा अध्याय आहे, यात शंका नाही. पण त्या दृष्टीने चेम्सफोर्ड, इरविन दाम्पत्य, कॅनिंग, फ्लॅग स्टाफ, मिंटो व त्यांच्याही आधीच्या औरंगजेबापासून (लेन) हुमायू, शाहजहान, अकबर आणि खुद्द बाबर आदींच्या नावाच्या खाणाखुणाही दिल्लीत बदलाची वाट पाहत असणार. बाबर हा फक्त आक्रमक होता. त्याच्या नावाने या देशात एकही गल्ली, रस्ता, गाव नसावं, हा खुद्द राममनोहर लोहियांचा विचार होता.

इथे मुद्दा वेगळा आहे. नाव बदललं तरी दिल्लीच्या एपीजे अब्दुल कलाम रस्त्यावरची अतिक्रमणं, फेरीवाले पूर्ण हटले का? त्या रस्त्यावरच्या दैनंदिन जीवनातील समस्या दूर झाल्या का? नसेल तर एखादं ठिकाण नावापुरतंच 'प्रेरणास्थळ' बनण्याची शक्यता जास्त. पुतळे बदलले की मानसिकता बदलते का, हा यानिमित्तानं पुन्हा समोर आलेला प्रश्न. कुसुमाग्रजांच्या 'पाच पुतळे' या कवितेत पुतळ्यांचं चित्रण आधुनिक लोकशाहीतल्या मतपेढ्या आणि सत्तेची रूपकं असंही केल्याचं दिसतं. ज्यांचे पुतळे उभे केले त्यांच्या विचारांचे समाजजीवनात रूपांतर होत नसेल, तर पुतळे उभारणंही एक आन्हीक यापुरतंच उरतं. म्हणून त्याच कवितेत गळ्यातला आवंढा आवरणारे गांधीबाबा, 'जात जमात सोडा, पण माझ्या मागे फक्त सरकारी कचेऱ्यांतल्या भिंती', असे उद्विग्न उद्गार काढतात. इतिहास पुसून टाकता येत नाही; तो संदर्भासह समजून घ्यावा लागतो, हे लक्षात घ्यायला हवं.

मुळात सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे उभारण्याची परंपरा हीच भारतात गुलामगिरीची खूण आहे. आपल्याकडे देवदैवतांच्या मूर्ती होत्या. हाडामासाच्या माणसांचे पुतळे उभारण्याची तद्दन साहेबी परंपरा स्वातंत्र्यानंतर साडेसात दशकांनीही सुरू ठेवण्याच्या मानसिक गुलामगिरीचा अंत कधी होणार, या प्रश्नाला गावागावांत पुतळे उभारण्याची स्पर्धाच उत्तर देत नाही का? एखादा पुतळा किंवा नावं बदलणं हे भावनिक आणि प्रतीकात्मक पातळीवर अल्पकालीन परिणामकारक ठरत असेलही; पण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाच्या प्रयत्नांचे परिणाम दीर्घकालीन असतात.

दिल्लीत अलीकडे 'एआय परिषद' झाली आणि 'एआयमुळे बेकारी वाढणार' यासारख्या चर्चांचं पेव फुटलं. राजीव गांधी यांनी १९८०च्या दशकात कम्प्युटर प्रसाराला बळ दिलं तेव्हापासून, ते अलीकडे नरेंद्र मोदी यांनी 'डिजिटल इंडिया'चा आग्रह धरला तेव्हाही संसदेपासून अनेक ठिकाणी अनेकांनी शंकांचं काहूर उठलं. काळ पुढे सरकत राहतो. इतिहास पुसता येत नाही; तो समजून घ्यावा लागतो आणि प्रतीकांबरोबरच वास्तवावर काम करावं लागतं. बॉम्बे ते मुंबई, मद्रास ते चेन्नई, कलकत्ता ते कोलकाता, मुघलसराय ते दीनदयाळ उपाध्याय, फैजाबाद ते अयोध्याधाम अशा अनेकानेक नामांतरांनी अस्मिता आणि भाषिक ओळख दृढ करण्याचे प्रयत्न झाले.

ल्युटियन्स यांचा एक पुतळा हटला, पण भारताच्या राष्ट्रप्रमुखांसाठी याच ल्युटियन्सनं उभारलेल्या राष्ट्रपती भवनाला पर्याय शोधण्याचा विचार अद्याप तरी समोर आलेला नाही. महात्मा गांधींचे व्याही असलेले राजाजी स्वातंत्र्यलढ्यातील विचारवंत, लेखक, आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले व अखेरचे भारतीय गव्हर्नर-जनरल होते. त्यांना राष्ट्रपती भवनात स्थान मिळालं, तसं त्यांच्या विचारांना सार्वजनिक चर्चेत स्थान मिळेल का? आज ज्यांचा गौरव होतो, उद्या ते टीकेचे धनी होऊ शकतात याचं किमान भारतात तरी, नेहरू-गांधी घराणं हे एकमेव उदाहरण असेल, असं मानता येणार नाही! एखादा पुतळा हटवणं व नवा बसवणं आणि वास्तूचा- विचारांचा स्वीकार या दोन गोष्टींच्या विरोधाभासाकडेही लक्ष जातं ते त्यामुळेच. म्हणूनच पुतळ्यांपेक्षा मूल्यं जपणं महत्त्वाचं, हाही सांगावा ल्युटियन्स ते राजाजी या प्रवासानं दिलाय.

**ता. क :** उत्तर प्रदेश सरकारनं राज्यातील सर्व शाळांत रोज वृत्तपत्र वाचन सक्तीचं करण्याचा निर्णय मध्यंतरी घेतला. लहान वयात रोज सकाळी वृत्तपत्रांच्या वाचनाची सवय लागणं ही डिजिटल व्यसनापासून बचावाची एक पायरी ठरू शकते. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यांनही अशा नवकल्पना गांभीर्यानं विचारात घ्यायला हरकत नाही. पुतळ्यांच्या वादापेक्षा असे उपक्रम राबवणे श्रेयस्कर!

mangesh.w@timesofindia.com

# अविचल रणधैर्याची रोमांचक कहाणी

दखल इंग्रजी पुस्तकाची

■ राहुल गोखले

भारत-चीन युद्धाच्या स्मृतींना उजळा देण्याचा प्रयत्न सध्या होताना दिसतो आहे. '१२० फॉरवर्ड' हा चित्रपट जरी व्यावसायिकदृष्टया यशस्वी ठरला नसला तरी त्या चित्रपटाने मोठ्या पडद्यावर मांडलेली कथा भारतीय सैन्याच्या इतिहासातील तेजस्वी अध्यायांपैकी एक आहे. कुलप्रीत यादव यांचे 'द बॅटल ऑफ रेझांग ला' हे पुस्तक त्या अध्यायाचे महत्त्व प्रभावीपणे उलगडते. पुस्तकाचे लेखक भारतीय तटरक्षक दलातील निवृत्त अधिकारी असल्याने, पुस्तकातील कथन प्रत्ययकारी झाले आहे.

रेझांग ला म्हणजे चुशुल हवाई पट्टीकडे जाणाऱ्या मार्गांचे संरक्षण करणारे पूर्वोत्तर लडाखमधील ठिकाण. पँगोंग त्सो तलाव, स्पांगगुर गॅप, मग्गर टेकडी आणि रेझांग ला या भागांच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांचा उल्लेख करताना लेखकाने, ही ठिकाणे शत्रूच्या हाती गेली असती तर चुशुल पडले असते; पर्यायाने संपूर्ण लडाख धोक्यात आला असता, या सामरिक महत्त्वाकडे लक्ष वेधले आहे. तथापि मेजर शैतान सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील १३ कुमाऊँ बटालियनच्या चार्ली कंपनीतील अवघ्या १२० सैनिकांनी चीनचा हा डाव हाणून पाडला. १८ नोव्हेंबर, १९६२ रोजी पाच हजार चिनी सैनिकांच्या हल्ल्याच्या अतुलनीय प्रतिकाराचे वर्णन हे पुस्तक करते. ऑक्टोबर, १९६२मध्ये नेफा (आत्ताचा अरुणाचल प्रदेश) येथे भारतीय सैन्याला घ्यावी लागलेली माघार; लडाखमध्ये प्रारंभीच्या संघर्षांमध्ये झालेली हानी अशा निराशाजनक वातावरणात रेझांग ला येथील लढाई अविचल धैर्य व जिद्दीचे प्रतीक बनले. १८ हजार फूट उंचीवर, हाडे गोठविणाऱ्या थंडीत, ७, ८ आणि ९ क्रमांकाच्या पलटणींमध्ये तैनात असलेल्या जवानांनी केवळ शत्रूशीच नव्हे, तर निसर्गाच्या कठोर परीक्षेचाही सामना केला. त्याचे तपशीलवार वर्णन लेखक करतो.




भारतीय सैन्याकडे शस्त्रसामग्रीची कमतरता होतीच, पण चीनचे आघाडीवरील सैन्यबळ भारताच्या तुलनेत दसपट होते. सीमा रस्ते संघटना त्या वेळी सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्याने संरक्षणात्मक खंदक सैनिकांनी स्वतः खोदले होते. मर्यादित दारूगोळा, अपुरा तोफखाना, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा अशा प्रतिकूल परिस्थितीत चार्ली कंपनीच्या बहादूर सैनिकांनी चिनी सैनिकांना कसे रोखले, याचे बारकाव्यांनिशी चित्रण लेखकाने केले आहे. रेझांग लाच्या बाजूने हल्ला होण्याची शक्यता गृहीत धरलेली नसूनही प्रत्यक्षात चीनने तेथून आक्रमण केले. पण भारतीय जवानांनी जीवाची बाजी लावत तो हल्ला परतवून लावला. त्यातील सैनिकी डावपेच, नियोजन यांचे तपशील देताना लेखकाने मांडलेल्या वैयक्तिक शौर्यकथा हृदयस्पर्शी आहेत. बंदुकीतील गोळ्या संपल्यामुळे चिनी सैनिकाशी झटापट करून त्याला नामोहरम करणारे लान्सनाईक सिंह राम, शत्रूकडून मशिनगन हिसकावून घेणारे नाईक गुलाब सिंह, जखमी झाल्यावरही लढत राहिलेले नाईक राम कुमार, शत्रूच्या तब्बल ४७ गोळ्या झेललेले नायब सुभेदार हरी राम, आपल्या प्राणांची बाजी लावणारे नायब सुभेदार सुरजा कुमार व नायब सुभेदार राम चंदर यांच्या कहाण्या 'प्राणांची आहुती मंजूर आहे, पराभव मंजूर नाही' या सैनिकी धारणेची प्रचिती देतात.

कंपनी कमांडर मेजर शैतानसिंग या लढाईचे नायक ठरले. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत सतत सैनिकांना धीर देणारा, शत्रूच्या गोळीबाराच्या वर्षावातही जवानांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणारा संयमी, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी म्हणून त्यांचे संयत चित्रण लेखक करतो. मरणोत्तर परमवीर चक्र सन्मानाने त्यांना गौरविण्यात आले. लढाई संपली तेव्हा चार्ली कंपनीचे १२० पैकी ९६ सैनिक हुतात्मा झाले होते. काही महिन्यांनी शोधपथके रेझांग ला येथे पोहोचली, तेव्हा खंदकांमध्ये शत्रूकडे तोंड करून पडलेले; हातात रायफल घट्ट पकडलेल्या स्थितीत जवानांचे मृतदेह आढळले. मेजर शैतान सिंग यांचा पार्थिव देहही त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जिथे ठेवला होता तेथेच सापडला. त्या दृश्याने सैनिकांच्या पराक्रमावर आधी घेण्यात आलेल्या शंकांचे निरसन झाले, असे लेखकाने नमूद केले आहे. बर्फाळ युद्धभूमीवर आवश्यक साहित्य, दारूगोळा वाहून नेणाऱ्या भारतीय हवाई दलाच्या एएन-१२ आणि सी-११९ विमानांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानावर लेखक प्रकाश टाकतो.

कुटुंबे, पत्नी, मुले आणि पालक यांची आठवण सैनिकांच्या मनात दाटून येत होती, याचे हृद्य वर्णन करून लेखक लष्करी गणवेशातील मानवी भावविश्वालाही स्पर्श करतो. बचावलेले तसेच शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांच्या मुलाखती, युद्ध दैनंदिनी इत्यादींच्या आधारे हा पट उलगडण्याचा लेखकाचा प्रयत्न वाखाणण्याजोगा आहे. त्यामुळे भारतीय सैनिकांच्या सर्वोच्च बलिदानाची कहाणी वाचकांपर्यंत पोचली आहे.

**द बॅटल ऑफ रेझांग ला**
**लेखक :** कुलप्रीत यादव
**प्रकाशक :** पेंग्विन वीर
**पाने :** २०८ **किंमत :** ३९९ रुपये

डॉ. बाळ फोंडके
mtedit@timesofindia.com

# विज्ञान दिन... संकल्प दिन



चित्र : एआय

**विज्ञानदिन हा केवळ उत्सव नाही, तर संकल्प आहे, विचारपूर्वक जगण्याचा, चिकित्सेवर आधारित निर्णय घेण्याचा, आणि देशविकासासाठी विज्ञानाचीच कास धरण्याचा... आजच्या राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्ताने लेख...**

आज २८ फेब्रुवारी. राष्ट्रीय विज्ञान दिन. वर्षभरात असे अनेक दिन प्रत्यही साजरे केले जातात. कधी महिला दिन, कधी मातृभाषा दिन, तर कधी वसुंधरा दिन. शाळा कॉलेजांमध्ये तर पारंपरिक पोशाख दिन, मैत्री दिन असेही साजरे होतात. त्या त्या दिवशी त्या संकल्पनेचा सोहळा करून झाला की त्याचा विसर पडतो. परत पुढच्या वर्षापर्यंत. विज्ञान दिनही त्याच मार्गाने जाणार असेल तर तो साजरा न केलेलाच बरा.

नोबेल पुरस्कार विजेते सी. व्ही. रमण यांनी, त्यांच्याच नावाने आता ओळखलं जाणारे, आपले पथदर्शी संशोधन १९२८मध्ये याच दिवशी जगासमोर सादर केले. त्याची स्मृती जागृत ठेवण्यासाठी या दिवसाची निवड झाली आहे. तरीही विज्ञानदिन हा इतर दिनांसारखा केवळ स्मरणदिन नाही, तर तर्कसंगत विचार करण्याचा आणि तो सातत्याने आचरणात आणण्याचा निर्धार करण्याचा दिवस आहे.

विज्ञान म्हणजे केवळ प्रयोगशाळा, पांढरे कोट आणि गुंतागुंतीची समीकरणे एवढेच नाही. अणुच्या अंतरंगात होणाऱ्या विविध आविष्कारांचा किंवा सुदूर अंतराळात घडणाऱ्या घटनांचा मागोवा घेणे म्हणजेच विज्ञान ही समजूत चुकीची आहे. विज्ञान म्हणजे वेगवेगळ्या नैसर्गिक आविष्कारांचा, एवढेच नव्हे तर आपल्या दैनंदिन जीवनातल्या साध्यासाध्या कृतींचाही कार्यकारणभाव समजून घेण्याचा तर्कसंगत प्रयत्न. निरीक्षण, प्रयोग, तर्क आणि पडताळणी या टप्प्यांतून सत्याचा शोध घेणे म्हणजे विज्ञान. त्याच सूत्राला वैज्ञानिक दृष्टिकोन असेही म्हटले जाते. कोणतीही गोष्ट अंधपणे न स्वीकारता तिची चिकित्सा करणे, 'क'ची बाराखडी असणारे प्रश्न विचारून त्यांची उत्तरे शोधणे, हाच वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा गाभा आहे. समाजात हा रुजणे आवश्यक आहे. कारण तुम्ही आम्ही अनेकदा भावना, भीती, परंपरा किंवा अफवा यांच्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवत निर्णय घेतो. करोनासारखी एखद्या रोगाची साथ कोणा आकाशस्थ ग्रहगोलाच्या किंवा दैवताच्या अवकृपेची परिणती नसून कोणत्यातरी रोगजंतूचा प्रताप आहे, हे समजून घेतले तर त्यावर प्रतिबंधात्मक लस किंवा उपचारात्मक औषध तयार करून तिला आळा घालता येतो. वैज्ञानिक दृष्टिकोन समाजाला विवेक देतो, अंधश्रद्धेऐवजी तर्काला, आणि भीतीऐवजी विश्वासार्ह माहितीला महत्त्व देतो.

आज माहितीचा स्फोट झालेला आहे. समाज माध्यमांवर अनेक दावे केले जातात, काही खरे, काही अर्धवट, काही पूर्णपणे खोटे. अशा वेळी वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेला नागरिक 'यामागे पुरावा काय?,' असा प्रश्न विचारतो. तो माहितीची पडताळणी करतो. ही वृत्ती लोकशाहीसाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण सुजाण निर्णय हेच राष्ट्राच्या प्रगतीचे पायाभूत तत्त्व असते.

विज्ञानाचा समाजावर होणारा परिणाम केवळ उपकरणांपुरता मर्यादित नाही; तो विचारसरणी बदलतो. उदाहरणार्थ, शेतीत मातीचा वैज्ञानिक अभ्यास केल्यावर कोणत्या पिकासाठी कोणती जमीन योग्य आहे, हे समजते. हवामानाचा अंदाज उपग्रहांमुळे मिळतो. जलसंधारणाच्या पद्धती भूगर्भशास्त्राच्या अभ्यासातून विकसित होतात. या सर्व गोष्टींनी उत्पादन वाढते, त्याचा दर्जा उंजावतो, शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान कमी होते. म्हणजे विज्ञान थेट अर्थव्यवस्थेशी आणि त्या अनुषंगाने समाजस्वास्थ्याशीही जोडलेले आहे.

आरोग्य क्षेत्रातल्या जंतूशास्त्र, औषधनिर्मिती, जैवतंत्रज्ञान यातील संशोधनामुळे आयुर्मान वाढले. उद्योगधंद्यात नवीन पदार्थ, स्वयंचलित यंत्रे आणि संगणकीय तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनक्षमता वाढली. संवाद तंत्रज्ञानामुळे ज्ञानाचा प्रसार झपाट्याने होतो. या सर्व गोष्टींच्या पाठीशी वैज्ञानिक संशोधनाचे पाठबळ आहे.

ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वावलंबन हवे असेल तर सौर, पवन अण्विक आणि हरित उर्जेचे संशोधन आवश्यक आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करायचे असेल तर हवामानशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र आणि शाश्वत विकासाच्या संकल्पना समजून घ्याव्या लागतील. पाण्याचे व्यवस्थापन, कचऱ्याचे विघटन, टाकाऊ पदार्थांचा पुनर्वापर, प्रदूषण नियंत्रण - या सर्वांसाठी वैज्ञानिक उपाययोजना हव्यात. केवळ भावना किंवा घोषणांनी समस्या सुटत नाहीत; त्यासाठी संशोधनाधिष्ठित धोरणे अंगिकारावी लागतात.

उद्योग आणि स्टार्टअप संस्कृती विकसित करण्यासाठी नवोन्मेष (innovation) आवश्यक आहे. त्याची रुजवण वैज्ञानिक विचारातूनच होते. एखादी समस्या ओळखणे, तिचे मूळ कारण शोधणे, प्रयोग करून उपाय शोधणे ही प्रक्रिया वैज्ञानिक आहे. तरुणांनी संशोधन, अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवतंत्रज्ञान, अवकाश संशोधन अशा क्षेत्रांत पुढे येणे गरजेचे आहे. यामुळे रोजगारनिर्मिती होईल, देश अधिकाधिक आत्मनिर्भर होईल आणि त्यायोगे आजच्या जीवघेण्या स्पर्धेच्या युगात देश समर्थपणे उभा राहील.परंतु तंत्रज्ञान उपलब्ध असले तरी वैज्ञानिक दृष्टिकोन नसेल तर प्रगती अपुरी राहते. उदाहरणार्थ, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर जबाबदारीने कसा करायचा, पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता उद्योग कसे उभारायचे, डेटा आणि गोपनीयता कशी जपायची, हे सर्व प्रश्न विवेकाने सोडवावे लागतात. वैज्ञानिक दृष्टिकोन माणसाला संतुलन शिकवतो.

समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी काही गोष्टी तुम्हीआम्हीही करू शकतो. प्रश्न विचारण्याला प्रोत्साहन देण्यापासून सुरुवात करता येईल. मुलांनी प्रश्न विचारले तर त्यांना गप्प बसवण्याऐवजी त्यांच्या कुतूहलाचे कौतुक करून ते शमवण्याची धडपड करणे... माहितीच्या स्त्रोतांची तपासणी करणे.

समाज माध्यमांवर आलेली प्रत्येक गोष्ट खरी असेलच असे नाही; तिच्या मागे शास्त्रीय आधार आहे का, हे पाहणे गरजेचे. तसंच प्रयोगशीलता वाढवणे. घरच्या घरी साधे प्रयोग, निरीक्षणे, नोंदी ठेवणे यामुळे विचारांची शिस्त तयार होते.

विज्ञान सर्वत्र आहे. स्वयंपाकघरात भाजी शिजवताना उष्णतेमुळे कोणते आणि कसे बदल होतात, साबणाने हात धुताना तेलकट घाण कशी निघते, सायकल चालवताना संतुलन कसे राखलं जाते, या सर्वांमध्ये विज्ञान दडलेले आहे. आपण श्वास घेतो, हृदय धडधडते, वनस्पती प्रकाशात अन्न तयार करतात या प्रत्येक प्रक्रियेमागे निसर्गाचे नियम कार्यरत असतात. विज्ञान म्हणजे या नियमांना समजून घेण्याचा प्रयत्नच आहे.

विज्ञानदिन आपल्याला आठवण करून देतो, की विज्ञान ही केवळ माहितीची साठवणूक नाही; ती जगण्याची पद्धत आहे. सत्याचा शोध घेण्याची प्रामाणिक वृत्ती, चूक मान्य करून पुढे जाण्याची तयारी, आणि नव्या कल्पनांना खुल्या मनाने स्वीकारण्याची सवय, हे विज्ञान आपल्याला शिकवते. अशा वृत्तीने समाज अधिक प्रगत, समंजस आणि मानवतावादी होतो.

म्हणून विज्ञानदिन हा केवळ उत्सव नाही, तर संकल्प आहे, विचारपूर्वक जगण्याचा, चिकित्सेवर आधारित निर्णय घेण्याचा, आणि देशविकासासाठी विज्ञानाचीच कास धरण्याचा. २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडवण्याचे स्वप्न आपण पाहत आहोत. पण विकसित देश म्हणजे केवळ उंच इमारती किंवा मोठी अर्थव्यवस्था नव्हे. जीवनकलह सुसह्य करणाऱ्या सोयीसुविधांची रेलचेल नव्हे. ते आवश्यक आहेच. पण खरा विकसित देश म्हणजे सुशिक्षित, आरोग्यदृष्ट्या सक्षम, तंत्रज्ञानसज्ज आणि विवेकशील नागरिक असलेला देश. हे साध्य करायचे असेल तर प्रयोगशाळा आणि उद्योग यांच्याइतकाच महत्त्वाचा आहे तो सामान्य नागरिकाचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन. जिज्ञासा, तर्क आणि जबाबदारी या तीन आधारांवर उभा राहिलेला समाजच खऱ्या अर्थाने विकसित होतो. ते स्वप्न साकार करण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास धरणे अनिवार्य आहे.

विज्ञान म्हणजे प्रकाश, तो अज्ञानांधकार मिटवतो. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे तो दिशा दाखवतो. त्या दिशेने निश्चयाने चालणं, हीच विज्ञानदिनाची खरी प्रेरणा आहे.

**(लेखक ज्येष्ठ वैज्ञानिक आहेत.)**

# वसईचा जागतिक वारसा

**वसईचा वारसा हा केवळ दगडी वास्तूंमध्ये मर्यादित नाही; तो स्मृती, श्रद्धा आणि सामूहिक प्रयत्नांमध्ये नांदतो. वसईतील 'अवर लेडी ऑफ ग्रेस' या ऐतिहासिक कॅथेड्रलला मिळालेला युनेस्कोचा 'अवॉर्ड ऑफ मेरिट' हा सन्मान या सामूहिक प्रयत्नांचा जागतिक स्तरावर झालेला गौरव आहे.**

फ्रँक मिरांडा
mtedit@timesofindia.com



महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वसई येथे वसलेले अवर लेडी ऑफ ग्रेस या ऐतिहासिक कॅथेड्रलला २०२५ सालच्या युनेस्कोच्या आशिया-पॅसिफिक अवॉर्ड्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज कॉन्झर्वेशन अंतर्गत 'अवॉर्ड ऑफ मेरिट' हा प्रतिष्ठेचा सन्मान जाहीर झाला आहे. हा पुरस्कार केवळ एका वास्तूच्या संवर्धनाचा गौरव नसून स्थानिक समाजाच्या सामूहिक सहभागाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतलेली दखल आहे.

वसई पश्चिमेतील पापडी धर्मग्रामात, मुंबईपासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर असलेले हे कॅथेड्रल सोळाव्या शतकातील पोर्तुगीज स्थापत्य वारशाचे भव्य प्रतीक मानले जाते. इ.स. १५७४ मध्ये उभारलेली ही दगडी वास्तू शतकानुशतके नैसर्गिक झळा सहन करत आजही दिमाखात उभी आहे. सिमेंटचा आधार न घेता केवळ चुनादगडांच्या साहाय्याने उभारलेली ही रचना त्या काळातील अभियांत्रिकी कौशल्याची साक्ष देते.

अलीकडेच पूर्ण झालेल्या पुनर्संवर्धन प्रकल्पासाठी सुमारे ४.७५ कोटी रुपये खर्च झाले. विशेष म्हणजे, हा निधी स्थानिक भूमिपुत्रांच्या देणग्यांमधून उभारण्यात आला. गावकऱ्यांनी केवळ आर्थिक मदतच केली नाही, तर नियोजन, देखरेख आणि व्यवस्थापनातही सक्रिय सहभाग घेतला. त्यामुळे हा उपक्रम सरकारी प्रकल्प न ठरता लोकचळवळीचे स्वरूप धारण करू शकला.

युनेस्कोच्या प्रशस्तिपत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्रातील ख्रिस्ती परंपरेचे प्रतीक असलेल्या या कॅथेड्रलचे संवर्धन हे पोर्तुगीज वसाहतकालीन वारशाचे पुनरुज्जीवन करणारे महत्त्वपूर्ण कार्य आहे. अंतर्गत भागातील सुबक आणि तांत्रिकदृष्ट्या अचूक पुनर्बांधणी, पारंपरिक कारागिरीचा वापर, तसेच उपासनेसाठी आवश्यक घटकांचे संवेदनशील पुनर्निर्माण यामुळे या वास्तूला पुन्हा एकदा सजीव प्रार्थनास्थळाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. मर्यादित साधनसामग्री असूनही स्थानिक परिषदेच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हा प्रकल्प यशस्वी ठरला,

या कॅथेड्रलची स्थापना इ.स. १५६५ मध्ये जेजुइट्स धर्मगुरूंनी केली आणि इ.स. १५९७ मध्ये त्याची पुनर्बांधणी झाली. १५ ऑगस्ट १९९८ मध्ये जेव्हा वसई धर्मग्राम मुंबई धर्मग्रामपासून वेगळा झाला तेव्हा त्याला अधिकृतपणे 'कॅथेड्रल'चा दर्जा देण्यात आला. स्थापत्यदृष्ट्या या इमारतीवर गॉथिक आणि मॅन्युएलिन शैलीचा प्रभाव दिसून येतो. उंच कमानीदार दरवाजे, भव्य दर्शनी भाग आणि दगडी कोरीव काम या वैशिष्ट्यांमुळे वास्तूला एकाच वेळी राकटपणा आणि भव्यता लाभली आहे. स्थानिक दगडांच्या वापरामुळे ही रचना परिसराशी सुसंवादी वाटते.

सोळाव्या शतकात पोर्तुगीजांनी वसईला आपले महत्त्वाचे प्रशासकीय व धार्मिक केंद्र बनवले. विविध धार्मिक संघटनांनी येथे चर्च आणि पॅरिश उभारून ख्रिस्ती धर्म वाढवला. निर्मळ, आगाशी, नंदाखाल, रमेदी, सांडोर, पापडी, पाली, माणिकपूर आणि मर्सेस या भागांत चर्चेस बांधण्यात आली. काळाच्या ओघात या चर्चांचा विस्तार होत गेला आणि आज वसई परिसरात ३२ चर्चेस अस्तित्वात आहेत आणि स्थानिक वसईकर धर्मगुरू येथे मोठ्या संख्येने कार्यरत आहेत. काही प्राचीन चर्च नष्ट झाली असली, तरी त्यांचा वारसा सांस्कृतिक स्मृतीत जिवंत आहे.

अठराव्या ते विसाव्या शतकात मराठा आणि ब्रिटिश सत्ताकाळात या प्रदेशाने अनेक राजकीय उलथापालथी अनुभवल्या. युरोपीय धर्मगुरूंना परत जावे लागल्यावर गोव्याहून आलेल्या धर्मगुरूंनी श्रद्धेची परंपरा टिकवून ठेवली. स्थानिक पूर्व भारतीय (ईस्ट इंडिया) समाजातील धर्मगुरूंनीही नेतृत्व स्वीकारत धार्मिक आणि सामाजिक संरचना मजबूत केली. त्यामुळे वसईतील कॅथोलिक समाजाने बदलत्या सत्ताकाळातही आपली ओळख जपली.



सदर कॅथेड्रलच्या जीर्णोद्धाराला नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सुरुवात झाली आणि ऑगस्ट २०२३ मध्ये काम पूर्ण झाले. हे कार्य केवळ दुरुस्तीपुरते मर्यादित न राहता वारशाच्या जतनाची जबाबदारी म्हणून पार पडले. वसईचे तत्कालीन आर्चबिशप फेलिक्स मच्याडो आणि पापडी पॅरिशचे तत्कालीन प्रमुख धर्मगुरू फा. जॉन फरगोज यांच्या नेतृत्वाखाली हे कार्य पार पडले. त्यांना फा. भूषण कोळी, फा. किरण लोपीस, फा. मॉर्गन फर्नांडीस आणि फा. चार्ल्स फरगोज यांचे सहकार्य लाभले. जीर्णोद्धारात लाईमस्टोन (चुनखडी दगड) हा महत्त्वाचा घटक होता. हा दगड गुजरात आणि राजस्थान येथून मागविण्यात आला. दगड बसवण्यासाठी आवश्यक पारंपरिक चुना चर्च परिसरातच तयार करण्यात आला, ज्यामुळे मूळ रचनेची ऐतिहासिक सुसंगती अबाधित राहिली.

मुंबईस्थित 'सवानी हेरिटेज कन्सर्वेशन' या कंपनीने हे काम बारकाईने पूर्ण केले. आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (वसई विभाग) यांच्या सूचनेनुसार मूळ रचनेत कोणताही बदल न करता केवळ जीर्णोद्धारावर भर देण्यात आला. या प्रकल्पाचा आराखडा मुंबईचे आर्किटेक्ट एन्सली लेवीस यांनी तयार केला, तर स्थानिक आर्किटेक्ट जेरी डिकुन्हा यांनी मानधन न घेता सहभाग नोंदवला. वसईतील सुप्रसिद्ध सिक्वेरा बंधू यांनी चर्चचे ऑल्टर आणि नव्या स्टॅच्यूंचे कोरीवकाम साकारले, ज्यामुळे अंतर्भागाला नवचैतन्य लाभले. एकंदरीत, धर्मगुरू, आर्किटेक्ट, अभियंते, कारागीर आणि स्थानिक समाज यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून कॅथेड्रल नव्या तेजाने उभे राहिले. हा जीर्णोद्धार केवळ वास्तूचा नव्हे, तर श्रद्धा, परंपरा आणि सांस्कृतिक ओळखीच्या जतनाचा प्रवास ठरला आहे.

वसईचा वारसा हा केवळ दगडी वास्तूंमध्ये मर्यादित नाही; तो स्मृती, श्रद्धा आणि सामूहिक प्रयत्नांमध्ये नांदतो. 'अवॉर्ड ऑफ मेरिट' हा सन्मान या सामूहिक प्रयत्नांचा जागतिक स्तरावर झालेला गौरव आहे. स्थानिक लोकसहभाग, पारंपरिक कारागिरी आणि ऐतिहासिक जाणिवेचा संगम साधत उभारलेले हे संवर्धन कार्य इतर वारसा प्रकल्पांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकते.

वसईतील कॅथोलिक संस्कृती ही केवळ धार्मिक विधींपुरती मर्यादित नाही. ती भाषिक, खाद्यसंस्कृती, पोशाख, संगीत आणि सण-उत्सव यांचा समृद्ध पट उलगडते. ख्रिसमस आणि इस्टरसारखे सण मोठ्या उत्साहात साजरे होतात. पॅरिश फेस्ट, लग्नसमारंभातील पारंपरिक गीते, विशिष्ट विधी आणि घरगुती पाककृती यांमधून या समाजाची वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख प्रकट होते. परस्पर सहकार्याची आणि समुदायभावनेची परंपरा आजही जिवंत आहे.

आज या परिसरातील चर्चेस सामाजिक बांधिलकीची केंद्रे म्हणून कार्यरत आहेत. शिक्षणक्षेत्रात त्यांचे मोठे योगदान असून अनेक चर्चशेजारी शाळा कार्यरत आहेत. रक्तदान आणि आरोग्य शिबिरे, गरजूंसाठी मदतकार्य, आणि विविध सामाजिक उपक्रमांद्वारे सर्वधर्मीय नागरिकांना आधार दिला जातो. त्यामुळे चर्च हे केवळ उपासनेचे स्थान न राहता सामाजिक समन्वयाचे केंद्र बनले आहे.

वसईचा वारसा हा केवळ दगडी वास्तूंमध्ये मर्यादित नाही; तो स्मृती, श्रद्धा आणि सामूहिक प्रयत्नांमध्ये नांदतो. 'अवॉर्ड ऑफ मेरिट' हा सन्मान या सामूहिक प्रयत्नांचा जागतिक स्तरावर झालेला गौरव आहे. स्थानिक लोकसहभाग, पारंपरिक कारागिरी आणि ऐतिहासिक जाणिवेचा संगम साधत उभारलेले हे संवर्धन कार्य इतर वारसा प्रकल्पांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकते. या कॅथेड्रलचे पुनरुज्जीवन हे केवळ भूतकाळाचे जतन नाही, तर वर्तमान आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी सांस्कृतिक ओळख जपण्याचा जागरूक प्रयत्न आहे. वसईच्या इतिहासातील हा अध्याय आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधोरेखित झाला असून, या वारशाचे जतन करणे ही संपूर्ण प्रदेशाची सामूहिक जबाबदारी असल्याची जाणीव अधिक दृढ झाली आहे.

# 'पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शहा, देशाची माफी मागा'

**न्यायालयाच्या निकालानंतर केजरीवाल यांची मागणी**

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

दिल्लीतील कथित दारू घोटाळा प्रकरणातून निर्दोष मुक्त झाल्यानंतर दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर थेट हल्लाबोल करताना, या दोघांनी आम आदमी पक्षाला नष्ट करण्यासाठी आपल्याविरुद्ध एक घातक कट रचल्याबद्दल जनतेची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी केली. दिल्लीत आजच निवडणुका होऊ द्या, भाजपने १०पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या तर मी राजकारण सोडेन, असे खुले आव्हान त्यांनी पंतप्रधानांना दिले.



केजरीवाल यांनी निर्दोष मुक्तता झाल्यावर पहिल्याच पत्रकार परिषदेत दिल्लीच्या जनतेचा मूड आणि राग जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारला दिल्ली विधानसभेच्या नवीन निवडणुका घेण्याचे आव्हान दिले. कठीण परिस्थितीतही कायद्याचे पालन केल्याबद्दल आणि

> **आज अमेरिका आपल्याला फटकारत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प रोजच्या रोज आपल्या देशाला शिव्या देतो, तरीही मोदीजी त्याच्यासमोर एखाद्या भित्र्या मांजराप्रमाणे गप्प राहतात.**
> – अरविंद केजरीवाल

धाडस दाखवल्याबद्दल केजरीवाल यांनी 'आप'च्या सहकाऱ्यांसह न्यायाधीश आणि वकिलांचे आभार मानले. ईडीच्या त्यांच्याविरुद्धच्या खटल्याला 'आप' उच्च न्यायालयात आव्हान देईल, असे त्यांनी सांगितले. आप नेत्यांना मिळालेली क्लीन चिट संशयास्पद असल्याच्या काँग्रेसच्या दाव्याला जोरदार प्रत्युत्तर देताना केजरीवाल यांनी, राहुल गांधी किंवा रॉबर्ट वड्रा यांच्यासह कोणताही काँग्रेस नेता तुरुंगात का गेला नाही, असा प्रश्न विचारला.

'गेल्या काही वर्षांपासून भाजप दारू घोटाळ्याबद्दल बोलत आहे आणि आमच्यावर आरोप करत आहे, परंतु आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. सत्याचा विजय झाला आहे. 'आप'ला संपविण्यासाठी सर्व प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. हा पूर्णपणे बनावट खटला होता. मी माझ्या आयुष्यात फक्त प्रामाणिकपणा कमावला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि 'आप' हे कट्टर प्रामाणिक आहेत. खोट्या खटल्यांमध्ये आम्हाला तुरुंगात टाकणे हे पंतप्रधानांना शोभत नाही. त्यांनी चांगल्या कामाद्वारे सत्तेत यावे', असेही केजरीवाल म्हणाले.

# चौकशीची शिफारस... तुरुंगवास ते मुक्तता



## अटकेची मालिका

- **२२ जुलै २०२२ :** नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाच्या (२०२१-२२) अंमलबजावणीतील नियमांचे उल्लंघन आणि प्रक्रियात्मक त्रुटींचा उल्लेख करून नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली. त्यांनी नंतर तक्रारही दाखल केली.
- **१७ ऑगस्ट :** सीबीआयने फसवणूक आणि लाचखोरीच्या आरोपाखाली उत्पादन शुल्कमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी आणि व्यावसायिकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
- **१९ ऑगस्ट :** सिसोदिया आणि इतर तीन 'आप' नेत्यांच्या घरांवर, आणि दिल्ली-एनसीआर प्रदेशातील अनेक ठिकाणी सीबीआयने छापे टाकले.
- **३० ऑगस्ट :** सीबीआयच्या पथकाने गाझियाबादमधील सेक्टर-४ येथील वसुंधरा येथील पंजाब नॅशन बँकेतील सिसोदिया यांचा बँक लॉकर तोडून त्याची झडती घेतली.
- **२७ सप्टेंबर :** उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणातील कट रचणाऱ्यांपैकी एक असलेल्या 'आप' मीडिया प्रभारी विजय नायर यांना सीबीआयने अटक केली.
- **१० ऑक्टोबर :** सीबीआयने हैदराबादमधील व्यापारी अभिषेक बोईनपल्ली यांना अटक केली. त्यांच्यावर दक्षिण भारतातील काही मद्यव्यापाऱ्यांसाठी लॉबिंग केल्याचा आरोप आहे.
- **१७ ऑक्टोबर :** सीबीआयकडून सिसोदिया यांची नऊ तास चौकशी केली.
- **२५ नोव्हेंबर :** दिल्ली उत्पादन शुल्क प्रकरणात सीबीआयने पहिले आरोपपत्र दाखल केले. त्यात आरोपी म्हणून सिसोदिया यांचे नावच नव्हते.
- **२६ फेब्रुवारी २०२३ :** सीबीआयने सिसोदिया यांना अटक केली.
- **२८ फेब्रुवारी २०२३ :** सिसोदिया यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
- **९ मार्च २०२३ :** 'ईडी'ने मनीष सिसोदिया यांची तुरुंगात चौकशी केली आणि त्यांना अटक केली.
- **२१ मार्च २०२४ :** मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआय व ईडीच्या नऊ समन्सवर चौकशीसाठी हजर राहू शकले नाहीत आणि त्यानंतर त्यांना त्यांच्या निवासस्थानातून अटक करण्यात आली.
- **२६ जून २०२४ :** तुरुंगात असतानाच मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना सीबीआयने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक केली.

## कोणत्या नेत्याला कधी जामीन?

- **९ ऑगस्ट २०२४ :** १७ महिने तुरुंगात घालवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला.
- **१३ सप्टेंबर २०२४ :** सहा महिने तुरुंगात घालवल्यानंतर केजरीवाल यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.

# विरोधक आणि भाजपमध्ये जुंपली

**केजरीवाल यांच्या सुटकेनंतर आरोप-प्रत्यारोप**

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात शुक्रवारी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर विरोधी पक्ष आणि भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. हा घटनात्मक मूल्यांचा विजय असल्याचे सांगून आम आदमी पक्षाने (आप) जल्लोष केला, तर या मुद्द्यावर जनतेने आधीच राजकीय कौल दिल्याचे भाजपने म्हटले.

तृणमूल काँग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पक्ष आणि डाव्या पक्षांनी या निकालाचे स्वागत करताना भाजपचे सूडाचे राजकारण उघडकीस आल्याचे म्हटले. मात्र, काँग्रेसने केजरीवाल यांची निर्दोष मुक्तता 'अपेक्षित पटकथा' असल्याचे म्हटले. 'भाजप हा राजकीय पक्ष नाही. तो एक इच्छाधारी नाग आहे. काँग्रेसमुक्त भारत या एकमेव ध्येयासाठी तो कोणत्याही थराला जाऊ शकतो', अशी टीका काँग्रेसचे माध्यम आणि प्रसिद्धी विभागप्रमुख पवन खेरा यांनी केली.

भाजप प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी, हा तांत्रिक विषय असून, न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास केल्यानंतर पक्ष सुसंगत प्रतिसाद देईल, असे म्हटले आहे. 'आप'चे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी हे प्रकरण पक्षाच्या नेतृत्वाला बदनाम करण्याच्या कटाचा भाग असल्याचा आरोप केला. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी 'सत्याचा नेहमीच विजय होतो', असे म्हटले आहे.

मद्य धोरण प्रकरण कोसळणे हे भाजपसाठी नैतिक मृत्यूदंड आहे, कारण त्यांनी दिल्लीच्या जनतेचा विश्वासघात केला, असा आरोप समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केला आहे. आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत करून, दिल्लीत पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी केली.

# 'आप'ला फुटणार पालवी!

**भाजपसाठी नवी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता**

मंगेश वैशंपायन
mangesh.w@timesofindia.com

**नवी दिल्ली :** दिल्लीतील कथित उत्पादन शुल्क (दारू) घोटाळ्याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्याचा फाल्गुन महिन्यात आलेला निर्णय आम आदमी पक्षाला (आप) पुन्हा वसंतपालवी फुटणार याची चाहूल लावणारा आहे. हा केवळ एखाद्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा शेवट नाही, तर देशाच्या राजकारणातील सत्तासंघर्ष, तपास यंत्रणांची भूमिका आणि विरोधकांच्या राजकीय भवितव्याशी निगडित मोठा टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे.

एकखांबी तंबूप्रमाणे राजकीय पक्ष चालवणाऱ्या केजरीवालांच्या मुक्ततेनंतर केंद्रातर्फे या निर्णयाला पुढील आव्हान मिळेपर्यंत केजरीवालांची तोफ धडाडत रहाणार. ते व सिसोदिया पुन्हा विधानसभेवरही जातील. हे सारे भाजपसाठी नवी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणाने भारतीय राजकारणात आरोप, तपास आणि न्यायालयीन कसोटी यांतील नाजूक संतुलन पुन्हा





अधोरेखित केले आहे आणि पुढील काळात विरोधकांच्या एकजुटीच्या राजकारणाला कोणते वळण मिळते, हेच या निर्णयाचे खरे राजकीय फलित ठरणार आहे. मुळात या खटल्यात सीबीआयला पुरावे सिद्ध करण्यात अपयश आल्याची जी ठळक कारणे आहेत त्यात तांत्रिकतेचा भाग मोठा आहे. दिल्लीत केजरीवाल यांच्या धोरणानंतर दारूचा जो महापूर आला होता आणि 'एका बाटलीवर एक मोफत'चा मारा दिल्लीकरांवर होत होता, तो सारा व्यवहार हवाल्याचा आहे. याचा लाभ दिल्ली, आंध्र प्रदेश व इतरत्र ज्या दारू कंपन्यांना झाला त्यांच्याशी झालेला व्यवहार हवाल्याच्या मार्गाने केलेले आहेत. केजरीवाल सरकारने उत्पादन शुल्काचे नियम संशयास्पदरीत्या बदलले, हा आरोप आता उच्च न्यायालयात व प्रसंगी त्यापुढच्या पायरीवरही सिद्ध करण्यासाठी सीबीआयला नव्या पद्धतीने याचा अभ्यास करावा लागणार आहे.

या दारू घोटाळ्यात ठोस पुराव्याअभावी आरोप फेटाळण्यात आल्याने केंद्र सरकारच्या ताब्यातील तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पदावर असतानाच अटक झालेले केजरीवाल हे देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले होते, ही बाब लोकशाही व्यवस्थेतील असामान्य घटना म्हणून नोंदली गेली. त्यामुळे या निर्णयाचे परिणाम केवळ कायदेशीर मर्यादेत न राहता व्यापकपणे उमटणार हे स्पष्ट आहे. २०१४नंतर केंद्र सरकार केंद्रीय तपास संस्थांचा वापर राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना लक्ष्य करण्यासाठी करते, या विरोधकांच्या आरोपांना न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बळ मिळाल्याची भावना आप समर्थकांमध्ये निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून आपला सूडबुद्धीने छळ झाल्याची प्रतिमा ही राजकारणात अनेकदा सहानुभूती आणि समर्थनाचे भांडवल ठरते. दिल्लीतील सत्ता गमावण्याचा राजकीय धक्का बसल्यानंतर केजरीवाल यांच्यासाठीच नव्हे, तर 'आप'साठीही हा निकाल नव्याने उभारी देणारा ठरू शकतो. दिल्लीतील सत्ता गेल्यावर जाऊ तेथे बोलू, हे धोरण केजरीवाल यांनी म्यान केले होते. आता स्वतःच्या भल्यासाठी त्याचाच वापर आगामी काळातही करण्याची गरज व्यक्त होते.

राष्ट्रीय पातळीवर भाजपविरोधी मतांचे विभाजन टाळण्याची गरज वारंवार अधोरेखित होत असली तरी यापुढील राजकारणात काँग्रेस आणि आप यांच्यातील संबंधांकडे विशेष लक्ष लागून राहील. केजरीवालांच्या उदयानंतर दिल्लीतून काँग्रेस साफ झाला. गुजरात आणि पंजाबसारख्या राज्यांत काँग्रेस आणि आप प्रतिस्पर्धी आहेत. केजरीवाल यांनी या निकालानंतर अधिक ठाम आणि आक्रमक राष्ट्रीय भूमिका घेतली तर काँग्रेससमोर त्यांच्याशी संवाद वाढवण्याची वेळ येऊ शकते. परंतु नेतृत्वाचा प्रश्न, परस्परांतील अविश्वास आणि राज्यनिहाय स्पर्धा या अडचणी कायम राहतील.

## क्विक बाइट्स

### सरनाटोली में हाथी ने घर को किया क्षतिग्रस्त

**बेड़ो.** प्रखंड के ईटा पंचायत स्थित खिरदा गांव के सरनाटोली में हाथी ने गुरुवार की रात में 10.30 बजे उत्पात मचाया. हाथी ने सरना टोली में बिरासमुनि कुमारी पति बुधु उरांव के घर को ध्वस्त कर दिया. वहीं घर में रखे घरेलू उपयोग के सामान बर्बाद हो गये. परिजनों ने किसी प्रकार घर से भाग कर अपनी जान बचायी. इधर सूचना मिलने पर पूर्व मुखिया बुधराम बाड़ा ने घटना की जानकारी वन विभाग को दी. साथ ही उन्होंने वन विभाग से पीड़ित किसान को उचित मुआवजा तथा ग्रामीणों के बीच पटाखे व टॉर्च दिये जाने की मांग की.

### बीओआइ अधिकारी संघ का चुनाव कल

**नामकुम.** बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ झारखंड राज्य इकाई का चुनाव पहली मार्च को नामकुम के खरसीदाग स्थित उमंग बैंक्वेट हॉल में होगा. संघ के वर्तमान सचिव सुनिल लकड़ा ने बताया कि सदस्य चुनाव में 2026-2029 के लिए नयी कमेटी के लिए वोट करेंगे. पांच जोन धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची के सदस्य उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव, उपमहासचिव (रांची), सदस्य (गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़) पद के लिए मतदान करेंगे. श्री लकड़ा ने सभी सदस्यों से मतदान करने की अपील की है.

### कुड़मी अधिकार महारैली धुर्वा में कल

**अनगड़ा.** कुड़मी अधिकार महारैली पहली मार्च को प्रभात तारा मैदान, धुर्वा रांची में प्रस्तावित है. महारैली की तैयारी पूरी कर ली गयी है. कुरमी नेता रामपोदो महतो और वृहद झारखंड कुड़मी समन्वय समिति के केंद्रीय मीडिया प्रभारी सखीचंद महतो ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 18 कुड़मी संगठनों द्वारा आयोजित रैली के लिए गांव-गांव में प्रचार किया गया है. पारंपरिक वेशभूषा में लोगों से महारैली में आने की अपील की गयी है. रूट मैप भी जारी कर दिया गया है. उन्होंने नकारात्मक प्रचार से बचने का भी आग्रह किया है.

### सरहुल मिलन समारोह व जुलूस को लेकर बैठक

**बुढ़मू.** सिदरोल के चेड़ी सरना में शुक्रवार को प्रमुख सत्यनारायण मुंडा की अध्यक्षता में सरहुल मिलन समारोह व जुलूस को लेकर बैठक हुई. जिसमें सर्वसम्मति से समिति का पुनर्गठन किया गया. अध्यक्ष झिबरा मुंडा, सचिव हरिश्चंद्र पहान, कोषाध्यक्ष धर्मेश भगत, मीडिया प्रभारी सोनू मुंडा और उपाध्यक्ष राजेंद्र लोहरा को बनाया गया. सरहुल उपवास 20 मार्च, झखरा 21 और 25 मार्च को प्रखंड स्तरीय सरहुल मिलन समारोह सह जुलूस का आयोजन करने का निर्णय लिया गया. आयोजन की तैयारी को लेकर पांच मार्च को अगली बैठक होगी. संचालन सोनू मुंडा ने किया. बैठक में पूर्व प्रमुख रामेश्वर पहान, चकमे पंचायत मुखिया रामवृत मुंडा, मुरुपीरी पंचायत मुखिया सीता देवी, विधायक प्रतिनिधि रामकुमार टाना भगत, आकाश मुंडा, मनोज पहान, विष्णु गोड़ाइत, रामधरम मुंडा, शिवचरण पहान, रखिंद्र पहान सहित अन्य उपस्थित थे.

### गोला-मुरी मार्ग पर बनेंगे दो आरओबी

**रांची.** गोला-मुरी रोड के बीच दो आरओबी का निर्माण कराया जायेगा. इसके लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. डीपीआर के लिए कंसल्टेंट का चयन किया जा रहा है. इसके लिए पथ निर्माण विभाग ने इच्छुक कंसल्टेंट से नौ मार्च तक आवेदन मांगा है. कंसल्टेंट का चयन करके दो माह में योजना के लिए डीपीआर तैयार कराया जायेगा. फिर योजना की स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी.

### राज्य सम्मेलन में जुटे क्षेत्र के लोग

**पिस्कानगड़ी.** नगड़ी प्रखंड के नारो पंचायत में आयोजित झारखंड राज्य किसान सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कामरेड कृष्ण प्रसाद ने दूसरे दिन के राज्य सम्मेलन का उदघाटन किया. उन्होंने किसान विरोधी बीज, बिजली विधेयक, चार लेबर कोड, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, मनरेगा का नया नामकरण, झारखंड में खनिज संपदा की लूट का विरोध किया.

## बुंडू नगर पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होने पर जितेंद्र उरांव के समर्थन में निकला विजय जुलूस

# बुंडू नगर पंचायत अध्यक्ष बने जितेंद्र उरांव

बुंडू नगर निकाय चुनाव का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया. रांची में मतों की गिनती के लिए सुबह से गहमागहमी रही. सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ सुबह से ही मतगणना केंद्र पर जुट गये थे. जैसे-जैसे मतों की गिनती हो रही थी कुछ समर्थक केंद्र से जाने लगे. विजेता की घोषणा होते ही उनके समर्थक जयकारे के साथ नाचने लगे.

### निर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र उरांव ने विजय जुलूस निकाला

**बुंडू.** रांची के मतगणना केंद्र से बुंडू पहुंचते ही नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र उरांव को उनके समर्थकों ने बड़ी संख्या में उनके फूलमाला से स्वागत किया. इसके पश्चात उनके समर्थन में गाजे-बाजे के साथ पटाखा जलाते हुए विजय जुलूस निकाला गया. विजय जुलूस बुंडू के बस स्टैंड से शुभारंभ होकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल गया. जहां जितेंद्र उरांव भगवान बिरसा की प्रतिमा को माला पहनाया. विजय जुलूस धुर्वा मोड़, थाना रोड, मेन रोड, सुभाष चौक, महावीर मंदिर चौक, काली मंदिर चौक, होकर, पुराना बाजार टोली में संपन्न हुआ. विजयी जुलूस में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष शामिल होकर नारेबाजी किये. कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी.

**विधायक ने जितेंद्र उरांव की जीत पर दी बधाई : बुंडू.** बुंडू नगर निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद अध्यक्ष पद पर विजयी जितेंद्र उरांव को विधायक विकास कुमार मुंडा ने बधाई दी. उन्होंने बुंडू के नगर की जनता के प्रति आभार प्रकट किया. जितेंद्र उरांव की जीत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में उत्साह का माहौल है. एनडीए समर्थित भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजेश उरांव के घर पर एनडीए खेमे में निराशा छायी हुई है. विजयी घोषित जितेंद्र उरांव ने बातचीत में कहा कि मैं बुंडू नगर के जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं और बुंडू नगर के सर्वांगीण विकास के हित में लगातार कार्य करूंगा. जितेंद्र उरांव की जीत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन होने विजयी का जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी.

विजय जुलूस में नवनिर्वाचित नगर पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र उरांव

नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र उरांव व समर्थक.

### जीते हुए प्रत्याशी

1. घासीराम उरांव 394, छठा स्थान पर
2. जितेंद्र उरांव - 4007, विजेता
3. विजय बड़ाइक 1942 तीसरे स्थान पर
4. राजेश उरांव 3198 दूसरे स्थान पर
5. रितेश कुमार पातर 190, सातवें स्थान पर
6. शंकर सिंह मुंडा 533 पांचवां स्थान पर
7. श्रीकृष्ण मुंडा 1040 चौथे स्थान पर

**विजयी वार्ड पार्षदों की सूची**

वार्ड – 1 मंजू देवी
वार्ड – 2 राधा देवी
वार्ड – 3 करिश्मा भगत
वार्ड – 4 पूजा जायसवाल
वार्ड – 5 कमला देवी
वार्ड – 6 अरशद अंसारी
वार्ड – 7 नेपाल दस
वार्ड – 8 लालू उरांव
वार्ड – 9 बॉबी मछुआ
वार्ड – 10 धनंजय प्रमाणिक
वार्ड – 11 राकेश मछुवा
वार्ड – 12 सीमा देवी
वार्ड – 13 मंगिता देवी

# खलारी रोड में ट्रक व टेंपो की टक्कर में दो महिलाओं की मौत, चालक और एक अन्य महिला घायल, भर्ती

प्रतिनिधि, चान्हो

बीजुपाड़ा-खलारी मार्ग में चोड़ा के निकट गुरुवार की रात ट्रक व डाला टेंपो के बीच टक्कर हो गयी. जिससे टेंपो पर सवार दो महिलाओं की मौत हो गयी. जबकि चालक व एक अन्य महिला घायल हो गये.

मृतकों में बुढ़मू के गम्हरिया गांव की मंजू देवी (40) व चान्हो के चोड़ा की लक्ष्मनिया उरांइन (55) शामिल हैं. वहीं गम्हरिया का ही चालक उमेश भगत (48) व चोड़ा गांव की सोमरी उरांइन (40) घायल हुए हैं. घायल उमेश भगत को इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है. सोमरी उरांइन को मांडर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है. हादसा रात करीब 8.30 बजे की है. बताया जा रहा है कि मृत मंजू देवी व उसका पति उमेश भगत अपने टेंपो में स्थानीय हाट बाजार से सब्जी खरीदकर उसे प्रतिदिन खलारी एरिया में ले जाकर बेचा करते थे. वे गुरुवार को भी खलारी से सब्जी बेचकर अपने टेंपो से घर लौट रहे थे. रास्ते में उन्होंने सब्जी बेचनेवाली चोड़ा गांव की दो महिलाओं को भी टेंपो में बैठा लिया था. इसी क्रम में चोड़ा मोड़ के निकट सामने से आ रहे एक खाली ट्रक से उनकी टक्कर हो गयी. टक्कर से टेंपो पलट गया. हादसे के बाद घायलों को चान्हो पुलिस ने इलाज के लिए मांडर के एक निजी अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में गुरुवार को रात के करीब 10 बजे इलाज के क्रम में मंजू देवी की, जबकि लक्ष्मनिया उरांइन की शुक्रवार को दिन में मौत हो गयी. चान्हो पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मंजू देवी के शव को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. लक्ष्मनिया उरांइन के शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है. इधर रिम्स में इलाजरत टेंपो चालक उमेश भगत की हालत भी गंभीर बतायी जा रही है.

### ट्रैक्टर की ट्राली से टकरायी स्कूटी, जीजा-साले की मौत

प्रतिनिधि, खूंटी

खूंटी शहर के पिपराटोली में रांची-खूंटी मार्ग में सड़क किनारे खड़ा ट्रैक्टर की ट्राली दो लोगों के मौत का कारण बन गया. गुरुवार देर रात ट्रैक्टर की ट्राली से एक स्कूटी टकरा गयी. जिसमें स्कूटी सवार जीजा और साला की मौत हो गयी. मृतकों में मस्जिद गली, करां रोड खूंटी निवासी प्रदीप महतो (30) और उसके जीजा रांची के इटकी थाना क्षेत्र के कुरगी गांव निवासी संदीप प्रजापति (32) शामिल हैं. जानकारी के अनुसार दोनों मुंडन समारोह में शामिल होने डोड़मा गये थे. वहां से देर रात स्कूटी से खूंटी लौट रहे थे. इसी क्रम में पिपराटोली में सड़क के किनारे खड़े ट्रैक्टर की ट्राली से स्कूटी टकरा गयी. जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा. जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतक प्रदीप महतो के बड़े भाई संदीप महतो ने बताया कि प्रदीप अपने जीजा संदीप प्रजापति के साथ डोड़मा में रहनेवाली बहन के घर मुंडन समारोह में गया था. शुक्रवार को दोनों के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया. हादसे के बाद परिवार में दुःखों का पहाड़ टूट गया है.

संदीप प्रजापति और प्रदीप महतो का फाइल फोटो.

### 12वां माटी महोत्सव में जुटे ग्रामीण

माटी महोत्सव में शामिल लोग.

प्रतिनिधि, ओरमांझी

आरटीसी कॉलेज ने एनएसएस के तहत शुक्रवार को 12वां माटी महोत्सव 2026 का आयोजन किया. स्वर्णरेखा डैम के किनारे विस्थापित गांव हतवाल में मिट्टी स्नान और सूर्य के प्रकाश स्नान कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने लोगों को मिट्टी लगाकर किया. कहा कि दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण, खान-पान, कृषि में रसायन और कीटनाशक का प्रयोग ने मनुष्य के सामने स्वस्थ जीवन जीने में एक चुनौती खड़ी कर दी है. इस समस्या के समाधान के लिए हमें अपनी पुरानी प्राकृतिक जीवन शैली की तरफ फिर से लौटना होगा. महोत्सव में माटी स्नान और प्राकृतिक चिकित्सा पर बहुत विषद विश्लेषण करते हुए कॉलेज के निदेशक योग गुरु व क्षेत्र के शिक्षाविद डॉ पारस नाथ महतो ने कहा कि मिट्टी स्नान और सूरज के प्रकाश की थेरेपी में गंभीर और जटिल बीमारियों से छुटकारा प्रदान करने की शक्ति है. वहीं कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉ रुद्र नारायण महतो, जय गोविंद साहू, प्रो शैलेन्द्र मिश्र, रंधीर चौधरी, धनीलाल महतो, सुजीत कुमार, कैलाश पाहन, सोनामनी देवी, लालमनी देवी ने मिट्टी महोत्सव के महत्व पर प्रकाश डाला. समारोह में वुमेन ऑफ द इयर का पुरस्कार लालमनी देवी को दिया गया. साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया. लोगों ने स्नान के बाद मिट्टी के बर्तन में बने लजीज भोजन और स्वर्णरेखा डैम में नौका विहार का लुत्फ लिया. झारखंड के गीत-संगीत व नृत्य पर लोग झूमे.

# राज्य स्तरीय किसान मेला में 10 हजार किसान जुटे

प्रतिनिधि, अनगड़ा

रामकृष्ण मिशन आश्रम फॉर्म गेतलसूद में आयोजित दो दिवसीय श्री रामकृष्ण किसान मेला शुक्रवार को संपन्न हो गया. राज्यस्तरीय मेला के समापन समारोह में लगभग 10 हजार किसानों ने हिस्सा लिया. मुख्य अतिथि नाबार्ड की सीजीएम दीपमाला घोष ने जलछाजन व कृषि योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने किसानों से एआइ और जल संरक्षण तकनीक अपनाने की अपील की. आश्रम के सचिव स्वामी भवेशानंद महाराज ने उन्नत कृषि के जरिए 2047 तक भारत को विकसित व विश्वगुरु बनाने का आह्वान किया. वहीं, तसर अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ बाला सरस्वती एस, डॉ अवनी कुमार सिंह और जेएसएलपीएस के सीओओ विष्णु चरण परिदा ने किसानों व महिला समूहों को आमदनी बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीके बताये. किसान गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों ने किसानों की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान किया. उत्कृष्ट खेती, पशुपालन और कुटीर उद्योग के लिए किसानों को कुल 78 पुरस्कार (फसल/सब्जी-54, पशुपालन-12, कुटीर उद्योग-12) दिये गये. इसके अलावा टीएसपी योजना के तहत 586 किसानों के बीच हस्तचालित स्प्रेयर का वितरण किया गया. मेले में लगे 50 स्टॉलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेसर्स प्रिया एग्रीको और इफको को प्रथम पुरस्कार मिला. आदिवासी मॉडल पंचायत बनाने के प्रयासों के लिए नवागढ़ के मुखिया भुवनेश्वर बेदिया को तथा जैविक कृषि के लिए बड़की गोरांग के किसान जगदीश भोगता को पुरस्कार दिया गया. उषा मार्टिन फाउंडेशन के स्टॉल को लोगों ने काफी पसंद किया. इस अवसर पर जिप सदस्य अनुराधा मुंडा, राजेन्द्र शाही मुंडा, डॉ राजेश कुमार, जैलेंद्र कुमार, रामसाय मुंडा, प्रमुख दीपा उरांव, मेला समिति अध्यक्ष संतोष बेदिया, राजकुमार बेदिया, देवनारायण बेदिया, अशोक बेदिया, कमल बेदिया, पहलू बेदिया सहित अन्य उपस्थित थे.

किसान मेला उपस्थित अतिथि व अन्य.

# टीएसपीसी का एरिया कमांडर आदिल गिरफ्तार

प्रतिनिधि, खलारी

प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) के उत्तरी-दक्षिणी छोटानागपुर सीमांत जोनल कमेटी के एरिया कमांडर आदिल अंसारी उर्फ विभीषण जी को खलारी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसकी गिरफ्तारी शुक्रवार तड़के करीब 2.30 बजे लोहरदगा स्थित उसके आवास से की गयी. वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक खलारी आरएन चौधरी के नेतृत्व में की गयी. अभियान में थाना प्रभारी खलारी पुलिस निरीक्षक जयदीप टोप्पो, मेक्लुस्कीगंज थाना प्रभारी धनंजय बैठा तथा सुरक्षा बलों की टीम ने अहम भूमिका निभायी.

बताया जाता है कि बीते डेढ़ वर्ष से आदिल पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था. कई मामलों में उसकी संलिप्तता सामने आयी थी. मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार रात आदिल लोहरदगा में अपने परिवार के साथ मौजूद था. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार तड़के दो से ढाई बजे के बीच उसके ठिकाने को घेर लिया. खुद को घिरता देख आदिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान छज्जे से गिर जाने के कारण उसका बायां हाथ टूट गया. पुलिस ने उसे तुरंत कब्जे में लेकर उपचार कराया. समाचार लिखे जाने तक उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही थी.

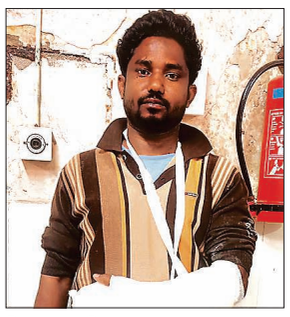

गिफ्तार आदिल.

### कोयला कारोबारी से नक्सली बना आदिल

खलारी निवासी आदिल अंसारी पहले पिपरवार क्षेत्र में कोयला कारोबार से जुड़ा था. बताया जाता है कि नक्सली संगठनों को लेवी देते-देते वह स्वयं टीएसपीसी से जुड़ गया. धीरे-धीरे उसका नाम कई आपराधिक और उग्रवादी गतिविधियों में सामने आने लगा. जो आदिल कभी लेवी देता था, वही बाद में लेवी मांगने लगा. करीब डेढ़ साल से वह संगठन के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था. उसकी पत्नी और तीन छोटे बच्चे हैं. उग्रवादी संगठन से नाम जुड़ने के बाद परिवार के लोग भी काफी असहज और परेशान थे. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आदिल की गिरफ्तारी से क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा और आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी.

## खबरें झारखंड की

### डॉ ऋत्विज और डॉ जसवानी को आशीर्वाद देने पहुंचे मुख्यमंत्री

संवाददाता, गोड्डा/पोड़ैयाहाट

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी, गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ पोड़ैयाहाट प्रखंड के बोहरा गांव पहुंचे. यहां वे विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के बड़े पुत्र डॉ. ऋत्विज और बहू डॉ. जसवानी के रिसेप्शन समारोह में शामिल हुए. समारोह में मुख्यमंत्री ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगभग 45 मिनट तक समारोह में रुके. इस दौरान वे परिवार के साथ बातचीत करते रहे और समारोह के आयोजकों से भी मिले. इसके बाद, सीएम 2:52 बजे हेलीकॉप्टर से रांची के लिए रवाना हो गये.

### उग्रवादियों ने बमबारी के बाद जेसीबी में लगायी आग

प्रतिनिधि, भदानीनगर

**भदानीनगर**

**3.5 करोड़ के पुल निर्माण साइट पर भी फेंका बम**

**पर्चे फेंक क्रशर मालिकों को दी जान से मारने की धमकी**

**घटना के बाद उग्रवादी ओरमांझी की ओर भाग गये**

जेजेएमपी उग्रवादियों ने गुरुवार की मध्य रात सुथरपुर एतियातू स्थित निर्माणाधीन श्रीराम स्टोन क्रशर में बमबारी के बाद वहां खड़ी जेसीबी मशीन में आग लगा दी. दो बाइक से पहुंचे चार उग्रवादियों ने बमबारी से पहले वहां मौजूद कर्मी रोहित साहू, बालकिशुन उरांव, बसंत उरांव, प्रभु उरांव, विक्की उरांव, निशांत उरांव को एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद क्रशर परिसर में बमबारी के बाद जेसीबी को आग के हवाले कर दिया. उग्रवादियों ने मनोज तुरी के नाम का धमकी भरा पर्चा छोड़ते हुए प्रोटेक्शन मनी की मांग की है. ऐसा नहीं होने पर गोली मार देने की धमकी दी है. पर्चे में सुथरपुर के पाउडर क्रशर व लेम क्रशर के मालिक को जान से मारने की धमकी दी है.

क्रशर के कर्मियों के अनुसार, सभी उग्रवादी नकाबपोश थे. एक के हाथ में बंदूक थी, जबकि अन्य के पास लोहे का हथियार था. मुंशी विनय कुमार व प्रकाश मिस्त्री ने घटना के बाद सभी को कमरे से बाहर निकाला व पुलिस को जानकारी दी. इसके बाद उग्रवादियों ने सुथरपुर बेहरा टोला में 3.5 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के साइट पर भी तीन बम का धमाका किया. हालांकि, यहां पर उग्रवादियों ने कोई पर्चा नहीं छोड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि बम धमाका कर पुल के ठेकेदार को संदेश दिया गया है. घटना को अंजाम देने के बाद उग्रवादी ओरमांझी की ओर भाग गये. उक्त क्रशर का काम नवंबर महीने से चालू हुआ है. फिलहाल मशीन बैठाने का काम चल रहा है. घटना की सूचना पर भदानीनगर पुलिस शुक्रवार की सुबह करीब सात बजे सुथरपुर पहुंची. करीब एक बजे एसडीपीओ पतरातू सर्किल के अन्य थानों व टेक्निकल टीम के साथ जांच के लिए पहुंचे थे. इधर, क्रशर मालिक ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना में मामला दर्ज कराया है.

### एक्सएलआरआइ के सर्टिफिकेट कोर्स के छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

एक्सएलआरआइ में शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र आर्यन राज (20 वर्ष) की 25 फरवरी की रात संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गयी. वह टेल्को थाना अंतर्गत ट्रक पार्क स्थित क्रॉस रोड-29 निवासी सेवानिवृत्त टाटा मोटर्स कर्मी बीरेन्द्र कुमार सिंह का पुत्र था. जानकारी के अनुसार, आर्यन को 26 फरवरी की सुबह पिता उठाने गये, तो वह नहीं जागा. इसके बाद आनन-फानन में उसे टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. इधर, घटना की सूचना मिलने पर टेल्को थाना पुलिस टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंची और पिता से बात कर जानकारी हासिल की. पुलिस की रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ पीने की संभावना जतायी जा रही है, क्योंकि आर्यन के शरीर का कुछ हिस्सा नीला पड़ गया था. हालांकि, मामले में पिता ने अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज कराया है. बेटे की मौत के लिए किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया है. आर्यन ने चिन्मया स्कूल ने प्लस टू की पढ़ाई की थी. वह घर का इकलौता बेटा था.

अमर उजाला

# प्रवाह

7 साल बेमिसाल

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

नई दिल्ली ■ शनिवार, 28 फरवरी 2026

शिक्षा का अर्थ सच्चाई की खोज है। यह कभी न खत्म होने वाली यात्रा है।
-एपीजे अब्दुल कलाम

# पाकिस्तान की तिलमिलाहट

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के इकसठवें नियमित सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भारत ने उचित ही उसे जमकर लताड़ लगाई है, हालांकि इससे उसके रवैये में सुधार की उम्मीद रखना बेमानी ही होगा। दरअसल, वैश्विक मंचों पर बार-बार विफल होने के बावजूद पाकिस्तान की जिद दर्शाती है कि वह यथार्थ से अधिक भ्रम की राजनीति में ही विश्वास करता है। कश्मीर पर उसकी बयानबाजी भी अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक घिसी-पिटी कहानी बन चुकी है, जिसका तथ्यात्मक आधार कमजोर और राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट है। जबकि सच तो यह है कि अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद से कश्मीर में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। हालिया चुनावों में रिकॉर्ड मतदान जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक भागीदारी और स्थिरता का ही प्रमाण है। सम्मेलन में भारतीय राजनयिक की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि जम्मू-कश्मीर का विकास-बजट पाकिस्तान द्वारा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मांगे गए बेलआउट पैकेज के दोगुने से भी अधिक है। अलबत्ता, यह तथ्य पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली और जम्मू-कश्मीर की प्रगति के बीच स्पष्ट विरोधाभास को उजागर करता है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस देश की अपनी सीमाएं अस्थिरता से जूझ रही हों, वह दूसरों पर आरोप लगा रहा है। अफगानिस्तान पर हो रहे पाकिस्तानी हमले यह दर्शाने के लिए काफी हैं कि इस्लामाबाद अपने ही पड़ोस में शांति स्थापित करने में विफल रहा है। पाकिस्तान की मनोदशा इससे ही समझी जा सकती है कि जब भारत ने इस हमले के लिए उसकी निंदा की, तब इस्लामाबाद बगैर किसी साक्ष्य के भारत पर ही पाकिस्तान-विरोधी गतिविधियों के समर्थन का आरोप लगाने लगा। मानवाधिकारों के मोर्चे पर भी देखें, तो पाकिस्तान के अपने रिकॉर्ड पर गंभीर प्रश्नचिह्न दिखते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जबरन गुमशुदगियों, अल्पसंख्यकों पर हमलों और अभिव्यक्ति

की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ भी लोग सड़कों पर आए-दिन उतरते रहते हैं। ऐसे में, भारत पर आरोप लगाना पाकिस्तान की तिलमिलाहट को ही अधिक दर्शाता है, जिस पर भारत का यह कहना बिल्कुल वाजिब है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि वह वैश्विक मंचों पर दिखावा करना छोड़, अपने अंदरूनी संकटों पर ध्यान दे।

# आखिर इस मर्ज की दवा क्या है

**सोशल मीडिया में व्यंग्य बन रहे हैं कि किताब पर रोक लगाने के बाद अब न्यायपालिका से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। न्यायिक प्रशासन की स्वतत्रंता और जजों का सम्मान बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार पर आंख मूंदने के बजाय इस पर स्वस्थ बहस और ठोस कार्रवाई की जरूरत है।**

घूसखोर पंडत फिल्म का नाम बदलने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जज उज्ज्वल भुयान ने लिखा है कि किसी भी समुदाय का अपमानजनक चित्रण गलत है। इसलिए न्यायपालिका के एकतरफा गलत चित्रण के मामले में एनसीईआरटी की किताब पर प्रतिबंध को सही ठहराया जा सकता है। न्यायपालिका की स्वतत्रंता और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई आपराधिक साजिश हुई है, तो उसका भी जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए।

सामान्य तौर पर इस किताब को कुछ हजार छात्र ही पढ़ते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सभी राज्यों को नोटिस, प्रधानाचार्यों की जवाबदेही और मीडिया में सुर्खियों की वजह से पूरे देश में इस मुद्दे पर बहस होने लगी है। अति प्रतिक्रियाशील होकर न्यायिक आदेश देने के बजाय यदि प्रशासनिक तरीके से किताब की गलतियों को ठीक कर दिया जाता, तो जजों और न्यायिक व्यवस्था को इस विवाद से हो रहे नुकसान से बचाया जा सकता था।

**विराग गुप्ता**
*सुप्रीम कोर्ट के वकील*

वर्ष 2020 में जारी नई शिक्षा नीति के अनुसार एनसीईआरटी की किताबों में बड़े बदलाव हुए हैं। उसके अनुसार, कक्षा सात और आठ की किताब में सरकार और जन-प्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय पहले से शामिल थे। न्यायपालिका से जुड़े नए अध्याय में लंबित मुकदमों का बोझ, जजों की नियुक्ति प्रणाली के साथ पूर्व चीफ जस्टिस गवई के बयानों के अनुसार, भ्रष्टाचार से जुड़ी विषयवस्तु शामिल की गई थी। कुछ अन्य न्यायिक घटनाओं के जरिये विवादित किताब से जुड़े विषय को सही ढंग से समझा जा सकता है।

पिछले साल होली के समय दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बंगले में नोटों के बंडल जलने का सनसनीखेज मामला आया था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत अनेक लोगों ने वर्मा के खिलाफ पुलिस या सीबीआई में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उन्हें ट्रांसफर करके मामले को जांच समिति के हवाले कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अब रिटायर भी हो रहे हैं। कंडक्टर के 10 रुपये के भ्रष्टाचार

के मामले में सख्त रवैया अपनाने वाली न्यायपालिका ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ऐसे अनेक मामलों से सोशल मीडिया में जजों के खिलाफ असंतोष और गुस्सा बढ़ रहा है। मर्ज को ठीक करने के बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो जजों की पीठ ने सोशल मीडिया में बढ़ रही अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला शुरू करने की चेतावनी दी है।

सरकार और नेताओं की तरह न्यायपालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को पिछले कई दशकों से स्वीकारा जा रहा है। वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सामूहिक तौर पर 16 सूत्री प्रस्तावों से न्यायपालिका में निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रति वचनबद्धता को दोहराया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भरुचा ने वर्ष 2002 में सार्वजनिक तौर पर कहा था कि 80 फीसदी जज ईमानदार हैं, लेकिन बकाया भ्रष्ट जजों की वजह से न्यायिक व्यवस्था बदनाम हो रही है। वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जज काटजू और ज्ञानसुधा मिश्रा की पीठ ने न्यायपालिका में भाई-भतीजावाद और बढ़ते भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए लिखित न्यायिक आदेश पारित किया था। पूर्व कानून मंत्री शांतिभूषण ने हलफनामे में अनेक जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन उन्हें अवमानना के तहत दंडित नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश जज रिटायरमेंट के बाद भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खिलाफ बोलते हैं। स्कूली किताब पर विवाद के दौरान ही अन्य मामले में वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने ट्रिब्यूनल्स की कार्यप्रणाली पर कठोर टिप्पणी करते हुए उन्हें बोझ और झंझट बताया है। सनद रहे कि अधिकांश ट्रिब्यूनल में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मुखिया और न्यायिक सदस्य नियुक्त होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के प्रशासनिक मुखिया चीफ जस्टिस हैं। मुकदमों की लिस्टिंग में अनियमितता पर नाराजगी जताते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि रजिस्ट्री के कामकाज में त्वरित और बड़े सुधारों की जरूरत है।

कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में एनजेएसी का कानून बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने उसे निरस्त कर दिया था। उस मामले में जज कुरियन जोसेफ ने फैसले में लिखा था कि कॉलेजियम प्रणाली से जजों की मनमानी नियुक्ति से न्यायिक व्यवस्था में बढ़ रही सड़ांध को रोकने के लिए पेरिस्त्रोइका (पुनर्निर्माण) और ग्लासनोस्त (खुलेपन) की जरूरत है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में हजारों जजों की नियुक्ति हो गई, लेकिन उस सड़ांध को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या संसद ने ठोस कदम नहीं उठाया।

संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी अब तक किसी भी जज को महाभियोग के तहत हटाया नहीं गया है। संसद में दिए गए सरकारी जवाब के अनुसार, जजों के खिलाफ आठ हजार से ज्यादा शिकायतें आई हैं। संविधान के अनुसार, जल्द न्याय लोगों का मौलिक अधिकार है। जजों से अन्य वर्गों की अपेक्षा ज्यादा ईमानदारी की अपेक्षा रहती है, इसलिए उन्हें महामहिम के सम्मान के साथ अनेक सांविधानिक संरक्षण मिले हैं। इसके बावजूद जजों के खिलाफ शिकायतों के निवारण और कार्रवाई के लिए पारदर्शी और ठोस प्रणाली नहीं है।

अन्ना आंदोलन के बाद लोकपाल को भ्रष्टाचार के विरुद्ध वरदान बताया गया था, लेकिन वह अपने मकसद में पूरी तरह से विफल हो गया। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यायिक व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, निष्पक्ष और ईमानदार बनाने की जरूरत है। सोशल मीडिया में व्यंग्य बन रहे हैं कि किताब पर रोक लगाने के बाद अब न्यायपालिका से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। न्यायिक प्रशासन की स्वतंत्रता और जजों का सम्मान बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार पर आंख मूंदने के बजाय इस पर स्वस्थ बहस और ठोस कार्रवाई की जरूरत है।

अनेक जज नाबालिग बच्चों की यौन शिक्षा और सहमति से संबंधों के पक्षधर हैं। इसलिए अफसरों और नेताओं के साथ जजों के भ्रष्टाचार के बारे में भी बच्चों को स्वस्थ तरीके से जागरूक करने पर विवाद करना ठीक नहीं है। इंटरनेट और डार्क वेब की दुनिया में किताबों के अध्ययन से जागरूक बच्चे जिम्मेदार नागरिक बनकर सुशासन से गणतंत्र को मजबूत करने के साथ विकसित भारत का सपना साकार कर सकते हैं।

edit@amarujala.com

## अंतरराष्ट्रीय

# सिर्फ टैरिफ चुनौती नहीं

■ द न्यूयॉर्क टाइम्स

**वैश्विक व्यापार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बेशक टैरिफ को माना जा रहा है, पर चीन का बढ़ता व्यापार अधिशेष भी एक बड़ा संकट है, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है।**

हाल ही में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चीन का व्यापार अधिशेष 2025 में बढ़कर चौंकाने वाले 11.9 खरब डॉलर तक पहुंच गया था। यह आंकड़ा एक ओर चीन की जबर्दस्त निर्यात क्षमता को दिखाता है, तो दूसरी ओर उसकी अर्थव्यवस्था की कमजोरियों और उन तौर-तरीकों की ओर भी इशारा करता है, जो मुक्त व्यापार के लिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से भी बड़ा खतरा बनते दिख रहे हैं।

अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व की भूमिका से पीछे हटने के बीच, चीन ने खुद को वैश्वीकरण का समर्थक और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का रक्षक बताने की कोशिश की और संयोग से, उस व्यवस्था का निर्माण करने में अमेरिका की भी अहम भूमिका रही है। चीन का आर्थिक मॉडल विकास तो लाया है, पर संतुलन के बिना। हाल के वर्षों में इमारतों, मशीनरी और उपकरणों में निवेश उसकी वृद्धि का मुख्य इंजन बना। इस भारी निवेश का नतीजा बड़े पैमाने पर उत्पादन के रूप में सामने तो आया, लेकिन घरेलू खपत उत्पादन की रफ्तार के साथ नहीं बढ़ पाई है। इसी वजह से चीनी परिवार खुलकर खर्च करने के बजाय बचत करना पसंद कर रहे हैं। सरकार की आर्थिक प्रबंधन क्षमता को लेकर चिंताओं ने भी घरेलू भरोसे को चोट पहुंचाई है, जिससे मांग और दब गई।

**ईश्वर प्रसाद**

जब कोई अर्थव्यवस्था जितना उपभोग करती है उससे कहीं अधिक उत्पादन करती है, तो संतुलन बिगड़ता है। एक रास्ता यह होता है कि कीमतें गिरें, ताकि उपभोक्ता ज्यादा सामान खरीदें। पर अगर परिवारों को लगातार कीमतें गिरने की आशंका हो, तो वे खरीद बढ़ाने के बजाय उसे टाल देते हैं। चीन इस समय ऐसे ही मंदी-दबाव (डिफ्लेशन) का सामना कर रहा है। ऐसे में, अब एक ही रास्ता बचता है-अतिरिक्त उत्पादन को विदेशों में खपाना। चीन ठीक यही कर रहा है। उसके निर्यात तेजी से बढ़े हैं। हालांकि, ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर लगाए गए ऊंचे शुल्कों के कारण अमेरिका को होने वाला चीन का निर्यात तेजी से घटा है। नतीजतन, चीन अपने अन्य व्यापारिक साझेदारों को निर्यात बढ़ा रहा है। चीनी निर्यात उन देश के निर्माताओं पर भारी पड़ रहा है, जो प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। जिन देशों पर इसका दबाव पड़ रहा है, वे अब प्रतिरोध कर रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का अपनी विकास दर को बनाए रखने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना, नियमों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था के बिखराव को और तेज करेगा। इसमें यदि ट्रंप के टैरिफ भी जोड़ दिए जाएं, तो चीनी निर्यात का यह दबाव जो कुछ बचा है, उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह कतई नहीं कि वैश्विक व्यापार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, लेकिन व्यापार अब ऐसे ढंग से बंटता जा रहा है, जिससे कुल लाभ कम हो रहा है। इस तरह के विभाजन का सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब अर्थव्यवस्थाओं को होगा, जो वैश्विक व्यापार में अपनी जगह बना रही हैं।

तो चीन क्या कर सकता है? वह अपने सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने जैसे सुधार कर सकता है, ताकि उसके नागरिक ज्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित हों। चीन का केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा को मजबूत होने की अनुमति दे सकता है, जिसका वह हाल तक विरोध करता रहा है। इससे चीनी निर्यात महंगे और आयात सस्ते हो जाएंगे और व्यापार अधिशेष घटाने में मदद मिलेगी। यदि मुद्रा का मूल्य केंद्रीय बैंक के बजाय बाजार की ताकतें तय करें, तो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में उसकी अहमियत भी बढ़ेगी-एक ऐसा लक्ष्य, जिसे बीजिंग लंबे समय से हासिल करना चाहता रहा है। दीर्घकाल में जो कदम सबसे बेहतर होंगे, उन्हें उठाकर चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी मदद कर सकता है। पर यदि ऐसा नहीं हुआ, तो चीन वैश्विक विकास को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, नई विश्व व्यवस्था में नेतृत्व की भूमिका का कोई भी दावा खो सकता है।

**असली खतरा यह नहीं है कि एआई खुद जागरूक हो जाएगा, बल्कि यह है कि वह बिना सवाल किए हमारे आदेशों का पालन करेगा।**
-मैक्स टेगमार्क

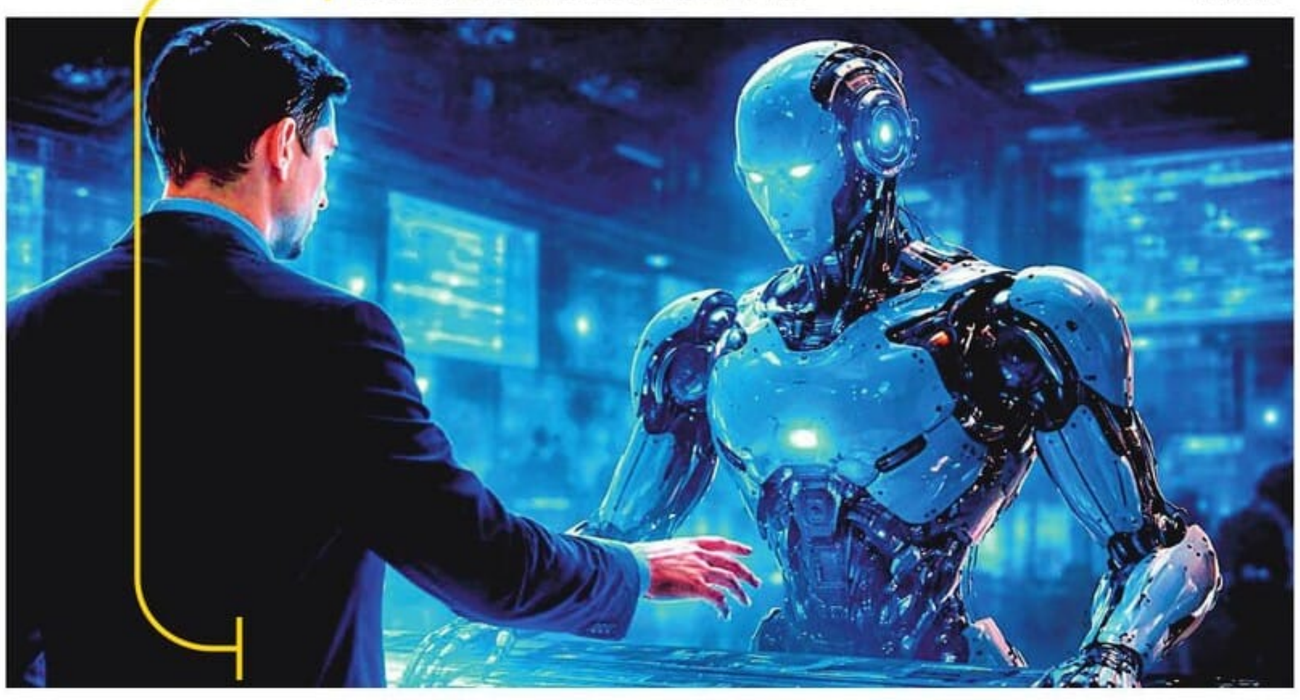

# तकनीक अंधेरे में मोमबत्ती की तरह है

**तकनीक हमारी आंखें और हाथ हैं, जिनसे हम अरबों मील दूर तक देख और मंगल की मिट्टी को छू सकते हैं। विज्ञान व तकनीक 'अंधेरे में एक मोमबत्ती' की तरह है, जिसे जलाने के लिए नैतिकता व सही सोच की जरूरत होती है।**

तकनीक केवल निर्जीव मशीनों, तारों या सर्किट का समूह नहीं है, बल्कि यह हमारी जैविक दुर्बलताओं और सितारों तक पहुंचने की अनंत इच्छाओं के बीच एक मजबूत पुल का निर्माण करती है। इस पुल पर चलकर ही हम न केवल अंतरिक्ष की दूरियों को मापते हैं, बल्कि अपने भीतर छिपी संभावनाओं को भी तलाशते हैं।

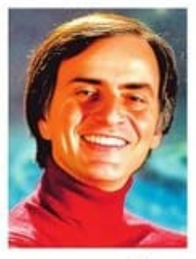

**कार्ल सेगन**

कई लोग खगोल विज्ञान को केवल ग्रहों की गणना करने तक ही सीमित मानते हैं, पर मेरा मानना है कि यह इन्सान को विनम्र बनाने और उसके चरित्र को निखारने का एक सशक्त माध्यम भी है। जब हम ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं, तो हमारा संकुचित दृष्टिकोण स्वतः ही विस्तृत होने लगता है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में सूरज की एक छोटी-सी किरण प्रवेश करती है, तब उसमें धूल के छोटे-छोटे कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह, असीमित अंतरिक्ष के गहरे कालेपन के बीच से देखने पर हमारी विशाल लगने वाली पृथ्वी भी सिर्फ एक नन्हा-सा चमकता हुआ सितारा या धूल का एक छोटा-सा कण मात्र प्रतीत होती है। हमारी दुनिया की यह धुंधली व सूक्ष्म तस्वीर दरअसल मानवीय अहंकार का सबसे बड़ा और जीवित सबूत है। यह दृश्य हमें उस गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है कि यही छोटा-सा ग्रह हमारा एकमात्र घर है और इस ब्रह्मांड में हमारे पास भागकर जाने के लिए कोई दूसरी जगह उपलब्ध नहीं है। अतः, हमारी सबसे पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी इसकी रक्षा करना ही है।

जीवन धारा

हमारा अस्तित्व इस बात पर टिका है कि हम अपनी तकनीकी शक्ति का इस्तेमाल नफरत के लिए करते हैं या मानवता के कल्याण के लिए। अंतरिक्ष यान और प्रोब हमारी इंद्रियों का ही विस्तार हैं। वे हमारी आंखें हैं, जो अरबों मील दूर देख सकती हैं और हमारे हाथ हैं, जो मंगल की मिट्टी को छू सकते हैं। वास्तव में, विज्ञान व तकनीक तो 'अंधेरे में एक मोमबत्ती' की तरह है, जिसे जलाने के लिए नैतिकता और सही सोच की जरूरत होती है। यदि कोई समाज तकनीक का उपभोग तो करता है, पर उसके पीछे के वैज्ञानिक तर्क व करुणा के आधार को नहीं समझता, तो वह अनजाने में ही विनाश की ओर बढ़ रहा है।

# कहीं आपका डॉक्टर चैटजीपीटी तो नहीं

**लैंग्वेज मॉडल्स की अपने उपयोगकर्ताओं को खुश करने की फितरत स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में खतरनाक साबित हो सकती है।**

**एडम रॉडमैन**
द न्यूयॉर्क टाइम्स

एक फिजिशियन होने के नाते, मैं इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हूं कि मेरे मरीज मेडिकल सलाह के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजतन, कई बार मरीज मेरे पास ऐसे परीक्षणों और संभावित बीमारियों की लंबी फेहरिस्त लेकर आते हैं, जिन्हें देखकर मैं चौंक जाता हूं। हालांकि, कई मरीज मासूमियत के साथ कबूल लेते हैं कि मुझसे मिलने से पहले उन्होंने 'डॉ. चैटजीपीटी' से मशविरा किया है। आंकड़े भी बताते हैं कि बड़ी संख्या में मरीज अपनी सेहत से जुड़े सवालों के लिए इन 'लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (एलएलएम)' पर भरोसा कर रहे हैं।

एक एआई शोधकर्ता होने के नाते मेरा यह मानना है कि सही ढंग से इस्तेमाल किए जाने पर ये मॉडल्स मरीजों को सशक्त बनाने वाले क्रांतिकारी हथियार साबित हो सकते हैं। पर, यह तकनीक मरीज और डॉक्टर के भरोसेमंद रिश्ते में दरार भी डाल सकती है, या फिर लोगों को मानसिक तनाव व चिंता की गहरी खाई में धकेल सकती है। ऐसे में, मरीजों के लिए एआई का सबसे अच्छा उपयोग यह है कि वे इसके जरिये डॉक्टर से अपनी मुलाकात को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। मरीजों की पहुंच उनकी मेडिकल रिपोर्ट तक तो होती है, पर अधिकांश लोग उन्हें कभी खोलकर भी नहीं देखते। जो देखते भी हैं, उनके लिए भारी-भरकम चिकित्सकीय शब्दावली को समझना या काम की बात निकालना मुश्किल होता है। इससे भी बुरा तब होता है, जब किसी पुरानी गलत रिपोर्ट या खारिज की जा चुकी बीमारी की जानकारी इन नोट्स में मौजूद रहती है, जिसे डॉक्टर अपनी भाषा में 'चार्ट लोर' कहते हैं। ऐसे मामलों में एआई मददगार हो सकता है।

बेशक, एआई उपकरण विशेषज्ञ स्तर की चिकित्सकीय सलाह देने में सक्षम हैं, पर उनकी सटीकता इस बात पर निर्भर करती है कि उनके पास मरीज की सेहत की पूरी तस्वीर है या नहीं। अपने लक्षणों को सबसे प्रभावी ढंग से समझाने के लिए, आप चैटबॉट से कह सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह लो। सवाल-जवाब का यह सिलसिला न केवल आपकी परेशानी को स्पष्ट रूप से बयां करने में मदद करेगा, बल्कि मन में डर पैदा करने वाली स्थितियों को भी खत्म करेगा।

लैंग्वेज मॉडल्स की फितरत अपने उपयोगकर्ताओं को खुश करने की होती है, जो स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इसे 'साइबरकॉन्ड्रिया' कहते हैं, जिसमें इंटरनेट पर सामान्य या हल्के लक्षणों की जानकारी खोजते-खोजते व्यक्ति डरावनी और गंभीर बीमारियों की संभावनाओं के जाल में फंस जाता है। चूंकि, एआई अचेतन इच्छाओं को पकड़ने में माहिर होते हैं, इसलिए वे समझ जाते हैं कि कौन-सी जानकारी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। वे इसे आपकी पसंद मान लेते हैं और वैसी ही बातें परोसने लगते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम आपको 'डूमस्क्रॉलिंग' (नकारात्मक खबरें पढ़ते रहना) के लिए उकसाते हैं। इससे बचने के लिए एआई से सवाल पूछते समय अपना मकसद साफ तौर पर बताना चाहिए। हालांकि, अगर एआई से बातचीत आपकी घबराहट या बेचैनी बढ़ा रही है, तो समझ लीजिए कि एआई अपनी चापलूसी वाली फितरत दिखा रहा है। ऐसे में, बिना देर किए सीधे अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

इसमें कोई शक नहीं कि एआई मॉडल्स भविष्य में बेहतर होंगे, पर मैं यही सलाह देता हूं कि अपनी संवेदनशील मेडिकल जानकारी बिना काट-छांट के किसी मशीन को सौंपने से पहले निजता के खतरों पर भी गंभीरता से विचार जरूर करें। एआई द्वारा दी गई राय आपके और डॉक्टर के बीच संवाद की शुरुआत होनी चाहिए, न कि इलाज का अंतिम फैसला। एआई बीमारी की पहचान में तो मददगार हो सकता है, पर इलाज की योजना के लिए इस पर भरोसा करना जोखिम भरा है, क्योंकि यहां अक्सर ये मात खा जाते हैं। पिछले साल *एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन* में डॉक्टरों ने सोडियम ब्रोमाइड पॉइजनिंग का एक चौंकाने वाला मामला दर्ज किया। एक शख्स ने साधारण नमक के विकल्प के तौर पर अपनी डाइट सुधारने के लिए चैटजीपीटी से सलाह ली थी। डॉक्टरों ने पाया कि वास्तव में चैटजीपीटी ने उसे सोडियम ब्रोमाइड को नमक के विकल्प के रूप में सुझाया था।

2026 की चिकित्सा व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज मरीज व डॉक्टर, दोनों ही नियमित रूप से एआई का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन एक-दूसरे को बताने से कतराते हैं। पिछले साल प्रकाशित एक सर्वे के अनुसार, लगभग 66 प्रतिशत डॉक्टरों ने कबूल किया कि वे 2024 से ही अपने अभ्यास में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मैं खुद भी शामिल हूं। मेरा मानना है कि एआई के इस्तेमाल को लेकर एक-दूसरे के प्रति ईमानदार रहना मरीज व डॉक्टर, दोनों के लिए बेहद जरूरी है।

**बफर**

*यह एक एआई-समर्थित सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल है, जिसकी मदद से व्यक्ति, व्यवसाय और कंटेंट क्रिएटर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को आसानी से संभाल सकते हैं। इस टूल के जरिये उपयोगकर्ता फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), लिंक्डइन और पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट पहले से तैयार करके निर्धारित समय पर अपने-आप प्रकाशित कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और नियमितता बनी रहती है। इसका एनालिटिक्स फीचर बताता है कि आपकी पोस्ट पर कितने लाइक्स, कमेंट और शेयर मिले, किस समय पोस्ट करने पर ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है और कौन-सा कंटेंट दर्शकों को अधिक पसंद आता है।*

# एजुकेशन & कॅरिअर

जीवन में समस्याएं आना तय है, लेकिन उनका हल ढूंढना आपकी सोच पर निर्भर करता है।

## अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

### संघ लोक सेवा आयोग

सीएपीएफ में सहायक कमांडेंट (ग्रुप-ए) के पद रिक्त




349 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 12 मार्च, 2026
योग्यताएं : स्नातक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : upsconline.nic.in

### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ■ 188 पद

लेखा अधिकारी, निजी सचिव व अन्य पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि
28 मार्च, 2026
पात्रताएं
ग्रेजुएशन, बीई, बीटेक व अन्य योग्यताएं
यहां आवेदन करें
drdo.gov.in

### आरआईआईसीओ में संभावनाएं ■ 121 पद

कंपनी सचिव, कनिष्ठ सहायक आदि पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि
07 मार्च, 2026
योग्यताएं
बारहवीं, स्नातक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
riico.rajasthan.gov.in

### दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ■ 216 पद

रेडियोग्राफर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, सहायक प्रबंधक व अन्य पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि : 28 मार्च, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 32 वर्ष
यहां आवेदन करें : dsssb.delhi.gov.in

### एम्स-सीएपीएफआईएम में अवसर ■ 49 पद

असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि
28 मार्च, 2026
वेतनमान
रुपये 1,01,500 से रुपये 1,67,400 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें
aiimsexams.ac.in

### एसईसीआई में निकली भर्ती ■ 19 पद

महाप्रबंधक, वरिष्ठ अभियंता व अन्य पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि
23 मार्च, 2026
योग्यताएं
बीकॉम, एमकॉम व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
seci.co.in

### विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी...

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण : चेयरपर्सन के पदों पर आवेदन आमंत्रित।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 13 अप्रैल, 2026
- fssai.gov.in
- भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ : अनुसंधान सहायक के पदों पर मौके।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 08 मार्च, 2026
- iiml.ac.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

# जिम्मेदारियां सिखाती भी हैं

*नई जिम्मेदारियों को परंपरागत तरीकों से संभालना कई बार नाकाफी हो सकता है, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार कार्यशैली में बदलाव लाएं*

**जेनी फर्नांडीज**
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू



नेतृत्व की असली परीक्षा तब होती है, जब अचानक एक बड़ी टीम की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है। ऐसे समय में काम का दबाव और निर्णय लेने की जिम्मेदारी बोझिल लग सकती है, खासकर तब जब स्पष्ट रणनीति न हो। लेकिन बड़े स्तर पर नेतृत्व का अर्थ केवल अधिक काम करना नहीं, बल्कि समझदारी से काम करना है। ठहरकर सोचना, प्राथमिकताएं तय करना, जिम्मेदारियां बांटना और टीम पर भरोसा करना जरूरी होता है। जब लीडर रणनीतिक सोच अपनाता है, तो न केवल उसका दबाव कम होता है, बल्कि टीम को भी स्पष्ट दिशा और मजबूत आधार मिलता है, जिससे वे बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं।

Harvard Business Review

**■ काम के तरीके को रीसेट करें**

लीडर्स को टीम के साथ मिलकर काम करने का तरीका फिर से तय करना चाहिए। बड़ी टीम में हर काम खुद करना तनाव बढ़ाता है, इसलिए जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से बांटना जरूरी है। साथ ही, टीम के साथ मिलकर नए और सरल काम करने के तरीके बनाने चाहिए-जैसे समय पर जोखिम साझा करना और अनावश्यक बैठकों से बचना। इससे काम का माहौल सहयोगपूर्ण बनता है, विश्वास बढ़ता है और टकराव कम होते हैं।

**■ प्राथमिकताएं तय करें**

जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो हर काम समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता। इसलिए लीडर्स को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन-से काम सबसे जरूरी हैं और किन्हें सौंपा जा सकता है। साथ ही, इन प्राथमिकताओं को टीम के सामने साफ तौर पर बताना भी जरूरी है। जब टीम को यह पता होता है कि इस सप्ताह या महीने के मुख्य लक्ष्य क्या हैं, तो वे भ्रमित नहीं होते। इससे समय और ऊर्जा की बचत होती है, निर्णय जल्दी होते हैं और बेहतर परिणाम मिलते हैं।

**■ सहयोगियों को मौका दें**

बड़ी टीम का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए लीडर्स को अपनी भूमिका में बदलाव लाना चाहिए। हर निर्णय स्वयं लेने के बजाय उन्हें योग्य सहयोगियों को आगे बढ़ाना चाहिए। सक्षम टीम लीडरों या वरिष्ठ सदस्यों को अधिकार देना और उन पर विश्वास रखना जरूरी है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। इससे काम की गति बढ़ती है और टीम में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। नियमित मार्गदर्शन देकर नेता अपने प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं।



**■ काम का माहौल सरल बनाएं**

जैसे-जैसे टीम बड़ी होती है, कार्यप्रणालियां अधिक जटिल हो जाती हैं। ऐसे में लीडर्स का दायित्व है कि वे प्रक्रियाओं को सरल बनाएं। इसके लिए उन्हें टीम से पूछना चाहिए कि उनके काम में कौन-सी बाधाएं आ रही हैं और फिर उन रुकावटों को दूर करना चाहिए। कभी-कभी एक छोटी अड़चन हटाना मामूली कदम लगता है, लेकिन यही छोटे कदम संगठन की कार्यसंस्कृति तय करते हैं। जब सिस्टम सरल होता है, तो टीम की ऊर्जा सही दिशा में लगती है। इससे काम की गति बढ़ती है और कर्मचारियों का उत्साह भी बना रहता है।

**आवेदन आमंत्रित**

## कैम्ब्रिज डिजिटल माइंड्स फेलोशिप-2026

**कैम्ब्रिज** डिजिटल माइंड्स फेलोशिप-2026, कैम्ब्रिज डिजिटल माइंड्स (कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय) द्वारा रीथिंक प्रायोरिटीज और प्रिज्म के सहयोग से प्रदान की जा रही है। यह फेलोशिप एक गहन आवासीय कार्यक्रम है, जिसे डिजिटल माइंड्स क्षेत्र में क्षमता निर्माण के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें तकनीकी और दार्शनिक समझ, सामाजिक एवं नीतिगत पहलुओं पर चिंतन, तथा परियोजना विकास के लिए संरचित मार्गदर्शन और सहायता शामिल है। इस फेलोशिप के लिए स्नातक छात्र, पोस्ट-डॉक्टरल शोधकर्ता, प्रारंभिक कॅरिअर के अकादमिक, या सरकार, नीति अथवा उद्योग में कार्यरत पेशेवर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, वे अभ्यर्थी भी पात्र हैं, जो एआई कल्याण या डिजिटल माइंड्स अनुसंधान में रुचि रखते हों या पूर्व में इस क्षेत्र से जुड़े रहे हों। उम्मीदवारों का चयन निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। चयनित प्रतिभागियों को 1,000 पाउंड का वजीफा प्रदान किया जाएगा। योग्य आवेदक आधिकारिक लिंक digitalminds.cam/fellowship/ पर जाकर 27 मार्च, 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

**इंटर्नशिप प्रोग्राम**

## आईआईटी, गांधीनगर का समर इंटर्नशिप

**भारतीय** प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गांधीनगर द्वारा समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस इंटर्नशिप में आवेदन करने के लिए आवश्यक है कि आवेदक भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों। यह इंटर्नशिप आठ सप्ताह की होगी और इसका आयोजन ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को आईआईटी गांधीनगर के संकाय सदस्यों के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा। चयनित छात्रों को इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रति सप्ताह 2000 रुपये का वजीफा तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। आवेदक अपनी अर्हता की जांच करते हुए आधिकारिक लिंक srip.iitgn.ac.in/info/ पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 05 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है।

**एग्जाम अलर्ट हफ्ते की परीक्षाएं**

## एनटीए सीयूईटी पीजी-2026

- **परीक्षा की तिथि :** 06 से 27 मार्च, 2026
- इस सीबीटी परीक्षा के भाषा विषय को छोड़कर ह्यूमैनिटीज, साइंस और सामान्य विषयों के प्रश्न-पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे, जबकि एमटेक के प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** exams.nta.nic.in/cuet-pg/

## रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 06 मार्च, 2026
- इस परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल साइंस और इंजीनियरिंग व मैथमेटिक्स आदि से 100 अंकों के 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।
- **यहां से परीक्षा केंद्र का विवरण देखें** tinyurl.com/3fbzavv6

## खुद को परखें

1. सीएम-302 किस देश द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल है?
   (a) चीन (b) रूस
   (c) जर्मनी (d) भारत
2. हाल ही में खबरों में छाई रही चांगू झील (त्सोंगमो) किस देश में स्थित है?
   (a) सिक्किम
   (b) असम
   (c) अरुणाचल प्रदेश
   (d) मिजोरम
3. 'राह-वीर' योजना किस मंत्रालय की पहल है?
   (a) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
   (b) गृह मंत्रालय
   (c) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
   (d) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

उत्तर : 1.a, 2.a, 3.d

**सामान्य ज्ञान**

## ऑपरेशन क्रैकडाउन



**■ क्या है**

यह साइबर अपराध के खिलाफ चलाया जा रहा एक संयुक्त अभियान है। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (टीजीसीएसबी) द्वारा इसकी परिकल्पना की गई और इसका नेतृत्व भी किया गया।

**■ चर्चा में क्यों**

हाल ही में, तेलंगाना राज्य में 'ऑपरेशन क्रैकडाउन' शुरू किया गया है।

**■ डाटा के आधार पर कार्रवाई**

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खाताधारकों, एजेंटों और बैंक अधिकारियों की संभावित सांठगांठ की जांच करना तथा डाटा के आधार पर कार्रवाई करते हुए साइबर अपराध की आर्थिक जड़ को समाप्त करना है।

**■ अवैध बैंक खातों को बंद करना**

इसके तहत धोखाधड़ी के पैसों को छिपाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अवैध बैंक खातों की पहचान कर उन्हें बंद किया जाता है, ताकि संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को कमजोर किया जा सके और बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

## पहचान

**शख्स : जैमिसन ली ग्रीर**

■ **चर्चा :** अमेरिकी टैरिफ नीति के निर्माण में बेहद अहम भूमिका।
**क्यों :** ट्रंप के खासमखास और अमेरिका के 20वें व्यापार प्रतिनिधि।

# टैरिफ का वास्तुकार

**साधारण परिवार में पले-बढ़े, बेहद नपा-तुला बोलते हैं, खूब पढ़ते-लिखते हैं और विक्टर ह्यूगो के उपन्यास *लेस मिजरेबल* के दीवाने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जिस टैरिफ नीति ने दुनिया के विभिन्न देशों की नींदें उड़ाई हुई हैं, उसके वास्तुकार यही जैमिसन ली ग्रीर हैं।**

स्कूल की घंटी बजते ही बाकी बच्चे मैदान की ओर भागते थे, पर एक दुबला-पतला लड़का अक्सर खेलने के बजाय दुनिया का नक्शा फैलाकर बैठ जाता। उसे देशों की सीमाएं याद करना नहीं, बल्कि यह समझना अच्छा लगता था कि कौन-सा देश क्या बनाता है और चीजें एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाती हैं। एक दिन उत्सुकतावश उसने अपनी मां से पूछा, 'अगर खिलौना चीन में बनता है, दुकान अमेरिका में है और खरीदार कोई और है, तो असली मालिक कौन है?' परिवार ने तो इसे बचपन की जिज्ञासा समझकर हंसी में टाल दिया, पर इसी तरह की जिज्ञासाएं उसकी पेशेवर सोच की नींव बनीं। उसने बचपन में ही पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर एक 'मिनी ट्रेड क्लब' बना लिया था। क्लब के बच्चे आपस में कॉमिक्स, कार्ड और वीडियो गेम की अदला-बदली करते थे, लेकिन वह लड़का हर अदला-बदली के लिए नियम लिखता-जैसे 'अगर हालत खराब है, तो मूल्य कम', 'देर से लौटाने पर जुर्माना' आदि। यह लड़का है जैमिसन ली ग्रीर, जिसे 2025 में 20वें अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के रूप में सीनेट से मंजूरी मिली और इसके तुरंत बाद ही उन्होंने अमेरिका की 'अमेरिका फर्स्ट' व्यापार नीतियों, चीन पर चल रहे टैरिफों और नए अंतरराष्ट्रीय समझौतों की रूपरेखा बनाने की जिम्मेदारी संभाली। आज वह फिर ट्रंप के खासमखास सलाहकार के रूप में अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में छाए हुए हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ पर रोक लगाने के बाद भी ट्रंप को राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वैश्विक टैरिफ को 15 फीसदी तक बढ़ाने और भारत, चीन व ब्राजील जैसे देशों के खिलाफ नई व्यापारिक नीति शुरू करने का कड़ा रुख अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टैरिफ नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ही दुनिया भर के आर्थिक विश्लेषक जैमिसन ली ग्रीर को ट्रंप की टैरिफ रणनीति का 'शांत वास्तुकार' कह रहे हैं।

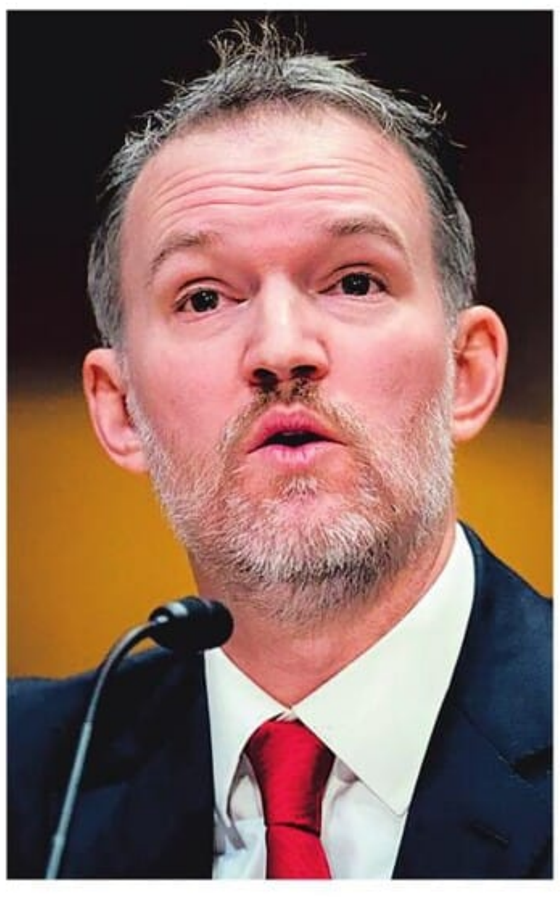



### 'मोबाइल होम' में बचपन

**जैमिसन ली** ग्रीर का जन्म चार मार्च, 1979 को अल्बानी, न्यूयॉर्क में हुआ था, पर उनका पालन-पोषण उत्तरी कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ। उनके माता-पिता, माइकल और शैनन ग्रीर, परिवार चलाने के लिए एक साथ कई नौकरियां करते थे। एक समय उनका परिवार 'मोबाइल होम' (पहियों वाले घर) में रहता था। चार भाई-बहनों में वह चौथे थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पैराडाइज हाई स्कूल, कैलिफोर्निया से 1998 में पूरी की। इसके बाद ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी (बीवाईयू) से उन्होंने 2004 में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने पेरिस के प्रतिष्ठित संस्थानों 'साइंसेज पो' और 'पैंथियन-सोरबोन विश्वविद्यालय' से ग्लोबल बिजनेस लॉ में मास्टर्स, जबकि वर्जीनिया विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ लॉ से कानून की डिग्री (जेडी) हासिल की है। उन्होंने अमेरिकी वायु सेना के 'जज एडवोकेट जनरल' (जेएजी) कोर में अधिकारी के रूप में कार्य किया। इस दौरान वह इराक में भी तैनात रहे, जहां उन्होंने 'चीफ ऑफ मिलिट्री जस्टिस' के रूप में अपनी सेवाएं दीं। सरकार में शामिल होने से पहले वे प्रतिष्ठित लॉ फर्म किंग एंड स्पैल्डिंग और स्कैडेन आर्प्स में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मामलों के पार्टनर के रूप में काम कर चुके थे। उन्होंने चीन के खिलाफ व्यापारिक मुकदमों में अमेरिकी स्टील कंपनियों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने चीन के साथ 'फेज वन' व्यापार समझौते तथा अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

### 'ट्रेड' से नाता

ग्रीर के पूर्वज टेनेसी के एक छोटे-से कस्बे से थे, जिसका नाम संयोगवश 'ट्रेड' था। वह मजाक में कहते हैं कि शायद नियति ने पहले ही तय कर लिया था कि वह बड़े होकर दुनिया के ट्रेड (व्यापार) समीकरणों को संभालेंगे। इंटरनेट पर उनका एक एआई अवतार भी मौजूद है, जिसके साथ एक गाना जोड़ा गया है। वह सार्वजनिक सुर्खियों से दूर रहते हैं। उनके सहकर्मियों के अनुसार, ग्रीर बेहद कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं, तो उनकी टिप्पणियां चर्चा की दिशा बदल देती हैं।

### एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड

*साल 2025 में जब जैमिसन ली ग्रीर को 20वें अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के रूप में चुना गया, तो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। साल 2009 के बाद वह पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जो 'मॉर्मन' समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और अमेरिका के इतने बड़े सरकारी पद (कैबिनेट स्तर) तक पहुंचे हैं। 'मॉर्मन' उन लोगों को कहा जाता है, जो 'द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स' नाम के ईसाई धार्मिक समूह को मानते हैं। ऐसे लोग परिवार को बहुत महत्व देते हैं। शायद यही कारण है कि ग्रीर अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देते हैं, और अपने अधिकतर संबोधनों में परिवार के त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। ग्रीर की पत्नी का नाम मार्लो ग्रीर है और उनके पांच बच्चे नोएल, पर्ल, ईव, जेम्सन और सोनोरा हैं।*

### पढ़ने-लिखने का शौक

**ग्रीर** को पढ़ने-लिखने का बेहद शौक है। वह इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संस्कृति, अंतरराष्ट्रीय मामलों और शास्त्रीय साहित्य से जुड़ी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। विक्टर ह्यूगो का उपन्यास *'लेस मिजरेबल'* उनका पसंदीदा है। उन्हें अपना खाली वक्त पुस्तकालय में बिताना अच्छा लगता है। इसके अलावा, वह अक्सर मीडिया संस्थानों के लिए भी लेख लिखते रहते हैं। जीवन से जुड़े खास लम्हों को वह पन्नों पर उतारना नहीं भूलते।

### टैरिफ हॉक का तमगा

**दूसरे** ट्रंप प्रशासन के दौरान चीन पर लगाए जाने वाले बड़े टैरिफ की रणनीति बनाने में ग्रीर को प्रमुख माना जाता है। उन्होंने टैरिफ नीति और व्यापार सुरक्षा से जुड़े कानूनों के तकनीकी पहलुओं पर काम किया और यह तर्क भी मजबूत किया कि इन कदमों से अमेरिकी विनिर्माण उद्योग को अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सकता है। इसी वजह से उन्हें अक्सर 'टैरिफ हॉक' (कड़े टैरिफ समर्थक) भी कहा जाता है। वह अटॉर्नी और पूर्व अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट ई लाइटहाइजर को अपना मार्गदर्शक मानते हैं।

## आज का दिन

28 फरवरी,1827

बाल्टीमोर और ओहियो रेलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला सार्वजनिक वाणिज्यिक रेलमार्ग बना था, जिसने नियमित रूप से सामान और यात्रियों दोनों का परिवहन शुरू किया था।



- **1922 :** ब्रिटेन ने मिस्र को एक स्वतंत्र देश घोषित किया था।
- **1942 :** द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना जावा द्वीप पर उतरी थी।
- **1901 :** अमेरिकी वैज्ञानिक लिनस पॉलिंग का जन्म हुआ था।
- **1983 :** अमेरिकी टेलीविजन शृंखला एमएएसएच का अंतिम एपिसोड प्रसारित हुआ था।

## व्रत त्योहार



**आज :** फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी।
**कल :** प्रदोष व्रत, बसंत ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, दक्षिण गोले।
**राहुकाल :** सायं 16.30 से 18.00 तक।

## कल का पंचांग

**विक्रमी** संवत 2082, 10 फाल्गुन मास शक 1947, फाल्गुन मास 18 प्रविष्टे, 11 रमजान हिजरी 1447, फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 19.09 तक उपरांत चतुर्दशी, पुष्य नक्षत्र 08.33 तक उपरांत आश्लेषा नक्षत्र, शोभन योग 14.32 तक उपरांत अतिगंड योग, कौलव करण 07.56 तक उपरांत तैतिल करण, चंद्रमा कर्क राशि में दिन-रात।

■ सूर्योदय : 06.51
■ सूर्यास्त : 18.17
(भारतीय मानक समयानुसार)

## राशिफल

amarujala.com/astrology
■ पं. विनोद त्यागी

**मेष :** कार्यक्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। नौकरी में नए प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। अटका धन मिलेगा। व्यवसाय में लाभ होगा।

**वृष :** मनोत्साह बना रहेगा। भू-संपत्ति के कार्य अटक सकते हैं। नौकरी में स्थिति सुखद रहेगी।

**मिथुन :** मित्र सहायक रहेंगे। व्यय पर नियंत्रण रखें। नौकरी में सम्मान बना रहेगा। नई योजना सफल होगी।

**कर्क :** भावुकता पर नियंत्रण रखें। नए कार्य में पूंजी निवेश से बचें। व्यावसायिक स्थिति से मन अशांत रहेगा।

**सिंह :** मनोत्साह बना रहेगा। नौकरी में उन्नति का अवसर मिल सकता है। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें।

**कन्या :** शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय में उत्तम लाभ के अवसर मिलेंगे।

**तुला :** नौकरी में नई जिम्मेदारी आ सकती है। आर्थिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। व्यवसाय में लाभ होगा।

**वृश्चिक :** योजना में सफलता मिल सकती है। नौकरी में वरिष्ठ सहायक रहेंगे। व्यवसाय में धन लाभ होगा।

**धनु :** नए कार्य में हानि संभव है। विरोधी से दूरी बनाए रखें। व्यवसाय में असावधानी से हानि होगी। यात्रा संभव है।

**मकर :** सकारात्मक सोच बनाए रखें। नौकरी में स्थिति अनुकूल रहेगी। व्यवसाय में विस्तार हो सकता है।

**कुंभ :** मानसिक तनाव में कमी आएगी। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ सकता है। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा।

**मीन :** नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे। आय-व्यय में संतुलन बना रहेगा। व्यवसाय में लाभ होगा। यात्रा से बचें।

## जन्मदिन

**हेजल कीच, अभिनेत्री**



**आज** जन्मे जातक साहसी, दयालु एवं स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। इस वर्ष उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो सकती है। सरकारी क्षेत्र में अटके कार्य पूर्ण होंगे। विरोधी परास्त होंगे। आर्थिक दृष्टि से वर्ष अनुकूल रहेगा। रोजगारपरक परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

## सुडोकू

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | | 9 | 3 | | 4 | 1 |
| | | | | 5 | | | | |
| | | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | | 8 |
| 3 | | | 9 | | | | 7 | 4 |
| | 8 | | | | | | 9 | |
| 1 | 9 | | | | 5 | | | 3 |
| 2 | | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | | |
| | | | | 4 | | | | |
| 5 | 3 | | 8 | 6 | | 4 | | |

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 |
| 4 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 |
| 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 |
| 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 9 |

## डेली हेल्थ कैप्सूल

### कई रोगों में लाभदायक है सुपारी

*सुपारी में पाए जाने वाले पोषक शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इससे कई बीमारियों की रोकथाम होती है।*

**सुपारी** की बात आते ही सबसे पहले पान ही ध्यान में आता है, लेकिन सुपारी का सही तरीके से उपयोग करने से यह सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होती है। सुपारी में एन्थेलमिंटिक होता है, जो कैविटी को खत्म करके दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। त्वचा में होने वाली खुजली को दूर करने के लिए सुपारी का उपयोग किया जा सकता है। इसमें मौजूद औषधीय गुण मांसपेशियों के दर्द और अकड़न से निजात दिलाते हैं। सुपारी का प्रतिदिन सेवन शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक है। इससे पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो इम्युनिटी बढ़ाते हैं। सुपारी में मौजूद एनाल्जेसिक गुण सूजन या दर्द में राहत देते हैं। इसके एंटीबैक्टेरियल गुण पेट के कीड़े खत्म करने और भूख बढ़ाने का काम करते हैं। इससे ओरल हाइजिन भी अच्छी बनी रहती है। सुपारी में प्रचुर मात्रा में स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके नियमित सेवन से जल्दी थकान नहीं होती है। इसमें मौजूद अल्कालॉइड याददाश्त बढ़ाता है और दिमाग को तेज बनाता है।



**क्या कहते हैं विशेषज्ञ**

गर्भवती, दुग्धपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए सुपारी का सेवन सुरक्षित नहीं है। इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा सकता है। सेवन से पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य लें।
-डॉ. नवदीप जोशी
प्राकृतिक चिकित्सक

# Last Day To Join Private channel

I GIVE YOU MY GUARANTEE, THIS PURCHASE WILL BE WORTH IT.

## 📚Indian Newspapers:

1) Times of India
2) Hindustan Times
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) The Hindu
7) Live Mint
8) Financial Express
9) Business standard
+All Editorial PDFs

**Uploding starts from 5AM**

**🎈Access to all this In Just 19 Rupees [lifetime Validity]**

Click below to

**Join**

## 📚International Newspapers Channel

## 📚 Magazine Channel (National & International)